चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

सड़क से सियासत

सियासी दुनिया पेज 4

क्या भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है

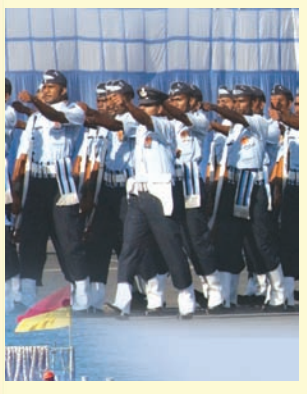

सियासी दुनिया पेज 5

दलितों की ज़मीन हड़प रहे हैं बसपा नेता

प्रशासन दुनिया पेज 6

हाफ़िज़ सईद और पाकिस्तान की मजबूरी

बाक़ी दुनिया पेज 11

मूल्य 5 रुपये | पेज 16+4 (बिहार + झारखंड) | दिल्ली, 5-11 अक्टूबर 2009

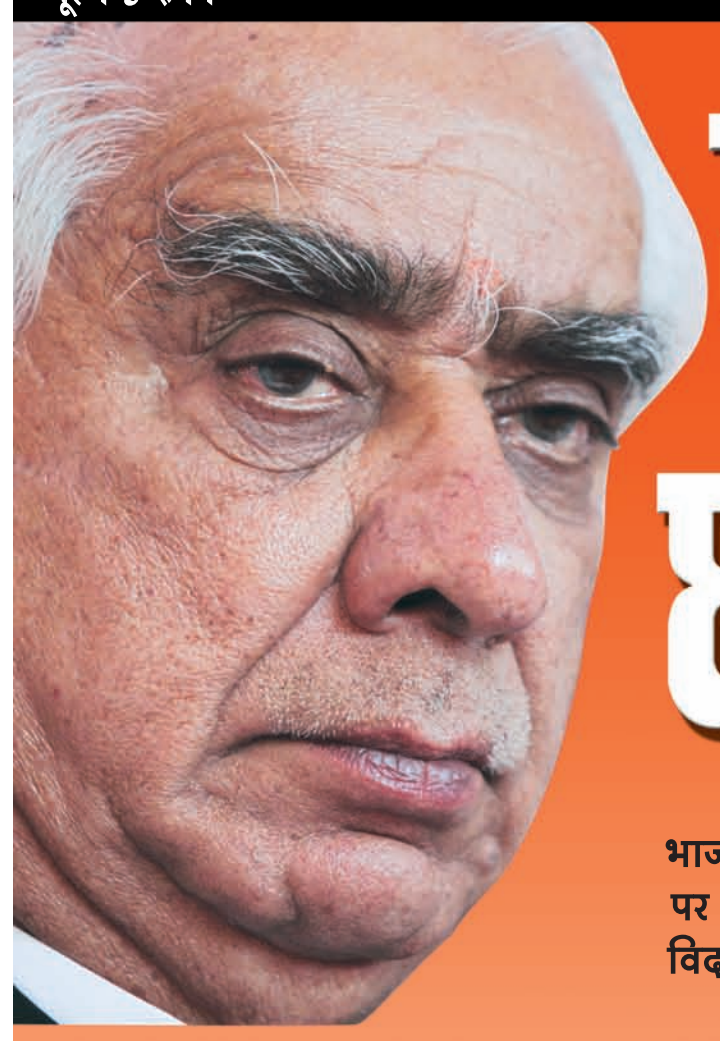

जसवंत से घबराए अनंत

भाजपा से निष्कासित जसवंत सिंह संसदीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर अभी भी बने हुए हैं. भाजपा में उनके कई पुराने साथी उनकी इस पद से भी विदाई चाहते हैं. अनंत कुमार भी. आखिर किस बात को लेकर इतने भयभीत हैं अनंत? क्या उन्हें किसी राज के उजागर हो जाने का भय सता रहा है?

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

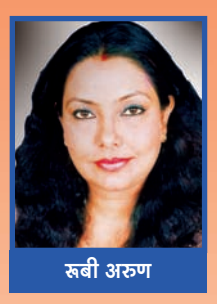

रूबी अरुण

बीजेपी नेता अनंत कुमार ऐसा क्यों चाहते हैं कि बीजेपी से निकाले गए नेता जसवंत सिंह, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे दें? क्यों वे बीजेपी नेतृत्व पर इस बात का दबाव बना रहे हैं? आख़िर अनंत कुमार को किस बात का डर सता रहा है? कहीं उन्हें इस बात का अंदेशा तो नहीं कि जसवंत सिंह उनका कच्चा चिट्ठा सरेआम न कर दें. सर्वशिक्षा अभियान से जुड़ी भारत सरकार की बेहद अहम योजना मिड डे मील को देश के छह राज्यों में संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संस्था इस्कॉन के एनजीओ अक्षयपात्र से उनका क्या नाता है? इस्कॉन के बंगलुरु के प्रभारी मधु पंडित दास से अनंत कुमार के प्रगाढ़ रिश्तों की कहानी क्या है? अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी द्वारा संचालित एनजीओ अदम्य चेतना के बेहद तेज़ी से प्रचार-प्रसार का राज़ क्या है? इसका ख़ुलासा न हो जाए? मिड डे मील के बहाने किस क़दर परिवार कल्याण किया जा रहा है, इस बाबत जनता को पता न चल जाए. यानी कि पहले इस्कॉन बंगलुरु की संस्था अक्षयपात्र और फिर पारिवारिक संस्था अदम्य चेतना के लिए अपने राजनीतिक रसूख़ का इस्तेमाल. दरअसल, सच यही है. अनंत कुमार इन दिनों इसी जद्दोज़ेहद में हैं कि बस किसी भी तरह जसवंत सिंह पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दें ताकि उनका रहस्य बरक़रार रह सके. पर जसवंत हैं कि इस्तीफ़ा देने का नाम नहीं ले रहे. वे अड़े हुए हैं. जसवंत के इस रुख़ ने न सिर्फ़ अनंत कुमार बल्कि कई दिग्गज़ भाजपा नेताओं की नींद उड़ा रखी है. जसवंत सिंह पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का पद छोड़ दें, इस ख़ातिर लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरूण जेटली सरीख़े नेता सारी ज़ोर-आज़माइश कर चुके. पर जसवंत सिंह वैधानिक तौर पर इस पद पर क़ाबिज़ हैं, लिहाज़ा उन पर कोई ज़ोर नहीं चल पा रहा. चूंकि जसवंत सिंह को ये सारे क़िस्से पता हैं तो उनसे घबराहट होना तो लाज़िमी है. लेकिन फ़िलहाल जसवंत सिंह अपना बड़प्पन दिखाने के मूड में हैं. उन्होंने इस मसले पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है. अपनी ज़ुबान खोलने के लिए शायद उन्हें सही वक़्त का इंतज़ार है. हालांकि, एक वो वक़्त भी था जब अनंत कुमार, जसवंत सिंह को बाइज़्ज़त ले गए थे अपनी संस्था का निरीक्षण कराने. जसवंत को संस्था के कामकाज़ में कुछ ख़ामियां भी नज़र आई थीं. उन्होंने अनंत कुमार और उनकी पत्नी को बेहतर कामकाज़ के कुछ सुझाव भी दिए थे. ज़ाहिर है, अनंत कुमार ने उस सलाह पर अमल करना मुनासिब नहीं समझा.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जसवंत सिंह पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का पद छोड़ दें, इसकी ख़ातिर लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सरीख़े नेता सारी ज़ोर आज़माइश कर चुके हैं.

मिड डे मील के बहाने इस्कॉन का घोटाला

मिड डे मील के नाम पर इस्कॉन विदेशों में व्यवसायिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर ज़बरदस्त तरीक़े से चंदा उगाही कर रहा है. इसके लिए इस्कॉन भारत की ग़रीबी और भुखमरी को ज़रिया बना रहा है. इस्कॉन के प्रतिनिधि विश्व भर के लोगों को यह समझाने में जुटे हैं कि भारत में लोग भूख से मर रहे हैं. अनाज की कमी ने भारत में तबाही मचा रखी है. यहां की सरकार इतनी नाकारा है कि इन मुश्किलों से वह निबट ही नहीं सकती. अगर विश्व के अन्य देशों ने इस काम में इस्कॉन की मदद नहीं की तो हालात बेक़ाबू हो जाएंगे. कर्नाटक की भाजपा सरकार बंगलुरु के इस्कॉन मंदिर के इस कारनामे से भलीभांति वाक़िफ़ हैं. पर बजाय इस्कॉन पर कोई लगाम लगाने के कर्नाटक की भाजपा सरकार उसे खुलकर शह दे रही है. यही वजह है प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी ने इस्कॉन की इस हरकत के विरोध में ख़ूब धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा में सवाल उठाए गए, जमकर हंगामा हुआ. पर कर्नाटक की भाजपा सरकार कान मे तेल डाले सोई रही. राज्य सरकार से निराश कांग्रेस अब इस्कॉन के इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है.

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार साफ़तौर पर आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन बंगलुरु को भाजपा सरकार का वरदहस्त है. भाजपा के बड़े-बड़े नेता इस्कॉन बंगलुरु के अध्यक्ष मधु पंडित दास की सेवा में हाज़िर रहते हैं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक विजय चव्हान के अनुसार, एमटीडीसी ने मुंबई में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक महीने का सघन अभियान चलाया.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

रॉ में ठनी तकरार

देश की प्रतिष्ठित ख़ुफ़िया संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग– रॉ– इस बार ग़लत कारणों से चर्चा में है. एक जूनियर आईपीएस अधिकारी की पदोन्नति को लेकर सात अतिरिक्त सचिव नाराज़ हैं. उन्हें लगता है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है. रॉ के आंतरिक संगठन रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार उनका प्रमोशन पहले होना चाहिए था. जासूसी संस्था के मुख्यालय में चल रही सुगबुगाहटों को देखकर लगता है कि सभी नाराज़ सचिव विरोध प्रदर्शन के लिए छुट्टी पर जा सकते हैं.

दरअसल, समस्या तब शुरू हुई जब सरकार ने मणिपुर के 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी ए बी माथुर को विशेष महानिदेशक के तौर पर पदोन्नत किया और रॉ में विशेष सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की. सूत्रों के अनुसार, पदोन्नति पाकर माथुर वर्तमान रॉ प्रमुख के सी वर्मा के कार्यकाल की समाप्ति के बाद रॉ प्रमुख बनने वालों की कतार में शामिल हो गए. यह संयोग की ही बात है कि वर्मा ख़ुद एक आईपीएस अधिकारी हैं और क़रीब तीन दशक तक इंटेलीजेंस ब्यूरो में रहे हैं न कि रॉ में. उस समय उन्हें रिसर्च एंड एनालाइसिस सर्विस के पी वी कुमार के वरीयता की अनदेखी करते हुए उन्हें उस पद की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी. स्वाभाविक है, सातों नाराज़ सचिवों ने अपने बॉस वर्मा व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को अपनी नाराज़गी से अवगत करा दिया. अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि माथुर का ओहदा इसलिए बढ़ाया गया, क्योंकि

उनके साथ काम कर रहे कुछ जूनियर आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था. लेकिन यह सफ़ाई, दरकिनार कर दिए गए लोगों को हज़म नहीं हो पाई.

रॉ ने इस विद्रोह को उनके साथ हुआ अन्याय मानते हुए भूल सुधार करने के प्रति अपनी सहमति जता दी. कैबिनेट सचिव ने इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने की धमकी के मद्देनज़र विभागीय प्रोन्नति समिति के सम्मुख भेज दिया.

फाइल की सुस्त चाल में फंसा पर्यटन

जहां एक ओर कई राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रहे हैं, वहीं पर्यटन मंत्रालय इस बात से चिंतित है कि कई राज्य बुनियादी पर्यटन परियोजना के कार्यान्वयन में अड़ंगे लगा रहा है.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक विजय चव्हान के अनुसार, एमटीडीसी ने मुंबई में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक महीने का सघन अभियान चलाया था. गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के पर्यटन विभाग के बाबू भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाने में व्यस्त हैं. लेकिन दिल्ली पर्यटन मंत्रालय का अपना दूसरा ही ऐजेंडा है. पर्यटन सचिव सुजीत बनर्जी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्र द्वारा दी गई धनराशि पर चल रही पर्यटन परियोजनाओं के सुस्त चाल के बारे में पत्र लिखा है.

कई मुख्य योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए बनर्जी और दूसरे बाबुओं ने चेतावनी दी है कि मंत्रालय राज्यों के उन पर्यटन परियोजनाओं को समाप्त कर देगा जिसके लिए ज़मीन का आवंटन और धनराशि उपलब्ध कराते हुए एक साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हो पाई है. साफ़ शब्दों में दी गई इस चेतावनी का इन बाबुओं पर क्या असर पड़ता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

मिड डे मील के बहाने इस्कॉन का घोटाला

पृष्ठ 1 का शेष

ये अनंत कुमार सरीख़े भाजपा के नेता ही हैं जिनकी बदौलत इस्कॉन देश के छह राज्यों में मिड डे मील योजना पर क़ब्ज़ा कर बैठा है और सरकार द्वारा मिड डे मील योजना मद में जारी सहायता राशि का पूरी तरह बेजा इस्तेमाल कर रहा है. सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि इस्कॉन अपनी झोली भरने के लिए ग़लत तरीक़े भी अख्तियार कर रहा है. वह विश्व भर में भारत की ग़रीबी और भुखमरी की नुमाईश कर रहा है. भारत के ग़रीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर दुनिया भर से चंदे के रूप में पैसे वसूल रहा है. बग़ैर इस बात का ज़िक्र किए कि मिड डे मील के लिए भारत सरकार भी पूरी सहायता राशि उपलब्ध करा रही है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी इन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही गड़बड़ियों का साफ़तौर पर ज़िक्र है.

शिवकुमार बताते हैं कि इस्कॉन विश्व भर से भारत में चल रही इस परियोजना के नाम पर 55 से 60 लाख रुपए की उगाही हर महीने कर रहा है. फ़िलहाल अक्षयपात्र लगभग दस लाख बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन उपलब्ध करा रहा है. इस्कॉन प्रति बच्चे के नाम पर छह रुपए बतौर डोनेशन वसूलता है. मतलब ये कि सालाना वसूली की कुल राशि 117 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है. शिव कुमार कहते हैं कि यह पूरी राशि बंगलुरु के इस्कॉन के अध्यक्ष मधु पंडित दास की जेब में जाती है. अक्षयपात्र की शुरुआत भी मधु पंडित ने अपने सहयोगी और बंगलुरु इस्कॉन के उपाध्यक्ष चुचलपथी दास के साथ की थी. ये दोनों अक्षयपात्र के आजीवन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बन गए. मिड डे मील के नाम पर भारत सरकार से जो अनाज अक्षयपात्र को मिलता है वह काले बाज़ार में बेच दिया जाता है. वेबसाइट, डोनेशन फॉर्म, प्रोमोशनल लिटरेचर के मार्फ़त फंड इकट्ठा किया जाता है. जिन देशों से वह भारत की ग़रीबी हटाने के नाम पर सहायता मांगता है, उनसे इस बात की चर्चा तक नहीं करता कि भारत सरकार इस परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर अनुदान जारी करती है. इस क्षेत्र में काम करने वाली अन्य जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं उनमें से किसी ने भी इस तरह चंदा उगाही करने की ख़ातिर अपने प्रतिनिधियों को नहीं रखा है. सरकार जो पैसा देती है वह मिड डे मील योजना के परिचालन के लिए पर्याप्त है. फिर क्यों हर जगह होर्डिंग और बैनर लगा कर इस्कॉन ग़रीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए मदद की अपील करता है. सरकार इस मद में जितना अनाज आवंटित करती है उससे सैकड़ों टन ज़्यादा अनाज की मांग सरकार से क्यों करता है? जबकि इस काम में लगे दूसरे एनजीओ कहते हैं कि सरकार द्वारा दिया गया अनाज इतना ज़्यादा होता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा बच जाता है. जिसे स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार को वापस कर देती हैं. दिसंबर 2007 में बंगलुरु इस्कॉन मंदिर के गेट पर कालाबाज़ारी के लिए जा रहा ट्रक पकड़ा भी गया था. इस्कॉन की इस धांधली के ख़िलाफ़ प्रदेश कांग्रेस ने पिछले दिनों ज़ोरदार अभियान भी चलाया था, जिसके तहत राज्य व्यापी धरना–प्रदर्शन किया गया. शिवकुमार बताते हैं कि बंगलुरु शहर का हर आदमी जानता है कि मधु पंडित मिड डे मील के नाम पर जमा की गई राशि को रियल एस्टेट के धंधे में निवेश करते हैं.

इस्कॉन बंगलुरु में 35 एकड़ निजी भूमि पर आवासीय और व्यवसायिक इमारतें बना रहा है. जबकि सरकार द्वारा आवंटित 28 एकड़ ज़मीन पर महत्वाकांक्षी कृष्ण लीला पार्क बना रहा है. हालांकि, मधु पंडित दास शिवकुमार पर उल्टा आरोप लगाते हैं कि उनकी निगाह निजी ज़मीन पर थी. जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने इस्कॉन पर ग़लत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए. मधु पंडित दास कहते हैं कि उन्होंने ज़मीन की पूरी क़ीमत सरकार को दी है. निजी ज़मीन को एक करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ख़रीदा है. शिवकुमार इस बात को मानते हैं कि वे बिल्डर भी हैं . वे कहते हैं कि एक राजनीतिज्ञ का बिल्डर होना ग़लत नहीं है, पर एक धार्मिक संस्था के फ़ायदे के लिए इमारत बना कर बेचना गुनाह है.

बहरहाल, इस्कॉन भारतीय बच्चों का पेट भरने के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है, उसकी जांच होनी निहायत ज़रूरी है. बंगलुरु इस्कॉन गुनाह कर रहा है या नहीं पर वह अपनी जेब भरने के लिए विश्व भर में हमारे देश को शर्मिंदा ज़रूर कर रहा है.

जसवंत से घबराए अनंत

पृष्ठ 1 का शेष

अगर जसवंत की सलाह उनके लिए अहमियत रखती तो अदम्य चेतना के जोधपुर स्थित किचन में जानलेवा लापरवाही नहीं बरती जाती. तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार और मिड डे मील घोटाले में भी कोई रिश्ता है? मिड डे मील के तहत बच्चों को जो सड़ा–गला खाना मिल रहा है, क्या इसमें अनंत कुमार की भी भूमिका है? क्या अनंत कुमार देश के ग़रीब बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या भाजपा का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता महज़ अपने फ़ायदे के लिए समाजसेवा की आड़ में इतना बड़ा गुनाह कर सकता है? अनंत कुमार देश की एक नामचीन स्वयंसेवी संस्था अदम्य चेतना के मुख्य संरक्षक हैं. उनकी पत्नी तेजस्विनी अनंत कुमार अदम्य चेतना की लाइफ़ टाइम ट्रस्टी हैं. अदम्य चेतना मिड डे मील के तहत बंगलुरु, हुबली, गुलबर्गा और जोधपुर के हज़ारों स्कूलों के लाखों बच्चों को दोपहर का खाना खिलाती है. संस्था का यह दावा है कि वह अपने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रसोई में बेहद साफ़–सफ़ाई के साथ तैयार लजीज़ खाना स्कूली बच्चों को परोसती है. बच्चों को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए हर दिन खाने का अलग मेन्यू तय किया गया है. पर सच्चाई इससे कहीं अलग है. पिछले दिनों संस्था के जोधपुर स्थित सेंट्रल किचन के नागौर रोड के निजी गोदाम में जब ज़िला रसद अधिकारी विजय पाल सिंह और सीएमएचओ गोपाल चौधरी ने छापा मारा तो वे यह देख कर हैरान रह गए कि वहां तीन हज़ार चालीस प्लास्टिक के कट्टों के बीच रखे 540 कट्टों में रखा गेहूं बिल्कुल ही सड़ा–गला था. कुछ कट्टों में सिर्फ़ धूल और मिट्टी भरी थी, तो कुछ में बदबूदार दलिया रखा हुआ था. स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर मूलचंद व्यास ने बताया कि अगर इस गेहूं से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को परोस दिए जाते तो किसी भी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता था.

अदम्य चेतना संस्था के प्रतिनिधियों के मुताबिक़ इसमें उनकी कोई ग़लती नहीं हैं. यह राजस्थान फूड कॉरपोरेशन (आरएफसी) की ख़ामी है, जो गेहूं की आपूर्ति करती है. पहले भी ऐसे गेहूं की आपूर्ति हुई है जिसे वे लोग लौटा चुके हैं. पर इतना कह देने से क्या अदम्य चेतना के प्रतिनिधि अपनी ज़िम्मेदारियों से बच जाएंगे? अगर पहले भी सड़े–गले गेहूं की सप्लाई हुई है तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बात की ख़बर क्यों नहीं दी? अगर उनकी नीयत सही थी तो उन्होंने अपनी शिकायत पहले ही दर्ज़ क्यों नहीं कराई? अगर संस्था वालों ने पहले ख़राब गेहूं को लौटा दिया था तो मिड–डे मील के नाम पर स्कूलों में बच्चों के सामने क्या परोसा? सवाल बहुतेरे हैं. ज़ाहिर है, संस्था का कामकाज़ शक़ के दायरे में है. और उसका स्तरहीन कामकाज़ सीएजी (कैग) की निगाह में भी है. कैग ने इस बाबत अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणी भी की है. कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार आरोप लगाते हैं कि अनंत कुमार की तथाकथित स्वयंसेवी संस्था अदम्य चेतना भी इस्कॉन की ही राह चल रही है. लोकसभा चुनावों के दरम्यान भी अनंत कुमार की समाज सेवा पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने कई सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि मिड डे मील योजना है तो राज्य सरकार का कार्यक्रम, पर इसके ज़रिए बीजेपी स्टेट प्रेसीडेंट अनंत कुमार अपने राजनीतिक मक़सद को पूरा कर रहे हैं. वे अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं.

बहरहाल, इसके पीछे की जो कहानी सामने आई है वो ये कि सन् 1998 में जब अनंत कुमार एनडीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब उन्होंने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक में मिड डे मील को राज्य में लागू कराने का काम अपनी स्वयंसेवी संस्था अदम्य चेतना को दिला दिया. अदम्य चेतना की स्थापना 1997 में की गई थी. इस संस्था के संरक्षक अनंत कुमार हैं. जबकि इसका संचालन उनकी पत्नी तेजस्विनी अनंत कुमार करती हैं. संस्था ने अपने कामकाज़ की शुरुआत बंगलुरु से की, पर धीरे–धीरे इसने पूरे राज्य में अपना साम्राज्य फैला लिया. देश में उनकी सरकार थी और अनंत कुमार दिग्गज नेताओं में शुमार होते थे. फिर वे पर्यटन, खेल और युवा मामलों के मंत्री भी बने. ज़ाहिर है, सरकारी तंत्र पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी, जिसका अनंत कुमार ने जमकर फ़ायदा उठाया और अपनी स्वयंसेवी संस्था अदम्य चेतना का प्रसार अन्य राज्यों में भी कर लिया. राजस्थान में जब भाजपा की सरकार बनी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनीं तो जोधपुर में राजकीय समारोह की तरह अदम्य चेतना के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ और स्वयं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अनंत कुमार, उनकी पत्नी तेजस्विनी और उनकी संस्था का महिमा मंडन करते हुए इसका उद्घाटन किया और इस क्षण के अज़ीम गवाह बने मान्यवर लालकृष्ण आडवाणी. वैसे लालकृष्ण आडवाणी की छत्रछाया अनंत कुमार की संस्था पर हमेशा से बनी रही है. कर्नाटक में भाजपा की सरकार अदम्य चेतना को भरपूर सरकारी सहयोग उपलब्ध कराती है. राजस्थान की वसुंधरा सरकार भी अदम्य चेतना के राजस्थान में फलने–फूलने में सहभागी रही. जब तक वसुंधरा राजे गद्दी पर रहीं, तब तक अदम्य चेतना का कामकाज़ धड़ल्ले से चलता रहा. अनंत कुमार की संस्था मिड डे मील के नाम पर बच्चों को पौष्टिक खाना परोस रही है या कीड़े–मकोड़ों भरा भोजन. शिकायतें मिलने के बावजूद किसी ने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी. पर जब महारानी का शासन गया और कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्हीं शिकायतों के आधार पर छापेमारी कर इस घोटाले का ख़ुलासा किया गया.

ruby@chauthiduniya.com

अदम्य चेतना संस्था के प्रतिनिधियों के मुताबिक़ इसमें उनकी कोई ग़लती नहीं हैं. यह राजस्थान फूड कॉरपोरेशन (आरएफसी) की ख़ामी है जो गेहूं की आपूर्ति करती है. पहले भी ऐसे गेहूं की आपूर्ति हुई है जिसे वे लोग लौटा चुके हैं. पर इतना कह देने से क्या अदम्य चेतना के प्रतिनिधि अपनी ज़िम्मेदारियों से बच जाएंगे? अगर पहले भी सड़े-गले गेहूं की सप्लाई हुई है तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बात की ख़बर क्यों नहीं दी?

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 1 अंक 30, 5 अक्टूबर–11 अक्टूबर 2009

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001

फोन न.
संपादकीय 011–47149999
विज्ञापन + 011 47149905
प्रसाद + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

अंक 28, 29, 30 संयुक्तांक

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनर्प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

गुटबाजी से त्रस्त मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उप चुनाव में जमकर आत्मघाती खेल खेला. एक दूसरे को नीचा दिखाने में दोनों ही सीटें उनके हाथ से निकल गईं.

पचौरी पर भारी पड़ेगी तेंदूखेड़ा की हार

संध्या पाण्डे

राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के लाख सिर पटकने पर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस गुटबाज़ी से बाहर निकलकर पार्टी हित के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं है. अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए विधानसभा चुनाव हार जाने वाले दिग्गजों ने एक बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस को नीचा दिखा दिया. सूबे में दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में एक सीट भाजपा के पक्ष में गई है.

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को दोबारा जीवित किए जाने की कोशिशों को मध्य प्रदेश में एक बार फिर धक्का लगा है. इस बार हुए उपचुनाव में कोई भी सीट कांग्रेस की प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ी गई. तेंदूखेड़ा की सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट थी, तो गोहद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर थी. दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा. तेंदूखेड़ा की सीट सुरेश पचौरी के व्यक्तिगत कोटे में थी, जहां उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को अपनी जीत मान लिया था. यह सीट कांग्रेस हार गई. कांग्रेसी नेता दबी ज़ुबान में इसे हाईकमान की निगाह में पचौरी को नीचा दिखाने का षड्यंत्र मानते हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों चर्चा थी कि पचौरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बनाया जा रहा है. ख़बर यह भी थी कि कांग्रेस का एक खेमा पचौरी को दिग्विजय सिंह पर नियंत्रण के लिए दिल्ली ले जाने पर आमादा है. संभवत: तेंदूखेड़ा की पराजय इसी ख़बर की परिणति थी. पचौरी आज भी अपने पांच समर्थकों की सीमा से निकलकर प्रदेश स्तरीय नेता के रूप में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं. यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नए अध्यक्ष की तलाश करनी पड़ रही है. कांग्रेस इस पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की पसंद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के विधायक पुत्र अजय राहुल सिंह को मानती है. उपरोक्त चयन से एक बार फिर स्पष्ट होने जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बड़े नेताओं की छत्रछाया से मुक्त होकर अभी राहुल गांधी की कांग्रेस बनने के लिए तैयार नहीं है. दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे जिन्ना संकट से गुज़रती हुई भाजपा के लिए तेंदूखेड़ा सीट की जीत महत्वपूर्ण है. इस सीट पर भाजपा को सहानुभूति के वोटों का अधिक लाभ मिला है. भाजपा स्वयं इस

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

हाल में हुए उपचुनाव के परिणाम तो एक बहाना हैं. असल वजह यह है कि हाईकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदरखाने में पिछले कुछ समय से चल रही आपसी खींचतान से हैरान-परेशान है. इसीलिए वह सूबे में पार्टी का मुखिया बनाने के लिए एक ताज़ा चेहरा तलाश रही है. आख़िर कौन होगा नया सरताज और किस पर गिरेगी गाज?

राष्ट्रीय आपदा के समय स्वयं को संगठित रखने की कोशिश कर रही है. यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय को छोड़कर राज्य के किसी भी बड़े या छोटे नेता ने जिन्ना विवाद पर भाजपा हाईकमान के पक्ष में भी खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई. भाजपा का प्रदेश नेतृत्व पानी में डोलते हुए पत्ते की चाल का परीक्षण करना चाहता है, जिससे दीर्घकाल तक प्रदेश के नेता अपने राजनीतिक हितों का राष्ट्रीय राजनीति में संरक्षण कर सकें. इन परिस्थितियों में भाजपा को यह उम्मीद कतई नहीं थी कि उसे उपचुनाव के दौरान कोई सफलता मिलने वाली है. गोहद सीट पर मिली पराजय को भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के आभामंडल की जीत के रूप में स्वीकार कर रही है, वहीं तेंदूखेड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक बार फिर पटखनी देकर भाजपा ने नेतृत्वविहीन कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर कर दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

भू-माफ़िया बने जान के दुश्मन

भोपाल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम जी रूसिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से एक बार फिर सूबे के लोग चिंतित हैं, लेकिन क्या इस हादसे के रहस्य से पर्दा उठाएगी सरकार?

राजधानी भोपाल में भू-माफ़िया पहली बार प्रभावशाली हस्तियों की हत्या या आत्महत्या का कारण बनते जा रहे हैं. भोपाल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम जी रूसिया की मौत मध्य प्रदेश में भू-माफ़ियाओं के बढ़ते आतंक और उन्हें हासिल संरक्षण की एक अबूझ पहेली है. पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है, परंतु परिणामों के प्रति कोई भी आश्वस्त नहीं है. राजधानी के भू-माफ़िया अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अब आतंक का सहारा लेने लगे हैं. चिंता का विषय यह है कि भू-माफ़ियाओं के इस तंत्र में जनप्रतिनिधि, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और कई पत्रकार भी शामिल हैं. राज्य शासन की भूमि संबंधी नीतियों में कथित रूप से लचीलापन इन भू-माफ़ियाओं को संरक्षण देने के लिए पर्याप्त है. पिछले दिनों भोपाल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूसिया भोपाल के विधायक जितेंद्र सिंह डागा के साथ एक ट्रेन में सफ़र करते हुए अचानक लापता हो गए. रूसिया का शव आगरा से 40 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी के किनारे पड़ा हुआ मिला. इस घटना ने जितेंद्र सिंह डागा को प्रथम दृष्ट्या मुलजिम बना दिया.

बताते हैं कि विधायक डागा रूसिया को अपने साथ ज़मीन संबंधी चर्चा के लिए दिल्ली ले गए थे. रूसिया प्रकरण की जांच का आश्वासन मुख्यमंत्री ने उनके अंतिम संस्कार के समय दिया है. उधर कांग्रेस ने भी विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए घटना की सीबीआई जांच की मांग कर डाली. जानकारों का कहना है कि भू-माफ़ियाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में ग़रीब आदिवासियों की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर उसे बेचने की प्रक्रिया निरंतर जारी है. इस भू-माफ़िया तंत्र के साथ कई सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार एवं भूतपूर्व राजनेताओं के परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं.

भोपाल की बावड़ियांकलां स्थित ज़मीन, जो कई राजनेताओं के प्रभुत्व में है, को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी. रूसिया स्वयं अपने कार्यकाल के दौरान कभी ईमानदार अधिकारियों की श्रेणी में नहीं शामिल किए जा सके. भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के लगभग सभी स्थानीय नेताओं ने बावड़ियांकलां की ज़मीन से चांदी काटने के लिए एक बड़ी रक़म इस क्षेत्र में ख़र्च कर रखी है. भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की सांठगांठ इन भू-माफ़ियाओं के साथ इस हद तक है कि सरकार ने अपनी कोई आवासीय योजना पिछले पांच सालों के दौरान राजधानी में घोषित ही नहीं की. परिणामस्वरूप, राजधानी में भूमि के दाम आसमान छू रहे हैं. बावड़ियांकलां की जिस ज़मीन को लेकर रूसिया की हत्या की गई, बताया जाता है कि उसकी वर्तमान क़ीमत कई सौ करोड़ रुपये आंकी जाती है. एम जी रूसिया की हत्या के षड्यंत्र का पर्दाफ़ाश करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में व्यापक छानबीन कर रही है. घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर रूसिया द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात गले नहीं उतर रही है. प्रथम दृष्ट्या यह दुर्घटना नहीं, जानबूझ कर की गई वारदात ही मानी जा रही है. प्रदेश शासन ने घटना की सीबीआई जांच के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की है.

संध्या पाण्डे
feedback@chauthiduniya.com

योजना लाख कल्याणकारी हो, लेकिन उसे अमलीजामा पहनाने वाला तंत्र अगर निकम्मा है तो वह कभी भी अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सकती.

चौथी दुनिया

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

सड़क से सियासत

हार से नहीं टूटा हौसला

हार ने न तो रामविलास पासवान के हौसले को तोड़ा है, न ही उनके इरादों को बदला है. हां, ज़िंदगी जीने का अंदाज़ ज़रूर बदल गया है. अब न तो सरकार में हिस्सेदारी रही, न ही सांसद का ताज़. तेज़ रफ़्तार सियासी ज़िंदगी में अचानक एक ठहराव-सा आ गया है. पर यह तब्दीली रामविलास पासवान को रास आ रही है. वे कहते हैं कि सत्ता से बाहर होने के बाद अब अपने सामाजिक राजनीतिक मक़सद और मसलों को ज़्यादा तरज़ीह दे पा रहे हैं. लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद आम तौर पर यह माना जाने लगा है कि वे राष्ट्रीय राजनीति के हासिए पर चले गए हैं. या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें अब वो अहमियत नहीं मिल रही, जो एक वज़ीर के तौर पर उन्हें मिलती आ रही थी. पर रामविलास पासवान ऐसा नहीं मानते कि राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर उनकी चमक धीमी पड़ गई है. वे मानते हैं कि आज भी वे हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों और ग़रीबों के सर्वमान्य नेता हैं. हार ने उन्हें सत्ता से बाहर ज़रूर कर दिया है, पर उनके ख़्यालातों की तपिश कम नहीं कर सकी है. वे कहते हैं कि सामाजिक बदलावों का बुनियादी सपना लेकर चलने वाला नेता चुनावों में हारता है तो ये शिकस्त उसकी नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों की होती है. मुद्दे कमज़ोर होते हैं. उन सिद्धांतों को मानने वालों को झटका लगता है. इसलिए, अगर वो हारे हैं तो ये पराजय सिर्फ़ उनकी नहीं है, बल्कि उन सबकी है जो उनके उसूलों में यक़ीन करते हैं.

फिर भी रामविलास जी, अपना कोई तो क़दम आपको राजनीतिक चूक लगता होगा जिसकी वजह से आज आपका क़द छोटा हुआ है?

कुर्सी पर पहलू बदलते हुए रामविलास पासवान इस बात को बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं. कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं है. कई क्षण बेहद दुविधा के होते हैं. जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता. तब आपको अपनी राह ख़ुद बनानी होती है. लोकसभा चुनावों के समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उस समय यह मुग़ालता तक नहीं था कि कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ सकता है. एनडीए में जाने का सवाल ही नहीं था. तो एक ही रास्ता था कि हम अलग होकर चुनाव लड़ें. हालांकि ये हमारा दुर्भाग्य था.

पर, रामविलास जी तसल्ली के लिए चाहे हम कोई भी तर्क दे दें. पर इससे तो इंकार नहीं ही कर सकते कि इस चुनाव में जनता के नकारने के बाद आप राष्ट्रीय नेता से क्षेत्रीय नेता बन गए?

बड़ी ही आत्मीय मुस्कान उभरती है रामविलास पासवान के चेहरे पर. बेफ़िक्री ज़ाहिर करते हुए फ़रमाते हैं कि हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हम सांसद बनें, केंद्रीय मंत्री बनें या देश पर राज करें. ये तो बिहार की जनता का भरोसा था हममें. कारवां बनता गया. हार को सब कुछ ख़त्म हो जाने के नज़रिए से क्यों देखते हैं आप लोग? ये भी तो सोचिए कि अब मेरे पास वक़्त है उन तमाम मसलों पर काम करने का जिन पर मंत्री रहते मैं ग़ौर नहीं कर पाया था. अब माथे पर बोझ कम है तो मुद्दों की लड़ाई भी धारदार होगी. रही बात नुक़सान की, तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई नुक़सान हुआ है. फिर ठठा कर हंसते हुए कहते हैं कि बस फ़र्क़ ये पड़ा कि जो तनख्वाह 50,000 रुपए मिलती थी, अब वो पेंशन के रूप में 25,000 रूपये मिल रही है. पावर था तो वो भी ग़रीबों के लिए ही था. एक हथियार के तौर पर. हम नहीं मानते कि सामाजिक या राजनीतिक तौर पर हमारी स्थिति में कोई ज़्यादा बदलाव आया है. पहले संसद के ज़रिए लड़ते थे, अब सड़क से लड़ेंगे.

> **“बड़ी ही आत्मीय मुस्कान उभरती है रामविलास पासवान के चेहरे पर. बेफ़िक्री ज़ाहिर करते हुए फ़रमाते हैं कि हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हम सांसद बनें, केंद्रीय मंत्री बनें या देश पर राज करें. ये तो बिहार की जनता का भरोसा था हममें. कारवां बनता गया.”**

लेकिन, मौज़ूदा हालातों में राजद के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ आपकी लड़ाई क्या रंग लाएगी? बिहार की जनता कैसे भरोसा करे, आप दोनों के तालमेल पर?

तपाक से जवाब मिलता है रामविलास पासवान का- उप चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता भरोसा करने लगी है. लोगों का यक़ीन वापस राजद और लोजपा में लौट चुका है. अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे. वो यक़ीनन हमारे हक़ में होंगे. लोकसभा चुनाव के समय हमारा अचानक तालमेल लोगों को परिपक्व नहीं लगा था. पर बीतते समय के साथ यह मिलन पुख्ता हो चुका है. इस उप चुनाव में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है. जीत ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया है. नीतीश कुमार के विकास पुरुष होने की कलई भी अब खुल चुकी है. जनता के तेवर उनके ख़िलाफ़ आक्रामक हो रहे हैं. अपने तात्कालिक लाभ के लिए नीतीश कुमार जिस तरह अलग-अलग आयोग बना कर समाज को बांट रहे हैं. इससे सभी जात-जमात में उनके ख़िलाफ़ रोष फैल रहा है. यहां तक की उनकी अपनी पार्टी जद यू में दरार पड़ रही है. उनकी सरकार में सहयोगी पार्टी भाजपा के नेता भी उनके रवैए से बेहद ख़फ़ा हैं. मुख्यमंत्री का जनता से संपर्क टूट चुका है. राज्य में अफ़सरशाही पूरी तरह से हावी है. जनप्रतिनिधियों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है. नीतीश कुमार का जनता दरबार का ढकोसला भी असरहीन हो चुका है. सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार पर धारा 302 का मुक़दमा दर्ज़ होता है. सरेआम औरत को नंगा कर घुमाया जाता है. ज़ाहिर है ऐसे मुख्यमंत्री पर बिहार की जनता दोबारा भरोसा किसी हाल में नहीं करेगी.

रूबी अरूण
ruby@chauthiduniya.com

नरेगा-कहीं ठंडापन तो कहीं बंदरबांट

सुरेंद्र अग्निहोत्री

योजना लाख कल्याणकारी हो, लेकिन उसे अमलीजामा पहनाने वाला तंत्र अगर निकम्मा है तो वह कभी भी अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सकती. नरेगा के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में. कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (नरेगा) के क्रियान्वयन में छेद ही छेद नज़र आए हैं. 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना का क्रियान्वयन ही उत्तर प्रदेश में दोषपूर्ण था. ग़रीब परिवारों को गारंटीशुदा काम नहीं दिया गया, मज़दूरी का फ़र्ज़ी भुगतान हुआ तथा भुगतान में विलंब किया गया. योजना के अनुमोदन में ही 6 से 11 महीने का विलंब किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यों का क्रियान्वयन प्राथमिकता सूची के अनुसार नहीं किया गया. मास्टर रोल में ऐसे लोगों को मज़दूरी का भुगतान किया गया, जो ग्रामसभाओं के अस्तित्व में नहीं थे. भू स्थितियों के अनुरूप ज़िला अनुसूची की दरें नहीं तैयार की गई. पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान के प्रावधान के बावजूद 1.21 करोड़ रुपये का भुगतान नौ महीने बाद किया गया. ज़िला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया तथा 49 प्रतिशत कामों के अनुश्रवण हेतु समिति का गठन ही नहीं किया गया. 9 ज़िलों के 36 विकासखंडों व 144 ग्राम पंचायतों का औचक तरीक़े (रैंडम) से लेखा परीक्षण किया गया. वर्ष 2006 में इस योजना के तहत काम के बदले अनाज योजना लागू थी, किंतु उसमें भी 85 करोड़ रुपये की धनराशि ख़र्च ही नहीं की गई. इसी प्रकार मार्च 2007 में 7.34 करोड़ रुपये बच गए. इससे हमीरपुर, फतेहपुर, गोंडा, उन्नाव, चंदौली व लखीमपुर खीरी प्रभावित हुए.

प्रदीप जैन

दद्दू प्रसाद

गुसाईगंज ब्लॉक के जागेश्वर ने तालाब खुदाई में सात दिन कार्य किया, लेकिन उसे मात्र तीन दिन का पैसा मिला. मोहनलालगंज विकास खंड के राकेश के पास जॉब कार्ड तो है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिला. प्रदेश में नरेगा दिवस के पहले ही दिन सारी कलई खुल गई, शिविरों में अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंचे. फ़ैज़ाबाद में 22, गोंडा में 42, लखीमपुर खीरी में 18, सीतापुर में 44 और बाराबंकी में 10 शिकायतें मिली. ललितपुर में ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद की मौजूदगी में लगे शिविर में मात्र 40-50 लोग ही उपस्थित थे. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य के उन्नाव दौरे पर उन्हें वृक्षारोपण के नाम पर लाखों डकारने, काम करने के बावजूद मज़दूरी न देने जैसी अनेक शिकायतें मिलीं. नवाबगंज तहसील के मगदूमपुर गांव के 300 मज़दूरों के जॉब कार्ड स्वयं मंत्री ने प्रधान के क़ब्ज़े से लेकर उन्हें वापस दिए. केंद्रीय मंत्री ने औरास ब्लॉक के डिपबल, सिंधूर, कबराई, पूराचांद और लोधई गांव में वृक्षारोपण के नाम पर 40 लाख रुपये के भुगतान के बावजूद मौक़े पर एक भी पेड़ न लगा होने पर आश्चर्य व्यक्त किया. वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, ग़ाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही के 128 विकासखंड क्षेत्रों में से सिर्फ़ 76 पर ही खंड विकास अधिकारी नियुक्त हैं. एक बीडीओ को तीन-तीन विकासखंडों का खेवनहार बना दिया गया है. नरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1779.48 करोड़ का बजट उपलब्ध है, जिसमें से 853.60 करोड़ रुपये अब तक व्यय हुए हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता डा0 आशीष पटैरिया बताते हैं कि रायबरेली और अमेठी में नरेगा प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया है. कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस इस योजना को ग़रीबों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है. कानपुर ज़िले में 1,35652 लोगों को जॉब कार्ड तो दिए गए, लेकिन काम सिर्फ़ 12768 लोगों को ही मिल पाया. बरहट गांगर गांव में तो ग्राम विकास अधिकारी ने काग़ज़ पर ही 120 मज़दूरों को जॉब कार्ड दे दिया और उनके ख़ाते मंधना स्थित सेंट्रल बैंक में खुलवा दिए. जबकि वास्तव में उसने एक भी व्यक्ति को न जॉब कार्ड दिया और न किसी का ख़ाता खुलवाया. मकसूदाबाद, नौरंगा, मछैला, पतरसा व सरसौल आदि गांवों में भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है. बुंदेलखंड में इस योजना को परवान चढ़ाने में ग्राम प्रधान ही बाधक है. जॉबकार्ड तो बने, लेकिन मज़दूरों के हाथ पहुंचने के बजाय ग्राम प्रधान के घरों में पड़े रहे. प्रधान अपने ख़ास लोगों के नाम मास्टर रोल में भरकर मज़दूरी डकारते रहे. जालौन में नरेगा के तहत 1,24418 परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं. 31 मार्च 2008 से शुरू वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक 46068 परिवारों को रोज़गार दिया गया. महोबा को अब तक 35 करोड़ रूपये आवंटित हो चुके हैं. प्रशासन 57 हज़ार से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का दावा करता है. चित्रकूट में नरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए 3849.91 लाख रुपये की धनराशि में से 31 अगस्त तक 2131.84 लाख रुपये ख़र्च तो हुए, लेकिन अभी भी सैकड़ों जॉब कार्ड धारक दो-दो महीने की मज़दूरी के लिए भटकते दिखते हैं. फतेहपुर में पचास हज़ार से अधिक ऐसे ग़रीब परिवार हैं, जिन्हें शायद ही साल में सौ दिन का रोज़गार मिला हो. 80 प्रतिशत मज़दूरों के अभी तक बैंक ख़ाते नहीं खुले हैं. कन्नौज में सवा दो करोड़ रुपए से नरेगा की शुरुआत एक अप्रैल को हुई, लेकिन स्थायी मुख्य विकास अधिकारी न होने की वजह से नरेगा एक माह तक सिर्फ़ काग़ज़ों और मीटिंगों में ही सिमटी रही. औरैया में योजना लागू होने के पांच माह गुज़रने के बाद भी आधी ग्राम पंचायतों में नरेगा के अंतर्गत काम की शुरुआत नहीं हो सकी.

feedback@chauthiduniya.com

क्या भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है

फोटो– प्रभात पाण्डेय

भारत में सत्ता पर क़ाबिज़ लोगों को इस बात का अहसास है कि चीन के मुद्दे पर नकारात्मक रुख़ अख्तियार करने का कोई तुक नहीं है. हालांकि कभी-कभी तनाव बढ़ाने वाले बयानों के प्रति लापरवाही भी दिखती है.

सीमा मुस्तफा

बीजिंग से तिब्बत तक चलने वाली ट्रेन रणनीतिक तौर पर संवेदनशील ऊंचाईयों तक पहुंच चुकी है. स्थानीय चीनी और कुछ विदेशियों से भरी ट्रेन दम फुला देने वाली ऊंची वादियों से गुज़रती है. ऊंचाई के बावजूद ट्रेन में सवार मुसाफ़िर यहां चल रही सैन्य गतिविधियों की एक झलक के लिए खिड़कियों से टकटकी लगाकर बाहर देखते हैं. इन सबसे हमें कोई हताशा नहीं मिलती. इस रेलवे लाइन और भारत की सीमा तक दौड़ती सड़कों के बेहतरीन जाल की मदद से आज चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सैन्य सामग्री और सैनिकों को पहुंचाने का काम महज़ 25 दिनों में कर सकता है. इसी काम में पहले उसे छह महीने लगते थे. चीन ने 2009 परेड की अभ्यास के दौरान तिब्बत में 50,000 से भी अधिक जवानों को इकट्ठा कर लिया है. जिसके लिए उसने नागरिक क्षेत्रों सहित हवाई और ट्रेन लिंक का भी इस्तेमाल किया. चीन इन अभ्यासों के ज़रिए पीएलए की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है. पीएलए की रैपिड रिएक्शन फोर्स को रिज़ॉलविंग इमरजेंसी मोबाइल कॉमबेट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपातकाल में 24 से 48 घंटे के भीतर किसी भी जगह पहुंच हालात पर क़ाबू रखने की क्षमता रखता है. विश्लेषकों की मानें तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजिंग अब किसी भी आपात स्थिति में या भारत की ओर से ख़तरा होने पर या किसी भी वजह से चार डिविज़न या 2,00,000 से अधिक सैनिकों को भारतीय सीमा पर तत्काल तैनात कर सकता है. तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीन के नौ हवाईअड्डे हैं, जिनमें चार पीएलए की मदद के लिए ल्हासा में ही हैं.

नई दिल्ली में सीमा विवाद के मुद्दे पर 13वें दौर की चर्चा में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि एम के नारायणन और दाई बिंगुओ के बीच बातचीत में कुछ प्रगति हुई है. इसमें चीन की तरफ़ से उठने वाले ख़तरे पर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसका चीन ने विरोध भी किया. चीनी मीडिया ने भारतीय नीति पर ही आक्रामक तेवर अपनाते हुए बताया कि भारतीय रणनीति से ही चीन को ख़तरा है, न कि चीन से भारत को. भारतीय नौ सेना के सेवानिवृत प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता ने अपने पहले के रुख़ को स्पष्ट करते हुए बताया, उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि भारत चीन का मुक़ाबला नहीं कर सकता. लेकिन, यह सच है कि पारंपरिक और ग़ैर-पारंपरिक सैनिक क्षमताओं के लिहाज़ से भारत के पास बीजिंग जैसी शक्तियां नहीं है. इसलिए ज़रूरी है कि भारत सशक्त सैन्य क्षमताओं के विकास पर ध्यान दे. एडमिरल मेहता के मुताबिक़ यह भारत के लिए मुश्किल नहीं है. हमारे पास चीन से भी बेहतर जहाज हैं और तकनीक के मामले में हम चीन को उसके ही खेल में मात दे सकते हैं. भारत में सत्ता पर क़ाबिज़ लोगों को इस बात का अहसास है कि चीन के मुद्दे पर नकारात्मक रुख़ अख्तियार करने का कोई तुक नहीं है. हालांकि कभी-कभी तनाव बढ़ाने वाले बयानों के प्रति लापरवाही भी दिखती है. सरकार भारतीय सीमाओं के आसपास चीनी सेना के तेज़ी से बढ़ने की घटनी पर किसी भी ठोस प्रतिक्रिया को देने में बुरी तरह नाकाम रही है. पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले. जनरल विजय ओबराय के मुताबिक़, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति-निर्माता कोई भी कड़ा फ़ैसला नहीं ले पाते हैं और इसका ख़ामियाज़ा यह होता है कि सभी को भारत एक कमज़ोर राष्ट्र नज़र आता है, जो तनाव के समय में हमेशा घुटने टेक देता है. चेन्नई स्थित चाइना स्टडी सेंटर के कर्नल आर हरिहरण की मानें तो भारत के पड़ोसी देशों में यह धारणा बन चुकी है कि यह एक सॉफ्ट स्टेट है और धारणाओं से ही विश्वास बनता है. साथ ही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से कैसे अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार करता है. यदि देखें तो सुरक्षा से जुड़ी अधिकतर समस्याओं की वजह हैं, दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति का अभाव, समय पर अपने स्रोतों का इस्तेमाल न कर पाने की अयोग्यता, असुलझा थल और जल सीमा, पड़ोसियों से सुदृढ़ संबंधों का अभाव, साथ ही घरेलू स्तर पर उठे विवादों का समाधान न कर पाना. 1980 के दशक में श्रीलंका के साथ शांति प्रक्रिया की बहाली में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हरिहरण के मुताबिक़, इन सबके अलावा बातचीत के मसलों पर विफलता ने भी भारत की नकारात्मक छवि बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है. सेना और रणनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो हाल के समय में भारत ने ऐसे तीन मौक़े गंवाए, जब वह कड़ी कार्रवाई के ज़रिए एक ठोस संदेश दे सकता था. पहला अवसर था– करगिल के दौरान पाकिस्तानी इलाक़ों में हमला नहीं करने का फ़ैसला, दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद किसी भी तरह की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई न करना और आख़िरी मौक़ा जो हमने गंवा दिया, वह था पिछले साल मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद किसी भी ठोस नतीजे पर न पहुंचना. भूतपूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सतीश चंद्रा के मुताबिक़, करगिल फतह के समय एनडीए सरकार का मानना था कि अधिक क्षति से बचने का बेहतर तरीक़ा है कि करगिल की ऊंची चोटियों पर दोबारा क़ब्ज़ा करने के लिए सीमा पार कर उस इलाक़े को पूरी तरह से सीज़ कर दिया जाए. ताकि पाकिस्तानी सेना को ऊंची चोटी से धकेल बाहर कर दिया जाए. लेकिन उस समय के थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने इसका विरोध किया. उनके मुताबिक़ युद्ध की नौबत आने पर सेना न तो पूरी तरह हथियारों से लैस है और न ही तैयार. उनकी इस बात का समर्थन दो अन्य ख़ुफ़िया एजेंसी प्रमुखों द्वारा भी की गई. वे इस बात पर भी सशंकित थे कि यदि संघर्ष लंबा खींचा तो इसके नतीजे क्या होंगे.

कड़ी कार्रवाई करने का दूसरा अवसर संसद पर आतंकी हमले के बाद आया. लेकिन दिसंबर 2001 में अपनी सीमाओं पर अब तक के सबसे बड़े सैनिक जमावड़े, जो लगभग दस महीने तक रहा, के बाद एनडीए सरकार ने बग़ैर एक भी गोली चलाए या पाकिस्तान को बिना कोई ठोस संदेश दिए ही अपने सैनिकों को वापस बुलवा लिया. पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल ए पद्मनाभन के विचारों से कई सैन्य अधिकारी सहमत दिखते हैं. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि जनवरी 2002 में, राजनीतिक तौर पर युद्ध का फ़ैसला लेना भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी सेना ने अभी भारतीय सीमाओं के पास आना शुरू ही किया था. वह इस बात से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान के चुनिंदा इलाक़ों में आंशिक रूप से हवाई हमला किया जाए. उनका मानना था कि यदि किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और आप सही में उसे दंडित करना चाहते हैं, तो उसे बुरी तरह से तोड़ दीजिए. आप उसके हथियारों को नष्ट कर दीजिए और उसके इलाक़े पर क़ब्ज़ा कर लीजिए. लेकिन उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इसके लिए एक ख़ास नीति होनी चाहिए और इस पर सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति होना ज़रूरी है. ज़ाहिर है, तीसरा अवसर मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद आया, जब सेना सीमा पार जाकर किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए तैयार थी कि मुंबई जैसे नागरिक ठिकाने पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लेकिन सरकार ने ऐसे किसी भी मुद्दे पर एतराज़ जताया और इस तरह तीसरे मौक़े से भी हम चूक गए. चंद्रा ने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इससे भलीभांति वाक़िफ़ थी कि भारत किसी भी तरह का निर्णायक सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा. उसकी प्रतिक्रिया यही होगी कि हम दूसरी बड़ी आपदा की तरह इससे भी निपट लेंगे. चंद्रा कहते हैं, भारत की समस्या यह है कि हमारे ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई की गई, उसके लिए हमने किसी पर जवाबी कार्रवाई नहीं की. साथ ही, वह यह भी कहते हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और जो भी समस्याएं हमारे रास्ते में आती हैं, उसे चुपचाप स्वीकार करते जाते हैं. लेकिन जब सवाल राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हो तो सरकार को नतीजों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, न कि एक दब्बू राष्ट्र का तमगा लेकर घूमना चाहिए. विशेषज्ञों के मुताबिक़, चीन का मसला रणनीतिक तौर से निपटने का है. लेकिन सरकार ने चीनी प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए इस दिशा में बहुत ही कम काम किया है. भारत के सभी पड़ोसी देशों मसलन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और यहां तक कि मालदीव से चीन का सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संबंध हर तरफ़ से भारत के गले में शिकंजा कसने की साज़िश है. अमेरिकी विश्लेषकों की मानें तो चीन अपने इस मक़सद को अंजाम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मिशन के तहत दे रहा है.

(शेष अगले अंक में)

लेखिका विश्वविख्यात पत्रकार हैं

feedback@chauthiduniya.com

बसपा दलितों का रहनुमा होने का दावा करती है, जबकि हक़ीक़त यह है कि बसपा नेता खुलेआम दलितों की ज़मीन हड़प रहे हैं.

दलितों की ज़मीन हड़प रहे हैं बसपा नेता

कहावत है, नशा जब कभी किसी शख्स पर हावी हो जाता है तो विवेक का नाश कर देता है. बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ इन दिनों यही स्थिति है. जो हाथ कल तक शोषण के ख़िलाफ़ झंडा बुलंद करते थे, वही आज सत्ता के नशे में ग़रीबों और बेसहारों के लिए खंज़र साबित हो रहे हैं. कौन ध्यान देगा इस ओर?

शिव दास

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सियासतदारों के काले कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहा है. विंध्य क्षेत्र के भूमिहीन दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की राजनीति करके अपनी दुकानें चमकाने वाले रहनुमा अब ख़ुद खुलेआम लूटखसोट पर आमादा हैं. इस बार तीन विधायकों समेत आधा दर्ज़न बसपा नेताओं की काली करतूतें सामने आई हैं, जिन्होंने असहाय दलितों की ज़मीन पर अपनी नीयत ख़राब कर दी है.

राजगढ़ से विधायक अनिल कुमार मौर्या 2006 के हवाला ऑपरेटर कांड में पूरे देश में चर्चित हो चुके हैं. मौर्या ने बीते लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर हाथ आजमाया था, लेकिन हार गए. हवाला के ज़रिए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके बसपा विधायक मौर्या ने इस बार लाखों रुपए की स्टांप चोरी को अंजाम दिया है. साथ ही वन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की साज़िश रच रहे हैं. विधायक मौर्या ने राबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत विजयगढ़ परगना के सिलहट गांव में अपने भतीजों संदीप कुमार मौर्या व मधुकर मौर्या के नाम ऐसी ज़मीन ख़रीदी, जिस पर वन विभाग के करोड़ों रुपए के साखू, महुआ, कहु, पियार, आसन, आंवला और बरगद आदि के पेड़ हैं. मौर्या के भतीजों ने उक्त विवादित ज़मीन पनिकपकला निवासी चंद्रभूषण सिंह से ख़रीदी है. विधायक मौर्या के भतीजों द्वारा ख़रीदी गई 14.06 हेक्टेयर (आराजी संख्या 66 मी0) भूमि 1960 के सर्वे सेटलमेंट के दौरान वन विभाग की ज़मीन थी. वर्ष 1997–98 के दौरान हुए सर्वे–चकबंदी में भू–राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से उक्त भूमि पनिकपकला निवासी चंद्रभूषण सिंह के नाम दर्ज़ हो गई, जबकि पूरी भूमि पर घना जंगल है.

चंद्रभूषण सिंह ने आराजी संख्या 66 मी. की 14.06 हेक्टेयर भूमि 11 दिसंबर, 2008 को विधायक मौर्या के भतीजों संदीप व मधुकर को बेच दी. भूमि का बैनामा पेड़ व सड़क आदि तथ्यों को छुपाकर कराया गया, जिससे शासन को स्टांप शुल्क के रूप में लाखों रुपये की क्षति हुई. भूमि का बैनामा होते ही विधायक मौर्या और उनके लोग पेड़ों को कटवाने लगे. इस दौरान वन विभाग और ज़िला प्रशासन सोता रहा. क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध करने पर वन विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी और उन्होंने विवादित पेड़ों

सीएम प्रसाद

परमेश्वर दयाल

जैसाल

की कटाई पर रोक लगा दी. रामगढ़ वन प्रभाग के वन रेंज अधिकारी आर के प्रेमी का कहना है कि आराजी संख्या–66 की भूमि वन विभाग की है. विवादित भूमि के संदर्भ में धारा–4 की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और धारा–20 की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. शासन की ओर से धारा–20 की कार्रवाई में हो रही देरी को लोग बसपा विधायक की ऊंची पहुंच से जोड़कर देख रहे हैं. अब बात करते हैं विधानसभा सीट राबर्ट्सगंज से बसपा विधायक सत्यनारायण जैसल की. जैसल पार्टी के मंडल संयोजक रह चुके हैं और मायावती के ख़ास बताए जाते हैं. चुर्क निवासी विधायक जैसल राबर्ट्सगंज के मुसही गांव निवासी दलित अशोक कुमार का हक़ छीनने की कोशिश कर रहे हैं. जैसल ने अशोक कुमार के चाचा स्व. चंद्रदेव प्रसाद नागर की कई बीघा ज़मीन फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर अपनी पत्नी के नाम बैनामा करा ली और अब वह उसे ज़मीन से बेदख़ल कर रहे हैं. विधायक जैसल ने जिस ज़मीन

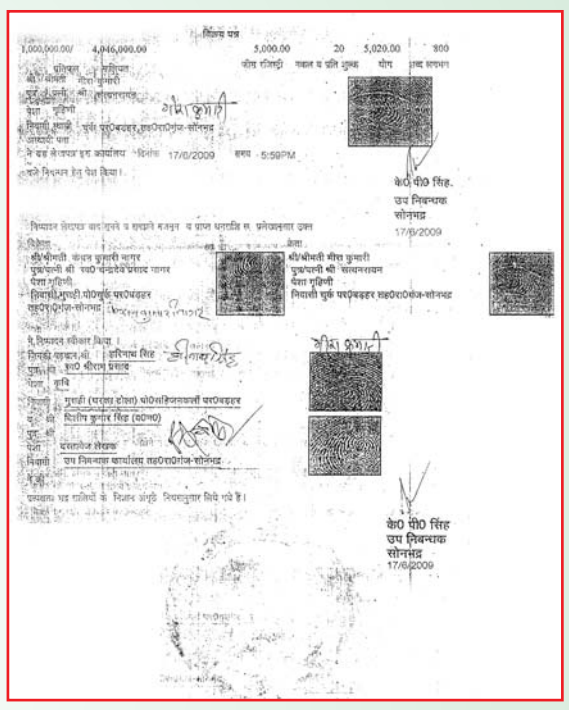

का बैनामा कराया है, वह विवादित है और उसे लेकर एक मुक़दमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र की अदालत में विचाराधीन है. अशोक के चाचा चंद्रदेव प्रसाद गोंडा ज़िले में कस्टम अधीक्षक थे, जिनकी शादी 10 साल पहले बलिया के चेतन किशोर गांव निवासी परीखाराम की पुत्री कंचन से हुई थी. कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और कंचन अपने मायके चली गई. बाद में उसने बलिया में ही चरौवा गांव निवासी बेचू से दूसरी शादी कर ली.

उधर 14 जनवरी, 2003 को कस्टम अधीक्षक चंद्रदेव प्रसाद का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया. बलिया के गौरा गांव निवासी विश्राम की पुत्री पुष्पा उर्फ चिलरी शव को लेकर मुसही आई और उसने ख़ुद को कंचन बताया. परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया. पुष्पा ने कंचन बनकर कस्टम अधीक्षक नागर की 10 बीघा 09 बिस्वा (आराजी संख्या–356मी0 व 357मी0) भूमि 24 मार्च, 2007 को अपने नाम करा ली. अशोक ने अपने चाचा नागर की मृत्यु के पहले की वसीयत को आधार बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र की अदालत में मुक़दमा दाख़िल किया. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर गत 24 अप्रैल को राबर्ट्सगंज पुलिस को आई पी सी की धारा 419, 420, 467, 468 के तहत प्राथमिकी दर्ज़ कर जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद बसपा विधायक जैसल ने 17 जून, 2009 को पुष्पा उर्फ चिलरी उर्फ कंचन से आराजी संख्या 357 मी0 की 2.023 हेक्टेयर भूमि का बैनामा अपनी पत्नी मीरा कुमारी के नाम करा लिया. अगले दिन यानी 18 जून, 2009 को जैसल ने शेष बचे आराजी संख्या–357 मी. की 0.644 हेक्टेयर भूमि का बैनामा भी दलशृंगार मेमोरियल शिक्षा समिति, रौंप, सोनभद्र की प्रबंधक/सचिव मीरा कुमारी के नाम पुष्पा उर्फ कंचन से करा लिया. बैनामा कराने के बाद विधायक जैसल और उनके लोग अशोक को ज़मीन से बेदख़ल करने लगे. अशोक ने मामले की शिकायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन, मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक विंधायचल समेत ज़िलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. ज़िला प्रशासन की उदासीनता और विधायक से मिल रही धमकियों से सहमा अशोक न्याय के लिए दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर है. राबर्ट्सगंज के पूर्व सपा विधायक एवं वर्तमान बसपा नेता परमेश्वर दयाल भी एक दलित की ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. पूर्व विधायक दयाल राबर्ट्सगंज नगर स्थित एक सरकारी भवन पर अभी भी क़ब्ज़ा जमाए हुए हैं. दयाल ने अपने कार्यकाल के दौरान 16 नवंबर, 2006 को राबर्ट्सगंज तहसील के कम्हारी गांव में फ़र्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर अपनी पत्नी गंगाजली के नाम 0.491 हेक्टेयर (आराजी संख्या–156मी.) भूमि का बैनामा दुखंती से कराया था. पूर्व विधायक की पत्नी ने जिस ज़मीन का बैनामा कराया है, वह पहले राबर्ट्सगंज (टाड़ के डौर) निवासी दलित बलई उर्फ महादेव की पत्नी विफनी देवी के नाम थी. विफनी की एक पुत्री फुलवा देवी है जिसकी शादी चंदौली के चकिया तहसील के जनकपुर गांव निवासी गोकुल प्रसाद से हुई थी. विफनी देवी का दुखंती से कोई संबंध नहीं था.

विफनी की मौत के बाद उसी के गांव के दुखंती ने 20 मई 1970 को लिखी गई वसीयत के आधार पर विफनी देवी की एक बीघा 18 बिस्वा 15 धूर ज़मीन 31 मार्च 1986 को अपने नाम करा ली. दुखंती ने 16 नवंबर, 2006 को आराजी संख्या–156मी. की ज़मीन पूर्व विधायक दयाल की पत्नी गंगाजली को बेच दी. ज़मीन का बैनामा होते ही पूर्व विधायक और उनके आदमियों ने फुलवा देवी को ज़मीन से बेदख़ल कर दिया. फुलवा देवी के पति गोकुल प्रसाद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र की अदालत में मुक़दमा संख्या 1938 दाख़िल कर न्याय की गुहार लगाई. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पूर्व विधायक परमेश्वर दयाल, गंगाजली देवी, दुखंती, विमलेश और रघुनाथ प्रसाद को आईपीसी की धारा 147, 467, 468, 420, 471 और 120बी का आरोपी पाते हुए तलब किया है. अति नक्सल प्रभावित विधानसभा सीट दुद्धी के बसपा विधायक सी.एम. प्रसाद भी ज़मीन के गोरखधंधे में शामिल हैं. पूर्व में पुलिस अधिकारी रहे प्रसाद ने दुद्धी नगर पंचायत में को–आपरेटिव बैंक की दो चौथाई भूमि पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर रखा है. विवादित भूखंड में बसपा विधायक प्रसाद एक चौथाई भाग के मालिक हैं, शेष तीन चौथाई भूमि का मालिक को–आपरेटिव बैंक है. बावजूद इसके, बसपा विधायक प्रसाद विवादित भूखंड के तीन चौथाई भाग पर क़ब्ज़ा किए हुए है. सूबे में पार्टी की सरकार होने के कारण प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है. विंध्य क्षेत्र में बसपा के छुटभैया नेता भी किसी से कम नहीं हैं. राबर्ट्सगंज तहसील की ग्राम सभा बहुअरा में बसपा नेता सुखराम भारती और श्याम जी कुशवाहा का क़हर एक दलित महिला पर जारी है. दोनों बसपा नेता अब भूमिहीन दलित महिला के घर को गिराकर कर उसे खुले आसमान के नीचे सोने को मज़बूर कर रहे है. पूर्व में भी बहुअरा निवासी बसपा नेताओं बनवारी, श्याम सुंदर कुशवाहा और बलवंत ने दलित रामनरेश भारती की 0.132 हेक्टेयर भूमि का फ़र्ज़ी बैनामा कराया था. रामनरेश ने ज़िला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा. इसके बाद रामनरेश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुक़दमा दाख़िल किया. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 420, 467, 468 व 120बी का आरोपी पाते हुए तीनों पर प्राथमिकी दर्ज़ कर पुलिस को जांच करने का आदेश दिया. राबर्ट्सगंज के ब्लॉक प्रमुख एवं बसपा नेता कमलाकांत पांडेय ने भी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनवा रखा है.

feedback@chauthiduniya.com

ग्रामीण भारत से रोज़ी-रोटी की तलाश में लाखों लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर पलायन करते हैं.

'परदेस' जाने की मजबूरी ख़त्म

उमाशंकर मिश्र

गावों से रोज़ी-रोटी की तलाश में लाखों लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर पलायन करते हैं. परिवार का पेट पालने की ज़िम्मेदारी के चलते इन लोगों को न केवल अपने घर-परिवार से दूर रहना पड़ता है, बल्कि तमाम पारिवारिक एवं सामाजिक दबावों को अनदेखा कर परदेस में विषम परिस्थितियों के बीच रहकर गुज़र-बसर करना पड़ता है. लेकिन, गुजरात के मोरकंडा गांव के निवासियों के साथ अब ऐसा नहीं है. जिन कारीगरों को पहले काम करने के लिए सूरत, मुंबई, गांधीनगर अथवा नवसारी जैसे शहरों की ओर रुख़ करना पड़ता था, आज वे घर पर ही रह कर काम करने लगे हैं.

उदारीकरण के बाद आज जब ग्रामीण उद्योग-धंधे चौपट होते जा रहे हैं और कृषि भी संकट के दौर से गुज़र रही हो तो ग्रामीण बेरोज़गारों का शहरों की ओर पलायन एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है. लेकिन गुजरात के मोरकंडा गांव के ग्रामीण आज अपने घर-परिवार के साथ रहकर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं. इस तरह मोरकंडा के गंवई परिवेश के लोगों के लिए रोज़ी-रोटी की तलाश में घर-परिवार छोड़कर शहरों के निष्ठुर वातावरण में जाने और काम करने की मजबूरी समाप्त हो रही है. जामनगर ज़िले के मोरकंडा गांव निवासी नरेंद्र भाई बेलजी चौहान इस बात की जीती-जागती मिसाल हैं. नरेंद्र भाई दो बीघे से भी कम भूमि के काश्तकार हैं. परिवार के छह प्राणियों के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी उन पर है. नरेंद्र भाई बताते हैं कि खेती-बाड़ी कम होने से गुज़र-बसर में समस्या आती थी, जो अब ख़त्म हो गई है. आज नरेंद्र भाई के चेहरे पर शिकन की लकीरें नज़र तक नहीं आतीं. वह खुलकर ठहाका लगाते हैं और इत्मीनान से पान चबाते हैं. लेकिन कुछ समय पूर्व नरेंद्र भाई चौहान की परिस्थितियां बिल्कुल उलट थीं. ख़ुद नरेंद्र भाई के साथ उनके दोनों बेटों को भी काम करने के लिए जामनगर जाना पड़ता था. इतनी दूर जाकर काम करने के बाद भी पूरे परिवार का गुज़ारा करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज नरेंद्र भाई व उनके बेटों को काम करने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता.

नरेंद्र भाई अपने गांव मोरकंडा में रहकर ही ब्रास पिन बनाने का काम करते हैं, इसके लिए उन्होंने नौ मशीनें लगाई हैं. नरेंद्र भाई बताते हैं कि हम जिसके लिए काम करते हैं, मशीनें भी उसी सेठ ने दी हैं. गांव के सरपंच के मुताबिक़, मोरकंडा में क़रीब 80 प्रतिशत लोगों के पास अपनी मशीनें हैं और सभी जगह ब्रास पार्ट का काम होता है. वह बताते हैं कि खेमालिया, ठेबा और मोखाणा में भी ब्रास पार्ट का काम होता है, लेकिन मोरकंडा इनके मुक़ाबले काफी आगे है. वह बताते हैं कि मोरकंडा के अमूमन हर घर में ब्रास पार्ट का ही काम होता है. बिजली की आंखमिचौली कम हो जाने से गांव के हालात भी बदल गए हैं. पहले ब्रास पार्ट का यह काम दम तोड़ने की हालत में था, अब इसमें नई जान आ गई है. इन मशीनों पर नरेंद्र भाई और उनके दोनों बेटों सहित सात लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, जिसमें गांव की दो महिला कारीगर भी शामिल हैं.

ब्रास पार्ट के काम में लगी आशाबेन कहती हैं कि वह प्रतिदिन इस काम से 150 से 200 रुपए तक कमा लेती हैं. नरेंद्र चौहान बताते हैं कि ब्रास पार्ट के काम के लिए 25 हॉर्स पावर की मशीनें लगाई गई हैं. बड़े तथा छोटे काम के लिए मशीनें भी अलग होती हैं. वह बताते हैं कि सभी ख़र्च निकाल कर उन्हें महीने में छह से सात हज़ार रुपए तक की कमाई हो जाती है.

नरेंद्र भाई चौहान ने आठ साल पहले गांव में ही रहकर ब्रास पार्ट मशीन लगाने का साहसिक क़दम उठाया था. हालांकि समय के साथ-साथ बिजली की आंखमिचौली ने उनके उत्साह को चकनाचूर करके रख दिया था. इसके बावजूद उन्होंने इस चुनौती से हारकर मुंह मोड़ने के बजाय डटकर उसका सामना किया. वह बताते हैं कि पहले यहां पूरे दिन में चार से लेकर अधिकतम आठ घंटे ही बिजली रहा करती थी और वह भी अनियमित. इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित तौर पर किसी उद्योग के फलने-फूलने में रास्ते का रोड़ा बन सकती है. नरेंद्र भाई लंबे समय तक इस तरह की समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन आज नरेंद्र भाई के गांव मोरकंडा में 20 से 24 घंटे तक बिजली रहती है. इससे ब्रास-पिन के उत्पादन में 50 फ़ीसदी तक की वृद्धि हुई है. इसके चलते न केवल नरेंद्र भाई और उनके बेटों का उत्साह बढ़ा है, बल्कि उन्हें अपने घर-परिवार के बीच रहकर अच्छी ख़ासी आमदनी भी होने लगी है.

नरेंद्र भाई इस बदलाव का श्रेय राज्य सरकार की ज्योतिग्राम परियोजना को देते हैं. इस परियोजना द्वारा गुजरात के गांवों को अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है. स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक़, ज्योतिग्राम योजना एक हज़ार से भी कम दिनों में पूरे राज्य में लागू कर दी गई थी.

उदारीकरण के बाद आज जब ग्रामीण उद्योग-धंधे चौपट होते जा रहे हैं और कृषि भी संकट के दौर से गुज़र रही हो तो ग्रामीण बेरोज़गारों का शहरों की ओर पलायन एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, लेकिन गुजरात के मोरकंडा गांव के ग्रामीण आज अपने घर-परिवार के साथ रहकर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं. इस तरह मोरकंडा के गंवई परिवेश के लोगों के लिए रोज़ी-रोटी की तलाश में घर-परिवार छोड़कर शहरों के निष्ठुर वातावरण में जाने और काम करने की मजबूरी समाप्त हो रही है.

स्थानीय लोगों की मानें तो बिजली के रहने से उद्योगों के अलावा अन्य कामों में भी अब सुविधा हो गई है. बच्चों को पढ़ने के लिए अब लालटेन के भरोसे नहीं रहना पड़ता और साथ ही सिंचाई के लिए वर्षा पर किसानों की निर्भरता भी समाप्त हो गई है. सरपंच माटू भाई के मुताबिक़, मोरकंडा में हर तरह की शहरी सहूलियतें अब नागरिकों को मिलने लगी हैं. गांव में ही दसवीं तक का स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र है. हर घर में नल के ज़रिये पानी की आपूर्ति होती है और गांव की गलियों में खड़ंजे बिछे हुए हैं. मोरकंडा को उसकी एक और विशेषता के लिए जाना जाता है. इस आदर्श गांव में पिछले 32 वर्षों से चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी. वजह, लोग मिलकर आम सहमति से सरपंच का चुनाव कर लेते हैं. इसी के चलते मोरकंडा गांव को समरस गांव की संज्ञा दी जाती है. सरकार की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप इस गांव को एक लाख रुपए का अनुदान भी मिल जाता है, जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए होता है.

क़रीब पांच हज़ार की आबादी वाले मोरकंडा गांव में 24 घंटे पीने का पानी सप्लाई होता है. भानू भाई माटू भाई मोरकंडा के सरपंच हैं. वह बताते हैं, यहां क़रीब 40 प्रतिशत लोगों के पास मात्र दो से तीन बीघा ज़मीन है और कम ज़मीन होने के कारण पहले लोगों को रोज़ी-रोटी की तलाश में जामनगर के अलावा सूरत व नवसारी जैसे शहरों की ओर रुख़ करना पड़ता था. बकौल माटू भाई वहां इन लोगों को मालिक के दुर्व्यवहार के अलावा मानसिक तनाव से भी गुज़रना पड़ता था, लेकिन घर चलाने की मजबूरी उन्हें गांव वापस आने से रोक लेती थी. आज सरपंच माटू भाई को अपने गांव की तरक़्क़ी पर गर्व होता है. वह बताते हैं कि बिजली आने से लोगों की बेकारी चली गई है. वह घर के कामकाज तक सिमटी रहने वाली महिलाएं भी अब बाहर निकलकर काम करने लगी हैं. इससे महिलाओं की स्थिति बदलने में भी मदद मिली है. पूरे गांव के लोग अपने काम से न सिर्फ़ ख़ुश हैं, बल्कि ख़ुशहाल भी.

feedback@chauthiduniya.com

विनाशकारी विकास मंज़ूर नहीं

कांची कोहली

इंसान ख़ुद को चुनौती दे, यह कतई आसान नहीं है. साथ ही यह भी आसान नहीं है कि वह अपने रिहायशी इलाक़े के उस स्वरूप को चुनौती दे, जिसके लिए किसी हद तक वह ख़ुद ज़िम्मेदार है. जब इस तरह की बातें सामने आतीं है तो क्या होता है, क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? आज शहर में रिहायशी इलाक़ों की अजीब विडंबना है. या तो इंसान को ख़ुद से दूर घट रही घटनाएं प्रभावित नहीं कर रहीं, या फिर हम अपने नाक केनीचे तेज़ी से बदल रहे हालातों के प्रति जानबूझ कर अनजान बने हुए हैं. शहर में रहने वाले हम जैसों ने ही अपने लिए यह अजीब विडंबना पैदा कर ली है.

विकास प्रक्रिया आज एक हक़ीक़त है और इस हक़ीक़त से पैदा हो रहे सवालों को जानना इससे भी अधिक दिलचस्प होगा. जैसा कि हम जानते हैं आज शहरों में विकास की रफ़्तार तेज़ होने की वजह से भूमि सबसे बड़ी पूंजी के तौर पर उभर रही है. भूमि के मालिकाना हक़ और इस्तेमाल का विवाद न सिर्फ़ दूरदराज़ के संवेदनशील इलाक़ों में है, बल्कि हमारे अपने शहर इस विवाद से घिरे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़भाड़ वाले बड़े शहरों में नदियां, कछार, जंगल या फिर उपजाऊ ज़मीन की स्थितियां कैसी हैं? ज़रा सोचिए, दिल्ली में बह रही यमुना नदी, मुंबई का बोरीवली नेशनल पार्क, पुणे का बेहद ख़ूबसूरत औंध दलदल या फिर हैदराबाद का हुसैन सागर झील, यह सभी प्राकृतिक संपदा के सूचक हैं.

इनके अलावा भी असंख्य संवेदनशील इलाक़े ऐसे हैं, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है. हालांकि ये भी आम जगह ही हैं, जो पर्यावरण को हरा-भरा बनाने का काम कर रहे हैं. अफ़सोस की बात है कि आज ये इलाक़े भी लोगों को निमार्ण कार्य के लिए आकर्षित कर रहे हैं. शायद शहरों में बढ़ रहे शॉपिंग मॉल जैसी विकास की स्थिति हम जैसे लोगों को बहुत भाती है. आज विकास और पर्यावरण को लेकर यही सबसे बड़ा अंतर्विरोध है. हालांकि, दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं. आज उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत सरंचनाएं तैयार करने के नाम पर रियल एस्टेट को अपने विस्तार की रूपरेखा नज़र आती है.

यह कहना कि ऐसे मामलों में विवाद होता ही है, समस्या को कम आकने जैसा होगा. जिसमें आसानी से किसी भी ज़िम्मेदारी को योजनाकारों और फ़ैसला लेने वालों पर थोपी जा सकती है. जबकि आज ज़रूरत है कि हम एकजुट हों और देखें कि हमारे शहरों का भविष्य किस तरह निर्धारित किया जा रहा है. या तो हम उपभोग के अपराधबोध से ग्रस्त हैं या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में हमें शर्म आ रही है, इसलिए हम इन सबसे भागते-फिरते हैं. इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस तरह की सारी समस्याएं कुछ लोगों ने ही पैदा की है. वह भी अपने स्वार्थों के लिए. और हम इसे पसंद करें या नहीं, फिर भी मूक हो कर सारा तमाशा देखते रहते हैं. कम से कम दिल्ली के मामले में तो यह यक़ीनन कहा जा सकता है, जहां एक तरफ़ यमुना के किनारे *यमुना जिए अभियान* कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चल रहे निर्माण के विरोध में चल रहा है वहीं दूसरी ओर इस अभियान में हमारी दिलचस्पी नहीं दिखती है. इत्तेफाक़ से यह वही जगह है, जहां मशहूर अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की गई है. यहां चल रहा निर्माण न सिर्फ़ पर्यावरण को चुनौती दे रहा है, बल्कि संपूर्ण कृषि पारिस्थितिकी को ही पतन के गर्त में ढकेल रहा है.

दूसरे कई शहरों में भी विकास की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, जबकि इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं न के बराबर है. हालांकि बंगलुरु में *हसीरू उसीरू* जैसी कई संस्थाएं और नागरिकों ने इसके तथाकथित शहरीकरण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू किया है. ये संस्थाएं पर्यावरण को संरक्षित और हरे-भरे शहर की कल्पना को दिशा देने की कोशिश में लगे हैं. *हसीरू उसीरू* समय-समय पर रियल एस्टेट के कच्चे चिट्ठे को उजागर भी करता रहा है. हाल ही में लोगों ने लालबाघ और लक्ष्मण राव पार्क को बंगलुरु मेट्रो से जोड़ने पर काफी विरोध किया था. साथ ही मेट्रो के आस-पास के सड़कों के चौड़ीकरण पर भी अपना विरोध जताया था.

अन्य सृजनात्मक अभिव्यक्तियां भी कई मौलिक सवाल उठाने के साथ जवाब तलाश रही हैं. अर्थकेयर फिल्म्स के बैनर तले कृष्णेन्दु बोस की फिल्म *डेल्ही-वर्क इन प्रोग्रेस*, इन सारे सवालों को उठाती है. यह फिल्म दिल्ली के शहरी विकास पर कई सवाल खड़े करती है. साथ ही नीतियां बनाने वालों की राजनीतिक और आर्थिक मंसूबों को भी उजागर करती है. यह फिल्म और बंगलुरू का आंदोलन भले ही स्थानीय या शहर विशेष के हों, लेकिन यह सभी के लिए एक सबक जैसा है. यदि आपने इस फिल्म को देखा है, तो ज़रा याद कीजिए वह वाकया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है- *इस राज्य की आर्थिक कहानी बिल्कुल अलग है. यदि ज़मीन ही किसी फ़ैसले का केंद्र बिंदु है तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का झुकाव अमीरों की तरफ़ ही होगा.*

इसका अगला क़दम जितना नीतिकारों पर निर्भर है, उतना हम पर भी. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो ज़िंदगी में बदलाव पसंद करेंगे. और जैसा कि यह फिल्म इस बात की ओर इशारा भी करती है, *कहीं पहुंचने की जल्दबाज़ी में...क्या हमें थोड़ी देर रूककर यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं?* क्या हम इस विचार के लिए तैयार हैं? अथवा क्या हम अपने इस 24 घंटे की सतत ज़िंदगी से ख़ुश हैं, जो न केवल स्व-उपभोक्तावादी है, बल्कि आत्मघाती भी.

विकास प्रक्रिया आज एक हक़ीक़त है और इस हक़ीक़त से पैदा हो रहे सवालों को जानना इससे भी अधिक दिलचस्प है. जैसा कि हम जानते हैं कि आज शहरों में विकास की तेज़ रफ़्तार की वजह से ही भूमि सबसे बड़ी पूंजी के तौर पर उभर रही है.

(लेखिका, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आज भी यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि क्या शिक्षा और नौकरियों में दिए गए आरक्षण की सुविधा से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हुई है या यह केवल राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने का उपकरण भर रह गया है?

यह मान्यता है कि ईव की जीन ग़रीब एडम की अतिरिक्त पसलियों से बनी थी और तभी से वह उन पसलियों के पिंजरे में क़ैद है. महिलाएं पुरुषों के बाद आईं.

चौथी दुनिया

एम जे अकबर

यह सादगी नज़रों का धोख़ा है!

बीसवीं सदी के अनूठे विद्वान और जासूस हरक्यूल पोइरट ने सामने की चीज़ों को नज़रअंदाज़ करने को अपने नैतिक मूल्यों में अक्षम्य गुनाह के तौर पर रेखांकित किया था. मीडिया ने उस हौआ, सादगी और उत्तेजना पर कम टीवी रेटिंग के साथ-साथ उदारता से जिस तरह शोर मचाया, उसने सबसे वाजिब सवाल को ही अंधेरे में ढकेल दिया कि आख़िर पैसा किसे मिला?

सरकारी ख़र्चों में यात्रा पर होने वाले ख़र्च की हिस्सेदारी मामूली है, लेकिन रेगिस्तान में पानी की बूंदें भी कम महत्वपूर्ण नहीं होतीं. फिर भी, इन विनम्र यात्रियों से होने वाले बचत का पैसा कहां जा रहा है? क्या इन आरामतलब नेताओं पर दबाव बनाकर उन पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए विशेष सादगी फंड भी बनाया गया है? अथवा क्या सरकार, जो सबसे अधिक बिल का वहन करती है, बाबुओं को वेतन देने के लिए इन पैसों को अपने फंड में जमा कर रही है? जैसा कि जगज़ाहिर है, सरकार का सबसे बड़ा लाभार्थी ख़ुद सरकार ही है.

जब कोई संसदीय समिति किसी दौरे पर जाती है तो सांसदों के यात्रा का टिकट और महंगे होटलों के बिल का भुगतान संसद ही करती है. महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अभी भी आत्महत्या कर रहे किसानों और उनके परिवारों के लिए जो पैसे रखे गए थे, अगर वह ख़र्च नहीं हो पाए तो क्या राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने उसे किसी गुप्त ख़ज़ाने (एस्क्रो) में छिपा दिया. राहुल गांधी की यात्राओं का ख़र्च कांग्रेस पार्टी उठाती है, जो निश्चय ही सही है. जब वह निजी प्लेन से सफ़र करते हैं, तब उसका ख़र्च लाखों में आता है. जब वह ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कम से कम कांग्रेस के लिए तो बिल न के बराबर ही होता है. हालांकि यह अलग बात है कि उनकी सुरक्षा का ख़र्च सरकार उठाती है, जिस पर लाखों रुपये का ख़र्च आता है. क्या कांग्रेस बचत की रक़म दक्षिण बिहार में रबी की फ़सल की बर्बादी से प्रभावित किसानों पर ख़र्च करेगी? यह किसी को मालूम नहीं है. हल्की सी एक रोशनी भी बहुत मददगार साबित हो सकती है.

ढाई मंत्रियों (नंदन निलेकणी को कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा तो मिला है, लेकिन विभागीय ज़िम्मेदारी नहीं) को सितारा होटल छोड़कर साधारण घरों में रहने का आदेश दिया गया. (जिसमें से एक ने तुरंत सबके सामने कहा कि उनके कई मित्रों ने रहने के लिए आवास की पेशकश की, लेकिन वह अक्सर जैसे ख़ास खाते-पीते हैं, वैसे रह सकते हैं. दिल्ली की भौतिकी का तीसरा नियम कहता है कि आपकी सत्ता के स्तर के समानुपात मित्रों की संख्या अलग होती है.) उन तीनों में से हरेक अब हर-रोज़ कम से कम 60,000 रुपये की बचत कर रहे हैं. अब जबकि उन्होंने पांच सितारा होटलों में रहने से मना कर दिया है, तो क्या उन्होंने उन पैसों से झारखंड के किसी गांव को गोद ले लिया या ये पैसे पहले से ही उनके भरे-पूरे बैंक खातों की शान बढ़ाएंगे. हमारे पास उनके लिए एक बेहतरीन सुझाव है. क्यों नहीं वे होटल के बिल जितना पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करते? यदि वे आरामदेह बेड और एक कप कॉफी के लिए 60,000 रुपये हर-रोज़ अपनी जेब से ख़र्च कर सकते हैं तो उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाक़ों की मदद के लिए भी इस छोटे बदलाव के लिए सक्षम होना चाहिए. वास्तव में सबसे बड़ी विडंबना है कि जब तीनों को सरकारी आवास मिलेगा तो वे दुनिया के शानदार होटलों के ख्वाबों की दुनिया से एक अलग दुनिया में प्रवेश करेंगे.

अमेरिकी कैबिनेट के सदस्य अपने निजी खेल के मैदान के रूप में वाशिंगटन में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार औपनिवेशिक बंगले के चारों ओर भव्य लॉन बनाने के विचार पर ललचाएंगे. चीनी कैबिनेट मंत्रियों को इस फंतासी के लिए या तो जेल की सजा होती या भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गोली मार दी जाती. भारतीय मंत्री के पास घर है, जो उनकी लालच का नतीजा है. इन सबके लिए कौन भुगतान करता है? दरअसल, आप. यदि आप टैक्स देते हैं, तो यह सब उसी की बदौलत ही है.

दिल्ली में सत्ता (पावर) का मतलब ही भव्यता है. इसकी ज़ोर-आज़माइश में ही तीखे विवाद खड़े हो जाते हैं. इस दरिद्र भारतीय राजधानी में कोई भी सफल इंसान आपसे नाम पूछने से पहले आपका पता पूछेगा. लेकिन केवल यह ध्यान देना जायज़ नहीं है कि पाखंड से भरे यदि इस सिस्टम में किसी के पास इस मुद्दे को उठाने का अधिकार है तो सिर्फ़ उसे ही जो सादगी के अभियान को लागू करता है. बेशक़ दिल्ली में प्रणब मुखर्जी के पास सबसे घटिया बंगला है. जबकि एक सांसद जो इससे भी अधिक आकर्षक बंगले का हक़दार था, उसके बावजूद इसे नहीं बदला गया और उन्हें यह आवास आवंटित किया गया. एक वजह यह है कि जब प्रणब मुखर्जी कुछ कहते हैं तो उनके सहयोगी उनकी बातों पर ध्यान देते हैं. दूसरी वजह यह है कि वह सरकार के अधिकांश विभागों को चलाते हैं.

अब थोड़ी देर के लिए, एक बेहद ही गोपनीय बात. बड़े दर्ज़े के टिकटों से हवाई यात्रा का ख़र्च अधिक नहीं है, बल्कि ज़मीन पर सफ़र करने के काफी क़रीब है. मंत्रियों, सांसदों, नौकरशाहों को उपलब्ध कराए गए हज़ारों महंगी गाड़ियों पर होने वाले ईंधन ख़र्च के बारे में भी पूछा जाना चाहिए. ईंधन की चोरी एक रैकेट बन चुका है. बस एक फ़ैसला, बड़ी राहत, सस्ता ईंधन, पर्यावरण की सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता है. उनकी गाड़ियों के क़ाफिले को सीएनजी गाड़ियों से बदल दीजिए. लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरा अनुमान भी आपके जैसा है, लेकिन मेरा सोचना है, नहीं. यदि आप अगाथा क्रिस्टी-पोइरट की किसी भी मर्डर मिस्ट्री ड्रामा में हत्यारे के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए. आख़िर पैसा किसे मिला? यदि आप दिल्ली की पेचीदगी भरी भूलभुलैया से निकलना चाहते हैं, तो आप भी यही सवाल पूछिए.

feedback@chauthiduniya.com

आरक्षण में योग्यता बनाम योग्यता में आरक्षण

रवि किशोर

शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण हमेशा से विवादास्पद मुद्दा रहा है. कोई भी इसे समाज और देश में व्याप्त विषमताओं के समाधान के तौर पर नहीं देखता. वैसे आरक्षण हमेशा से बहस का विषय रहा है. यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर सभी को पूर्वाग्रहों से परे हटकर निष्पक्ष राय बनानी होगी.

यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि क्या शिक्षा और नौकरियों में दिए गए आरक्षण की सुविधा से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हुई है या यह महज़ केवल राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने का उपकरण भर रह गया है? मेरे विचार से भारतीय संविधान को अपनाने के 59 साल बाद भी आरक्षण के मामले में सीमित सफलता ही मिली है. हालांकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में दिए गए आरक्षण के बावजूद उनमें से ज़्यादातर की दशा पहले जैसी ही है. आरक्षण का लाभ समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंच सका है, जबकि आरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत उन्हें ही है. आरक्षण की पूरी नीति पर विस्तार से चर्चा करना आज समय की मांग है. आरक्षण सौदेबाज़ी का हथियार बन गया है. नेता और राजनीतिक पार्टियां सत्ता की बढ़ती भूख मिटाने के लिए उसका दोहन कर रही हैं. हाल ही में राजस्थान में जाटों को आरक्षण की सुविधा देने के मुद्दे पर जो कुछ हुआ, उसकी यादें लोगों के दिमाग़ में आज भी बनी हुई हैं. धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की ओर से आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को इसकी स्वतंत्रता देता है कि अगर वह पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त मानती है तो वह उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है.

हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ़ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए थी, वह भी महज़ दस वर्षों की अवधि के लिए. लेकिन इस पूरे मामले ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो उसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया. पहले उन्हें नौकरियों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई, फिर शैक्षणिक संस्थानों को भी इसकी परिधि में शामिल कर लिया गया. आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और अंत में इंद्र साहनी और अशोक कुमार ठाकुर के मामले में फ़ैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुलझा दिया. इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में विस्तारपूर्वक नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया और क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया. आरक्षण का मुद्दा तब और भी अधिक विवादास्पद हो गया, जब कई राज्यों और अंत में केंद्र सरकार ने भी अनुसूचित जाति और जनजातियों से इतर दूसरी जातियों के लोगों के लिए आरक्षण के लाभ को विस्तार देने की कोशिश की. 1962 में रंगाचारी बनाम जनरल मैनेजर, साउदर्न रेलवे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है, तब अत्यधिक आरक्षण संविधान की भावना के ख़िलाफ़ होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में सरकार के एक आदेश, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 68 फ़ीसदी सीटें आरक्षित की गई थीं, को ज़रूरत से ज़्यादा मानते हुए ख़ारिज कर दिया और माना कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टी देवदासन बनाम भारतीय संघ के मामले में भी इस फ़ैसले को दोहराया. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पिछड़े वर्गों के दावों और अन्य नागरिकों के बीच उचित संतुलन की ज़रूरत थी. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण के मामले, मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन और पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण के सवाल पर इंद्र साहनी बनाम भारतीय संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फ़ैसले ने इसे अंत तक पहुंचा दिया.

हालांकि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट काफी पहले ही सौंप दी थी, लेकिन वीपी सिंह ने इसे 1990 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के साथ लागू किया. वीपी सिंह की इस घोषणा का देशव्यापी विरोध हुआ. इसके परिणामस्वरूप देश भर में सामान्य जनजीवन में व्यवधान उत्पन्न हुए. इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने वीपी सिंह द्वारा घोषित इस योजना में थोड़ा संशोधन किया. आरक्षण की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को और इसके बारे में विचार कर रहे नौ सदस्यों वाले संविधान पीठ को पहले ही चुनौती दी गई थी. संविधान पीठ ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के ज्ञापन पर फ़ैसला बरक़रार रखा और संविधान के अनुच्छेद 16(4) का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और पूरे मुद्दे पर व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए. सामाजिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जाति, व्यवसाय, ग़रीबी और सामाजिक पिछड़ेपन के बीच एक संपूर्ण संबंध क़ायम है. सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भारतीय संदर्भ में बारीकी से जुड़े हुए हैं. पिछड़े वर्गों की पहचान के संबंध में जाति को ही मापदंड के तौर पर उपयोग में लाया जाता है. क्रीमी लेयर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश की थी. कोर्ट ने पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से संपन्न सदस्यों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के फ़ैसले को सुरक्षित रखा. सुप्रीम कोर्ट ने

अपना यह रुख़ फिर से दोहराया कि कुल आरक्षण 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के मामले में आरक्षण को लागू नहीं करने के फैसले को सुरक्षित रखा और कहा कि अनुच्छेद 16(4) केवल नौकरी हासिल करने के स्तर पर ही आरक्षण की अनुमति देता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि कुछ पद जैसे रक्षा सेवा, अध्यापन और इससे ऊपर, अनुसंधान और विकास के तकनीकी पद, विशेषज्ञताओं वाले पद जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और तकनीकी विषय, पायलट और सह-पायलट आदि को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए कुछ निश्चित न्यूनतम मानक निर्धारित होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की विस्तार से व्याख्या नहीं की और इस पेचीदा मसले को सरकार पर छोड़ दिया. अदालत ने सिर्फ़ इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस आदि पर क्रीमी लेयर के तहत विचार नहीं किया जाएगा और उनके बच्चे आरक्षण के लाभ के हक़दार नहीं होंगे. बाद में क्रीमी लेयर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया. अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में ऊंची आमदनी को क्रीमी लेयर निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार माना गया.

आरक्षण के मसले पर एक बार फिर से सामाजिक बहस तब छिड़ गई, जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 को लागू किया. इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारतीय संघ के मामले में यह मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ी जातियों के पक्ष में क्रीमी लेयर के मसले पर विचार न करने के फ़ैसले को बरक़रार रखा. हालांकि माननीय न्यायाधीशों द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण हैं और यह प्रक्रिया उनके विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं. माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि आरक्षण एक ऐसा हथियार है, जिसका उपयोग समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ताकि वंचित वर्गों को आगे लाया जा सके. संवैधानिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण घटक है. मगर, ठीक उसी समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन न करे. ऐसा इसलिए, क्योंकि यह उसी का हिस्सा है और यह संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है. जब आरक्षण के ज़रिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर सहमति बनी, तब सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के महत्व को बनाए रखा कि अन्य सामाजिक हितों के साथ आरक्षण का संतुलन बनाना उचित है. अर्हता के न्यूनतम अंक की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उत्कृष्टता का मानक अप्रभावित रहे. ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए, जिसमें अन्य पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच न्यूनतम अर्हता के अंक बहुत अधिक हों. सामान्य वर्ग से नीचे 100 मार्क्स में से कट ऑफ मार्क्स 10 मार्क से अधिक नहीं होने चाहिए. बहुत से न्यायाधीशों का मानना था कि पांच साल के बाद आरक्षण की इस लिहाज़ से समीक्षा होनी चाहिए कि इसकी ज़रूरत है या नहीं. अशोक कुमार ठाकुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जातिवाद से ग्रस्त समाज के ख़तरे के बारे में पता था और उसने यह माना कि जाति देश को बांट देगी और यह विकास के लिए भी बाधक है. हाल में जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण दुर्भाग्यपूर्ण हैं. आरक्षण की सुविधा मिलने से पहले लोग पिछड़े वर्ग के बिल्ले से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन आरक्षण की सुविधा मिलने के बाद अब वे पिछड़ेपन के बिल्ले को गले में लटकाए रखना चाहते हैं.

जब अधिक से अधिक लोग अगड़ों की श्रेणी में आने की बजाय पिछड़ों की श्रेणी में ही रहने की कामना करेंगे तो देश ख़ुद-ब-ख़ुद ठहर जाएगा. स्पष्ट है कि आरक्षण की पूरी नीति जाति पर आधारित है और यह वंचितों के उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने और उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ लाने में सक्षम नहीं है.

यह तथ्य है कि आरक्षण अपने वांछित लक्ष्य से दूर है, क्योंकि कई पाठयक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें ख़ाली रह जाती हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम अंक को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं. पीवी इंद्रसेन व अन्य बनाम भारतीय संघ के मामले में इस मुद्दे ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फिर दोहराया कि अन्य पिछड़ी जाति के लिए कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्गों के कट ऑफ मार्क्स से 10 फ़ीसदी कम होने चाहिए. निष्कर्ष के तौर पर मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हालांकि आरक्षण में कुछ योग्यता होनी चाहिए, लेकिन योग्यता में आरक्षण नहीं होना चाहिए. न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी के अनुसार, आरक्षण से ग़लत संदेश जाता है. हर कोई पिछड़ी जाति की स्थिति का लाभ लेने का इच्छुक है. अगर वास्तव में हम सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की मदद करना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी से अनुच्छेद 21-ए को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. हमें उन्हें आरंभ से ही शिक्षा का अवसर मुहैया कराना होगा, तभी वर्ग और जातिविहीन समाज की कल्पना की जा सकती है. बच्चे जब तक कॉलेज जाने वाली उम्र में पहुंचते हैं, तब तक आरक्षण के प्रभावी होने के लिहाज़ से बहुत देर हो चुकी होती है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

उजागर किया तथ्य

प्रिय संपादक जी,

चौथी दुनिया में प्रकाशित लेख करकरे की दुखांत घटना के मामले में आप यह तथ्य सामने लाए कि पहले भी दो महीने तक कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी नरीमन हाउस, मुंबई में रुके थे. यहीं पर उन्होंने हथियार और खाद्य पदार्थ एकत्रित किए. सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

आपने लेख में आगे लिखा है कि हेमंत करकरे की मौत के बाद भी इस बिंदु पर जांच नहीं की गई. हालांकि नरीमन हाउस में अधिक संख्या में इज़रायली नागरिक रहते हैं. अत: नए सिरे से जांच शुरू की जाए. इस संबंध में संभव है कि हिंदू आतंकवाद का नेटवर्क हेमंत करकरे और इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी ने उजागर किया हो. मैं काफी आश्चर्यचकित हूं कि क्या इस बिंदु ने गृह मंत्रालय और उसके ख़ुफ़िया तंत्र को इस ओर जांच के लिए आकर्षित किया.

सैयद शहाबुद्दीन
पूर्व सांसद

हर लेख ज्ञानवर्धक

आदरणीय संपादक जी,

नमस्कार, वैसे तो इसका हर लेख ज्ञानवर्धक होता है. लेकिन *बाक़ी दुनिया* पेज पर छपा लेख कि क्या पाकिस्तान टूट कर बिखर जाएग बेहद रोचक लगा. इसी तरह से जिन्ना एक बेचैन आत्मा-1 और 2 भी अच्छी स्टोरी थी. आशा करता हूं कि हम जैसे पाठकों के लिए आप आगे भी इस सिलसिला को बरक़रार रखेंगे.

विनय शंकर
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

शर्मनाक है स्वार्थ

प्रिय संपादक जी,

सबसे पहले तो *चौथी दुनिया* के नए अंक के लिए धन्यवाद. पिछले अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी विकास की बलि चढ़ता पर्यावरण पढ़कर मानव जाति के स्वार्थ पर शर्म महसूस हो रही है कि किस तरह लोग विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने यह पता नहीं है कि उनकी इस ग़लती का ख़ामियाज़ा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा. आगे भी आपसे ऐसे ही लेख प्रकाशित करने की उम्मीद करता हूं, ताकि इसका कुछ असर लोगों पर तो होगा ही.

दीपक रस्तोगी, *चंद्रपुर, महाराष्ट्र*

भूल सुधार

06-09-2009 के अंक में भूलवश ***हर इंसान में नहीं है भगवान*** शीर्षक की जगह ***हर इंसान में है भगवान*** शीर्षक प्रकाशित हो गया है. इसका हमें खेद है.

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कांग्रेस और भाजपा में कुछ तो फ़र्क़ हो

> कांग्रेस की सरकार है, अच्छा हो कि कांग्रेस लोकसभा में प्रस्ताव लाए कि जब तक देश आर्थिक रूप से मज़बूत नहीं हो जाता या कम से कम आर्थिक मंदी के दौर से निकल नहीं आता, तब तक सभी सांसद साधारण श्रेणी में यात्रा करेंगे. पैसे की बचत तो तभी हो पाएगी. यह क़दम दिखावटी ही सही, पर कांग्रेस ने उठाए तो, लेकिन इनका विरोध जिस तरह भाजपा ने किया, वह अच्छा नहीं लगा.

जी बहुत अच्छा लगा सरकार का उदाहरण पेश करने वाला काम, जैसे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा व विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर को पांच सितारा होटलों से निकाल कर सरकारी गेस्ट हाउसों में भेजना, इसी तरह बहुत अच्छा लगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का साधारण श्रेणी में यात्रा करना. यह और बात है कि सांसदों को हवाई जहाज और रेल में एक्ज़ीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार है और उसका पैसा लोकसभा देती है. कांग्रेस की सरकार है, अच्छा हो कि कांग्रेस लोकसभा में प्रस्ताव लाए कि जब तक देश आर्थिक रूप से मज़बूत नहीं हो जाता या कम से कम आर्थिक मंदी के दौर से निकल नहीं आता, तब तक सभी सांसद साधारण श्रेणी में यात्रा करेंगे. पैसे की बचत तो तभी हो पाएगी. यह क़दम दिखावटी ही सही, पर कांग्रेस ने उठाए तो, लेकिन इनका विरोध जिस तरह भाजपा ने किया, वह अच्छा नहीं लगा. बेहतर यह होता कि भाजपा कहती कि यह कांग्रेस का नाटक है और हम लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे कि सभी सांसद व मंत्री अब साधारण श्रेणी में यात्रा करने के साथ कुछ प्रतिशत वेतन भी कम लेंगे. लेकिन भाजपा यह करना नहीं चाहती या शायद उसकी सोच ही कहीं भटक गई है.

अगर सोच न भटकती तो भाजपा को जनता की महंगाई से त्रस्त ज़िंदगी नज़र आ जाती. प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते वह महंगाई को लेकर सरकार पर दबाव बनाती और देश में लोगों के पास जाती और कहती कि उन्होंने उसे चुनकर ग़लती की है. लेकिन भाजपा ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे के कारण तलाशने के लिए ज़्यादा दिमाग़ नहीं दौड़ाना पड़ेगा. सन नब्बे से पहले भाजपा व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी. नेतृत्व भले अटल जी व आडवाणी जी का था पर दल की नीतियों पर छाप व्यापारियों के हित वाली थी. नब्बे के बाद इसीलिए भाजपा को रोजी-रोटी शोषण, बीमारी नज़र नहीं आई, नज़र आया राममंदिर और बाबरी मस्जिद.

कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि आप एक्ज़ीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करें, हमें कोई परेशानी नहीं लेकिन एक बार आलू की क़ीमत पर नज़र डालिए. ये आलू देश के ग़रीब और खाना न तलाश पाने वाले अभागे लोगों का सहारा हुआ करता था, आज वह अमीरों की पहुंच बन गया है. दालें, आटा, मोटा अनाज एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आम आदमी की पहुंच में हो. सब्ज़ियां और फल तो उसकी पहुंच से महीनों पहले दूर जा चुके हैं. लिखते हुए तकलीफ़ होती है, लेकिन सच्चाई है कि बच्चों के मुंह से दूध भी दूर हो चुका है. नए पैदा हुए बच्चे मां के दूध से भी वंचित हो रहे हैं क्योंकि मां को शारीरिक पोषण ही नहीं मिल पा रहा है कि वह अपने ही पैदा किए बच्चे को पिलाने लायक़ दूध अपने शरीर में बना सके.

> विपक्ष का नेता शेर होता है जो दिन रात आम लोगों की तकलीफ़ों को लेकर सरकार पर गरजता रहता है तथा सरकार को मजबूर करता है कि वह आम लोगों के हितों को अनदेखा न करे, उनकी समस्याएं सुलझाए. लालकृष्ण आडवाणी का एक भी बयान या उनका एक भी इशारा इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, कहना ग़लत है. कहना चाहिए कि वे इस कसौटी के आस-पास भी नहीं हैं.

और अब शरद पवार, जिन्हें कृषि मंत्रालय शायद इसीलिए मिला है कि वे देश में महंगाई बढ़ाने में जमाखोरों की मदद करें. उनका बयान आया है कि चावल का,यानी धान का उत्पादन कम है. इसीलिए उसका भाव बढ़ने वाला है. उनका बयान आते ही चावल की क़ीमतों में देशव्यापी उछाल आया है. आप, जो यह लेख पढ़ रहे हैं,जब चावल लेने जाएंगे तो पाएंगे, कि भाव कल से ज़्यादा बढ़े हुए हैं. शरद पवार बयान न देते तो भी भाव, हो सकता है बढ़ते, लेकिन कुछ दिन बाद बढ़ते. शरद पवार का मुख्य काम देश में कृषि पैदावार को संतुलित बना उत्पादन बढ़ाना है लेकिन यह काम करने की उन्हें फ़ुर्सत कहां. चावल व्यापारियों के साथ खड़े पवार को कौन सीख देगा पता नहीं.

इस सरकार ने हिंदू, मुसलमान, ग़रीब खेतिहर, मेहनत कश जनता को बढ़ती महंगाई की जकड़ में पहुंचा दिया है. सरकार इससे लड़ती तो अच्छा लगता बजाय इसके कि ख़र्च बचाने के लिए बचकानी कवायद करने के. सरकार विश्वसनीयता खोने के कगार पर पहुंच रही है. वहीं अफ़सोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठने का दावा करने वाले लालकृष्ण आडवाणी की जुबान ख़ामोश है. उन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है. उनकी रणनीति आज भी हिंदू मुसलमान को बांट, हिंदू भावना भड़का दिल्ली पर क़ब्ज़ा करने की है. उन्होंने साबित कर दिया है कि वे प्रधानमंत्री के पद के लायक़ तो थे ही नहीं. नेता विरोधी दल के लायक़ भी नहीं है. विपक्ष का नेता शेर होता है जो दिन रात आम लोगों की तकलीफ़ों को लेकर सरकार पर गरजता रहता है तथा सरकार को मजबूर करता है कि वह आम लोगों के हितों को अनदेखा न करे, उनकी समस्याएं सुलझाए. लालकृष्ण आडवाणी का एक भी बयान या उनका एक भी इशारा इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, कहना ग़लत है. कहना चाहिए कि वे इस कसौटी के आसपास भी नहीं है.

पार्टी के नेता को पार्टी को सही दिशा में ले जाने की ज़िम्मेदारी का पालन करना चाहिए. पर जैसे वे दिशाहीन और आम आदमी से दूर हैं वैसा ही उन्होंने अपनी पार्टी को बना दिया है. इसीलिए भाजपा जनता की तकलीफ़ों से कभी परेशान ही नहीं होती. उसकी परेशानी के स्वर जब भी सुनने को मिलते हैं, जनता के दर्द से दूर, दर्द बढ़ाने वाले ही होते हैं. आंसू पोंछने की जगह ख़ून के आंसू लाने वाले होते हैं. भाजपा के संगठन सालों से हिंदू मुसलमान की पैरवी का आलाप कर रहे हैं जिन्हें अब लोग सुनना नहीं चाहते. वे ऐसी पार्टी चाहते हैं जो उनकी तकलीफ़ों को समझकर राजनीतिक मांगे करे और दबाव बढ़ाए. क्या कांग्रेस और भाजपा के कर्णधार आम आदमी की तकलीफ़ को समझने की कभी कोशिश करेंगे, यह सवालिया निशान है.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

यस सर नहीं, यस मैडम बोलिए

सौमित्र मोहन

हम हर साल महिलाओं की सुरक्षा और उनके कई सामाजिक हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं. इस ध्येय के लिए हमारा प्रयास कई मायनों में अच्छी तरह सफल भी रहा. लेडी गोडिवा से लेकर सत्तर के दशक में अमेरिका में प्रतीकात्मक तौर पर अंत:वस्त्र का परित्याग कर अपनी आज़ादी का इज़हार करने वाली आंदोलनरत महिलाएं तक वास्तव में अब अपने आप में परिपूर्ण हैं. आप भले यक़ीन करें या न करें, आज महिलाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई हैं. महारानी विक्टोरिया ने सिसिल रोड्स से एक सवाल पूछा, क्या आप महिलाओं को पसंद नहीं करते? इस पर सिसिल रोड्स का जवाब था, महिलाओं में जो सेक्स है उसे नापसंद करना कैसे मुमकिन है ?

और वाकई, महिलाओं के बग़ैर पुरुष हैं ही क्या? और जैसा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, दुर्लभ व सबसे दुर्लभ. आख़िर, इन सबके बावजूद महिलाओं में मां की ममता, क्लोनिंग और जन्म देने का विशेषाधिकार जो है. दरअसल, हम महिलाओं की सहृदयता के बग़ैर इस दुनिया में क़दम रख ही नहीं सकते. ज़रा ध्यान से सोचिए, यदि ईव ने सेब खाने की ज़िद नहीं की होती, तो हम अभी भी गार्डेन ऑफ इडेन के चारों ओर तरबूज खाते हुए चक्कर लगा रहे होते.

मैं एक नारीवादी (फेमनिस्ट) हूं, इस बात को लेकर एक दिन मेरी पत्नी से मेरी बहस हो गई. जब तक मैंने उन्हें यह साबित नहीं कर दिया, वह इसे मानने को तैयार ही नहीं थीं. मैंने उन्हें बताया, आज जेंडर और सेक्स के मायने बदल रहे हैं और इसी तरह वैवाहिक संबंध भी. आजकल समलैंगिक विवाह भी ख़ूब प्रचलन में हैं और ऐसे में यदि मैं एक महिला से शादी करता हूं तो यह मेरे नारीवादी होने का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? इसके बाद वह कुछ भी नहीं बोलीं. दरअसल, हर किसी की तरह मैंने भी अपनी स्नातक की डिग्री गंवाकर और पत्नी को मास्टर डिग्री हासिल करने में मदद कर वैवाहिक जीवन में क़दम रखा. आप यक़ीन करें या न करें, शादी के वक़्त मेरी पत्नी इतनी ख़ूबसूरत दिखती थीं कि मैं अक्सर यही महसूस करता था कि उन्हें प्यार करता रहूं और अब जबकि शादी के कई साल हो गए हैं, सोचता हूं कि मुझे अपनी पसंद पर अमल करना चाहिए था. किसी ने सही ही कहा है, मुझे लगता है कि आख़िरकार मैं कुंवारा हूं?

> एक ग़रीब आदमी यह कभी नहीं सोचता कि उसके फ़ैसले से किसी को कुछ फ़र्क़ भी पड़ता है, लेकिन पत्नी के फ़ैसले उसकी या किसी और की ज़िंदगी के लिए काफी अहम होते हैं. अहंकार उसे भ्रम में डाल देता है. आज भी मेरे मित्र और उनकी पत्नी दोनों अच्छी तरह साथ-साथ रहते हैं. मगर, दोनों के अपने-अपने तरीक़े हैं.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

यह मान्यता है कि ईव की जीन ग़रीब एडम की अतिरिक्त पसलियों से बनी थी और तभी से वह उन पसलियों के पिंजरे में क़ैद है. महिलाएं पुरुषों के बाद आईं. महिलाओं ने ही यह फ़ैसला किया कि हमें कौन-सी चीज़ खानी है, क्या पहनना है. मेरे कई अच्छे दोस्त बड़े ही दंभी अंदाज़ में कहते हैं कि वह अपने घर के मालिक हैं. बड़ी सावधानी के साथ वे यह भी बताते हैं कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए या नहीं या फिर सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम में होना चाहिए या नहीं. ऐसे सभी अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फ़ैसले वह स्वयं लेते हैं, जबकि घर में खाना क्या बनेगा, वह आज क्या पहनेंगे और किस समय क्या बोलना है, यह तय करने की ज़िम्मेदारी उन्होंने पत्नी पर छोड़ दी है.

एक ग़रीब आदमी यह कभी नहीं सोचता कि उसके फ़ैसले से किसी को कुछ फ़र्क़ भी पड़ता है, लेकिन पत्नी के फ़ैसले उसकी या किसी और की ज़िंदगी के लिए काफी अहम होते हैं. अहंकार उसे भ्रम में डाल देता है. आज भी मेरे मित्र और उनकी पत्नी दोनों अच्छी तरह साथ-साथ रहते हैं, लेकिन दोनों के अपने-अपने तरीक़े हैं. आप मानें या न मानें, आज महिलाओं का ज़माना है. पुराणों में उल्लेखित पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज (शायद ही हमने महिलाओं पर कभी हुक़्म चलाया) धीरे-धीरे मातृसत्तात्मक या महिला प्रधान समाज में बदलता जा रहा है. ऐसे समाज में महिलाएं ही वास्तव में शासक हैं. आज कई जगहों और क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिली हुई है. यहां तक कि उनके कतार में लगने की भी ख़ास व्यवस्था होती है. महिलाओं की ख़ास उपलब्धि के लिए महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है. क्या नहीं है उनके लिए हर जगह, हर मामले में सबसे आगे महिला. और, मेरा यक़ीन मानिए दूसरे पायदान पर तो वह हरगिज़ नहीं हैं. ऐसा कहा गया कि जब टाइटेनिक जहाज डूब रहा था तो जहाज के कप्तान ने भी सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को ही बचाने का काम किया. यही वजह है कि रोज़ बच गई और बेचारा जैक मारा गया. यही वजह है कि अमेरिकी हास्य कलाकार गिल्डा रैडनर जैसे लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह पुरुष की अपेक्षा महिला ही बनना चाहेंगे. महिलाएं रो सकती हैं, ख़ूबसूरत कपड़े पहन सकती हैं और किसी डूबते जहाज से सबसे पहले बचकर निकल भी सकती हैं.

ऐसा मानना है कि हर सफल आदमी के पीछे कोई न कोई महिला अवश्य ही होती है. लेकिन, ऐसा हमेशा लगता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है. यह आश्चर्य की बात है कि उच्छृंखल और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बावजूद वह उसे सफल देखकर भी काफी ख़ुश होती है. यह अच्छी तरह जानते हुए कि महिलाएं ग़लत दिशा में जा रही हैं, हम ठीक इसके उलट चलते हैं. आख़िरकार, दो अलग-अलग हिस्से महिला और पुरुष दो सेक्स में, वे हमारा बेहतर अधूरा हिस्सा हैं. हम पुरुष, महिलाओं के मोहपाश में बंधे हुए हैं. हम हमेशा महिलाओं के पीछे भागते रहते हैं और उसकी साज़िश के जाल में बर्बाद होने की हद तक फंसते चले जाते हैं. हम पूरे महीने पागलों की तरह काम करते हैं और महीने के अंत में उसके प्रेम और करुणा में बहकर सारी कमाई उसे सौंप देते हैं. उसके बाद पूरे महीने अपने गुज़ारे के लिए उसकी ओर टकटकी लगाकर कातर निगाहों से देखते रहते हैं.

वास्तव में हमेशा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अनावश्यक लाभ मिलता है. स्मार्ट होने के बावजूद अगर वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकतीं, तो बेवकूफ़ होने पर भी उन्हें यह सब नहीं मिल सकता. महिलाओं के सबसे बड़े प्रशंसक पुरुष ही हैं, कोई और नहीं, यह उनके ख़र्च के बिल से भी साबित होता है. वास्तव में यदि महिलाएं नहीं होती तो दुनिया में पैसे का कोई मतलब ही नहीं होता. और आप किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध नहीं रह सकते. वह कभी आपसे सलाह-मशविरा भी नहीं करेंगी और वह ऐसा करे भी क्यों? आख़िरकार सलाह कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, जिसे वह शाम को पहन कर घूम सके. पुरुषों को बर्बाद करने की महिलाओं की अदा से जेफरी बर्नार्ड काफी आतंकित थे. उन्होंने यह मांग की कि महिलाओं को अपने माथे पर एक लेबल लगाना चाहिए, जिस पर सरकारी स्वास्थ्य चेतावनी के रूप में यह लिखा हो कि महिलाएं आपके दिमाग़, गुप्तांग, बैंक बैलेंस, विश्वास और दोस्ती को बुरी तरह नुक़सान पहुंचा सकती हैं.

ऐसी महिलाएं बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं, जो अपनी सही उम्र बताती हों. यदि बताती भी हैं तो सिर्फ़ दो हालात में. या तो कुछ गंवाने के लिहाज से वह काफी छोटी हैं, या फिर इतनी उम्रदराज कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकतीं. दरअसल, कोई महिला अपनी सही उम्र बताती है तो उस पर यक़ीन नहीं करना चाहिए. इसकी वजह यह है कि वह बेपरवाही से सब कुछ छुपाते हुए भी, कुछ भी और सब कुछ बता सकती है. महिलाओं की उम्र छिपाने की यही कला उन्हें संख्या और गणित के लिहाज़ से दिलचस्प बनाती है. वे अपनी उम्र वास्तविक उम्र से हमेशा आधी, अपनी पोशाक की क़ीमत दोगुनी और सबसे अच्छी दोस्त की उम्र उसकी वास्तविक उम्र से पांच साल ज़्यादा बताती हैं.

एक बच्चे के रूप में, मैं हमेशा यह सोचकर हैरान होता था कि सारे त्योहार पुरुषों के हिसाब से क्यों नहीं बनाए गए हैं? महिलाओं की तरह हम भी पैसा कमाते. राखी और भैयादूज के अवसर पर एक दिन पहले ही पूरे भारत में सभी बहनें पैसा लेने और अपनी पूरी ज़िंदगी की रक्षा के वादे के लिए जमा हो जाती हैं. इस तरह महिलाओं की रक्षा के लिए उनके शौहर, भाई, समाज और अब तो सरकार भी उनके साथ है. जबकि मानवता पूरी तरह असुरक्षित है. वे आज सही में विलुप्तप्राय: प्रजाति है. आज इस अधूरे और बेहतर हिस्से की रक्षा के लिए कई क़ायदे क़ानून हैं, लेकिन सबसे बुरे अधूरे हिस्से यानी पुरुषों के लिए ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं है.

पुरुष हमेशा से महिलाओं के आकर्षण में बंधे रहे हैं. आख़िर, आकर्षित होकर उसे हासिल करना ही तो उससे मोहमुक्त होने का सबसे बेहतर ज़रिया है. पुरुषों की दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद महिलाएं अपना रास्ता निकाल लेती हैं. हम उन्हें चाहे जितना भी बेवकूफ़ समझते हों, यदि ऐसी न हों तो वह हमसे कभी शादी नहीं करेंगी और आप मुझे एक बात बताइए, हम कई स्मार्ट लड़कों को बेवकूफ़ महिलाओं के साथ देखते हैं, लेकिन कितनी बार एक स्मार्ट लड़की को बेवकूफ़ लड़कों के साथ देखते हैं? आप मानें या न मानें, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सोच स्पष्ट है. इसीलिए वह इसे अक्सर बदलती रहती हैं. एक सर्वे के मुताबिक़, 85 फ़ीसदी महिलाएं सोचती हैं कि उनके पति ज़्यादा दिखावटी हैं. दस फ़ीसदी के मुताबिक़, उनके पति उसके क़ाबिल नहीं हैं. जबकि बाक़ी 5 फ़ीसदी सोचती हैं कि वे अपने पति से प्यार नहीं करतीं, बस शादी कर ली है.

(लेखक प. बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

इज़रायल की यह ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद अपने सभी मिशन को अंजाम तेल अवीव स्थित मुख्यालय से देता है.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

इज़रायल का ख़ुफ़िया आतंक

मोसाद का आग़ाज़

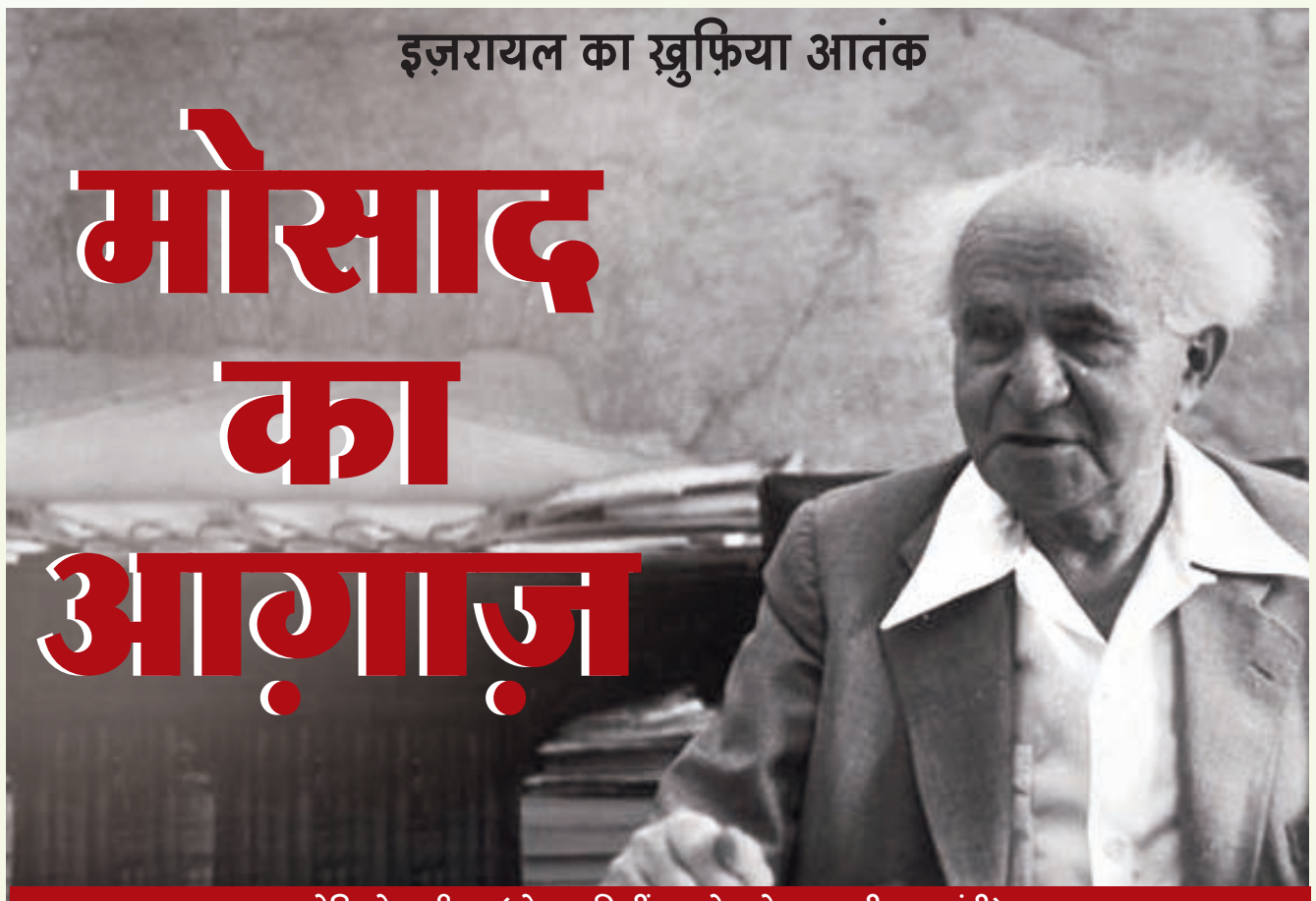

डेविड बेन गुरियन (मोसाद की नींव रखने वाले इज़रायली प्रधानमंत्री)

इज़रायल की ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद के बारे में इतना कहना ही काफी होगा कि सिर्फ़ भगवान ही सब कुछ जानता है और वह मोसाद के लिए काम करता है. ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे. इसका सबूत है मोसाद के कारनामे, जिसने पूरी दुनिया को ऐसा कहने पर मज़बूर कर दिया.

15 मई, 1948 को ब्रिटिश हुकूमत से मिली आज़ादी के बाद भी इज़रायल पर अरबों का हमला जारी रहा. इस तरह अरबों से सुरक्षा और इज़रायल की संप्रभुता को बरक़रार रखना एक चुनौती से कम नहीं था. हालांकि इज़रायल के आज़ाद देश के तौर पर अस्तित्व में आने से पहले कई यहूदी ख़ुफ़िया और गुप्त संगठन थे, जिन्हें अपने विरोधियों से निपटने के लिए ख़ुफ़िया सूचनाओं की ज़रूरत होती थी. इनका मक़सद था यहूदियों को अरबों के आतंक से बचाना. राज्य बनने की घोषणा और अरबों के बर्बर रवैये ने एक नई ख़ुफ़िया एजेंसी की ज़रूरत को जन्म दिया. ज़रूरत नए ख़ुफ़िया तंत्र को विकसित करने की, ताकि इसकी संप्रभुता को क़ायम रखा जा सके. इन्हीं सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुलाई 1949 में इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद ने इस दुनिया में पहली बार क़दम रखा. शुरुआती समय में इसने विदेश मंत्रालय के तहत काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही इसकी कमान प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई. अपने ख़ुफ़िया कारनामों की वजह से ही यह दुनिया की सबसे बेहतरीन और शातिर ख़ुफ़िया एजेंसियों में शुमार होने लगा. मोसाद ने धीरे–धीरे हर मुल्क़ में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए. ऐसा कोई देश नहीं, जहां मोसाद के एजेंट मौजूद न हों. अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश– जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नार्वे और रूस तक. इन सभी देशों में इसके ख़ुफ़िया एजेंटों ने अपनी पकड़ काफी मज़बूत बना ली है. कई देशों में तो मोसाद के कारनामे ही इसकी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए काफी है. मसलन, नाज़ी युद्ध के अपराधी एडोल्फ इक़मैन को मोसाद ने अर्जेंटीना से खोज निकाला, तो वहीं बैलेस्टिक एक्सपर्ट गेराल्ड बुल की बेल्जियम में हत्या के पीछे मोसाद को ही ज़िम्मेदार माना जाता है.

15 मई, 1948 को ब्रिटिश हुकूमत से मिली आज़ादी के बाद भी इज़रायल पर अरबों का हमला जारी रहा. इस तरह अरबों से सुरक्षा और इज़रायल की संप्रभुता को बरक़रार रखना एक चुनौती से कम नहीं था. हालांकि, इज़रायल के आज़ाद देश के तौर पर अस्तित्व में आने से पहले कई यहूदी ख़ुफ़िया और गुप्त संगठन थे, जिन्हें अपने विरोधियों से निपटने के लिए ख़ुफ़िया सूचनाओं की ज़रूरत होती थी.

जर्मनी में नाज़ी युद्ध अपराधियों के ख़िलाफ़ मोसाद का अभियान भी जगज़ाहिर ही है. मोसाद के बारे में यहां तक कहा जाता है कि एक बार उसके निशाने पर आने के बाद दुश्मनों का ख़ात्मा तय है और उसने इसे साबित भी किया. ब्लैक सितंबर के सदस्य अली हसन सालमेह की तलाश में नार्वे के होटल में एक वेटर की हत्या बताती है कि मोसाद की मौजूदगी हर जगह है. मध्य–पूर्व के देशों में मिस्र और ईरान में तो वह साठ के दशक से ही सक्रिय है. जब शाह के शासन को बरक़रार रखने के लिए उसने सीआईए के साथ मिलकर वामपंथियों के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम छेड़ी थी.

वहीं इराक के परमाणु हथियार बनाने के मंसूबों पर पानी फेरने वाला और कोई नहीं मोसाद ही था. जबकि फिलीस्तीन के ख़िलाफ़ इसकी मुहिम तो सबसे ख़तरनाक दौर में है और इसमें मोसाद की भूमिका आए दिन सुर्ख़ियों में बनी रहती है. लेबनान और सीरिया के विरुद्ध मोसाद की जंग सबसे पुरानी है और मोसाद ने कुख्यात ब्लैक सेप्टेंबर के सरगना अली हसन सालमेह को लेबनान में ही एक साज़िश के तहत कार बम ब्लास्ट में मार डाला था. सीरिया में मोसाद की पहुंच यहां तक थी कि सीरिया के राष्ट्रपति के क़रीबी को ही उसने अपना जासूस बना लिया था, जो बाद में रक्षा मंत्री पद का दावेदार भी बना. इस तरह देखा जाए तो मोसाद अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कहीं भी और कुछ भी कर सकता है. ऐसा नहीं है कि मोसाद के अड्डे इन्हीं देशों तक सिमटे हुए हैं. भारत और पाकिस्तान में भी इसने अपनी जड़ें इतनी मज़बूत कर ली हैं कि दोनों देशों की ख़ुफ़िया एजेंसियों को जो बात पता नहीं होती, उससे जुड़ी जानकारी मोसाद के पास होती है. यहां तक कि पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई ने ख़ुद लीबिया, सीरिया, जॉर्डन और सउदी अरब की कई ख़ुफ़िया जानकारियां हासिल करने में मोसाद की मदद की. इसके अलावा मोसाद का जाल अफ्रीकी देशों से लेकर न्यूज़ीलैंड तक भी फैला हुआ है. यदि मोसाद के बारे में कहा जाए कि वह दुनिया के चप्पे–चप्पे में मौजूद है और कोई भी ख़ुफ़िया जानकारी उसकी पहुंच से दूर नहीं तो कतई ग़लत नहीं होगा.

इज़रायल की यह ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद, अपने सभी मिशन को अंजाम तेल अवीव स्थित मुख्यालय से देता है, जिसके लगभग 1500 एजेंट दुनिया के हर देश में मौजूद हैं.

मोसाद का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने किया था. शुरुआत में इसके निदेशकों की जानकारी गुप्त रखी जाती थी, लेकिन 1996 में फिलीस्तीनी संगठन हमास के एक बड़े नेता की हत्या में मोसाद के असफल होने की वजह ने इज़रायल में इस पर कई सवाल उठने लगे. तभी से निदेशकों की जानकारी भी आम होने लगी. ग़ौरतलब है कि मोसाद में कुल आठ विभाग हैं, जिनके ज़रिए वह अपने कारनामों को अंजाम देता है. इनमें पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट, जो दूसरे देशों से राजनयिक और ग़ैर–राजनयिक सूचनाओं को इकट्ठा करता है.

दूसरा है पॉलिटकल और लायज़न विभाग का, जो दूसरे देशों की ख़ुफ़िया एजेंसियों से सूचनाओं की लेनदेन करता है. जबकि तीसरा स्पेशल ऑपरेशन डिविज़न, जिसे मेत्स्दा भी कहा जाता है यह राजनीतिक हत्याओं, मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे सनसनीख़ेज वारदातों को अंजाम देता है. रिसर्च डिपार्टमेंट सभी तरह की सूचनाओं को हासिल करता है, जिससे मोसाद को अपने मिशन को अंजाम देने में सहूलियत होती है. इसके अलावा बाक़ी विभाग सहयोगी के तौर पर काम करते हैं. इस तरह मोसाद ने अपने मिशन का आग़ाज़ किया. सबसे पहले इसने अपनी ताक़त को बढ़ाया. फिर पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया. और, अब अपने कारनामों की बदौलत सबसे क़ाबिल, शातिर और ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसियों में शुमार होता है. जिसकी निगाह से किसी भी ख़ुफ़िया सूचना का बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

बादल भी नक़ली होंगे

वैज्ञानिकों ने रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष की सतह पर यह जानने के लिए कृत्रिम बादल का निर्माण किया है कि ऊंचाई पर उड़ने वाले धूल कण किस तरह रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देते हैं. नोटील्यूसेंट या रात में चमकने वाले बादल सामान्य ऊंचाई पर तैरने वाले बादलों की तुलना में दर्जनों किलोमीटर अधिक ऊंचाई पर तैरते हैं. क़रीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसे क्षितिज के नीचे प्रकाशित करता है, इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर यह चमकीला प्रतीत होता है.

हाल के वर्षों में इन बादलों का विस्तार 40 डिग्री नीचे तक हो गया है और इनकी मात्रा और चमक में लगातार वृद्धि होती जा रही है. इस बदलाव की वजह बहुत हद तक बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है. ये बादल बर्फ से ढके होते हैं. आमतौर पर इसका निर्माण छोटे–छोटे कणों से होता है जो इलेक्ट्रॉन और आयन से आवेशित होते हैं. आवेशित कण ही रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं. रडार अध्ययनों के लिए इसे काफी उपयुक्त माना जाता है.

बादल बनने के शुरुआत में धूल कणों को मापने में इससे काफी मदद मिल सकती है. लेकिन रडार के डाटा को समझना कठिन होता है. काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले धूल कण रेडियो तरंगों को किस तरह परावर्तित करते हैं, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने हाल ही में नासा के वालॉपस फ्लाइट फैसिलिटी, वर्जिनिया से चार्ज्ड एरोसेल रिलीज़ एक्सपेरिमेंट (सीएआरई) लांच किया है.

यह प्रयोग ब्लैक ब्रांट–12 उपकक्षीय रॉकेट के जरिये किया जा रहा है. धरती से तक़रीबन 280 किलोमीटर की ऊंचाई पर इससे वातावरण में 100 किलोग्राम से अधिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड छोड़ा जा रहा है. पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों ही जगहों से उपकरण के जरिये बादलों को कई दिनों, बल्कि कई माह तक परीक्षण किया जाएगा.

जब इसका कण आवेशित होने के बाद संकुचित होकर अंत में विलीन

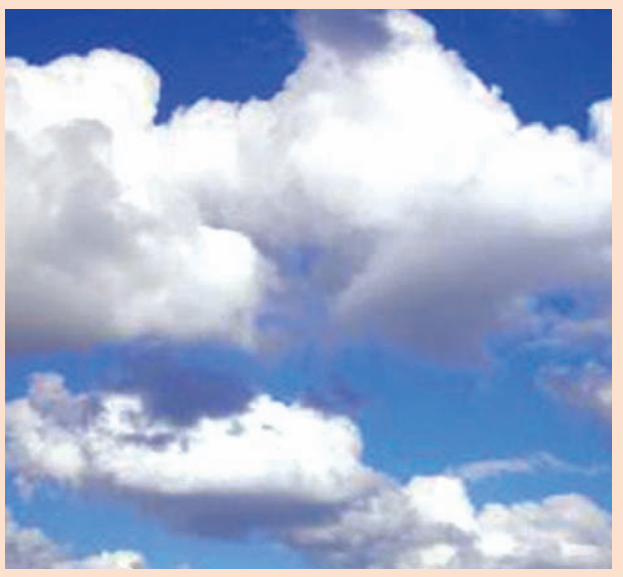

हो जाएगा. लेसर संकेत का इस्तेमाल बादल के कण का घनत्व मापने में किया जाएगा. इसकी बादलों के रडार द्वारा की गई पैमाइश से तुलना की जाएगी. नेवेल रिसर्च लैबोरेटरी वाशिंगटन डीसी स्थित सीएआरई के मुख्य अनुसंधानकर्ता, के पाउल बेहैर्ड के मुताबिक़, हमारा प्राथमिक लक्ष्य धूलयुक्त प्लाज्मा से रडार के अलग होने की प्रक्रिया को समझना है. हम यह समझना चाहते हैं कि जब आप रडार से संकेत भेजते हैं तो आपको किस तरह की जानकारी मिलती है. ब्लैक्सवर्ग के वर्जिनिया टेक के स्कॉट बैले के मुताबिक़, रडार का उपयोग बर्फीले धूल को जांचने के लिए किया जाता है, जो पृथ्वी से 90 किलोमीटर पर चक्कर लगाता रहता है और यह नोटील्यूसेंट बादलों में बर्फ के कणों को बढ़ा भी सकता है.

मोतियाबिंद का इलाज आसान होगा

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सेनडियागो स्कूल ऑफ मेडिसिन और नेशनल आई इंस्टीट्यूट के शोधकर्त्ताओं के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मोतियाबिंद (ग्लूकोमा) का जीन संस्करण खोजने का दावा किया है. भविष्य में इसका उपयोग इलाज के दौरान किया जा सकता है. यह अध्ययन, यूसी सैन डियागो के शीले आई सेंटर, इंस्टीट्यूट फॉर जेनोमिक मेडिसिन के निदेशक और नेत्र विज्ञान व मानव आनुवांशिकी के प्रोफेसर जांग कांग तथा जे फिल्डिंग हेज्टमैनिक और नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मॉल्यूकूलर जेनेटिक सेक्शन के चीफ और अमेरिका में बारबाडोस फैमिली स्टडी ग्रुप व उसके सहयोगियों ने साथ मिलकर किया है. हालांकि, चीन और बारबाडोस पहले ही इसे ऑन लाइन संस्करण में प्रकाशित कर चुका है.

द साइलेंट थीफ ऑफ साइट के तौर पर जाना जाने वाला मोतियाबिंद दिमाग़ की बीमारी है. इससे रेटिना की गैंगलिन (नाड़ी ग्रंथि) कोशिकाओं की मौत हो जाती है. परिणाम स्वरूप दृष्टि धीरे–धीरे कम होने लगती है और बाद में अंधापन स्थायी रूप ले लेता है. आंतरिक दबाव कम होने से अंधेपन की गति कम हो सकती है. लेकिन मोतियाबिंद को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है.

यूसी सैन डियागो में नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर और हैमिल्टन ग्लूकोमा सेंटर के निदेशक राबर्ट वेनरब के मुताबिक़, मोतियाबिंद के कारणों और उसकी प्रगति को सही तरीक़े से समझा नहीं गया है. हालांकि, हम यह जानते हैं कि यह रोग वंशानुगत भी होते हैं. झांग कहते हैं– हमने एक ऐसे सामान्य आनुवांशिक विकल्प की पहचान कर ली है जिसका किसी व्यक्ति के ग्लूकोमा के विकास पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है.

मोतियाबिंद के शिकार 294 मरीजों और 128 नियंत्रण विषय को देखते हुए यह शोध पूर्व के शोध के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें संपूर्ण मानव जीनोम सम्मिलित हैं. उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे मानव जीनोम के एक विशेष हिस्से में रखा और अंत में इस जीन का स्थान गुणसूत्र दो रखा. झांग के मुताबिक़, यह विशिष्ट जीन और प्रोटीन बीमारी से मिल गया, तो शोधकर्ता जीन या स्टेम सेल को विकसित करने के बिल्कुल क़रीब होंगे. और तब मोतियाबिंद का इलाज करना भी संभव हो पाएगा.

सब गोलमाल है

शायद आपने ये कहावत सुनी होगी कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया. जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और चीन में. आम इंसान से लेकर कारोबारी तक को सरकारी से लेकर ग़ैर–सरकारी कार्यालय में रिश्वत देनी पड़ती है. यह कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जो पूरे विश्व में भ्रष्टाचार पर निगाह रखती है. रिपोर्ट के अनुसार, एशिया क्षेत्र में इसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत और चीन दुनिया के बड़े बाज़ारों में शुमार हैं. मगर, विदेश में व्यवसाय के मामले में इन दोनों देशों की कंपनियों को बहुत ही भ्रष्ट समझा जाता है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में 30 फ़ीसदी लोगों का कहना था कि अपना काम जल्दी करवाने के लिए भारतीय कंपनियां अधिकारियों को रिश्वत देना पसंद करती हैं. एशियाई क्षेत्र के देशों के लिए जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हो गई हैं. पाकिस्तान में इस सर्वे में भाग लेने वाले 60 प्रतिशत अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कई सरकारी संस्थानों को रिश्वत दी है. हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत की तारीफ़ की है कि सेबी (प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ठोस क़दम उठा रहा है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में माना कि भ्रष्टाचार से आर्थिक प्रगति रूक जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक़, विकासशील देशों में बहुत–सी कंपनियों ने भ्रष्ट राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से एक वर्ष में लगभग 40 अरब डॉलर की घूसखोरी की है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्यों विफल हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता? अब हाफ़िज़ सईद का क्या होगा?

सभी फोटो– पीटीआई

हाफ़िज़ सईद और पाकिस्तान की मजबूरी

मनीष कुमार

साउथ अफ्रीका में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था और न्यूयॉर्क में दोनों देशों के राजनयिकों की बैठक हो रही थी. क्रिकेट मैच से पहले टेलीविजन एंकर मूर्खों की तरह दिन भर चिल्लाते रहे. वे मैच को कुछ इस तरह पेश कर रहे थे मानो उनके बीच क्रिकेट का मैच नहीं, सीमा पर युद्ध हो रहा हो. इस मैच में भारत की टीम हार गई, लेकिन न्यूयॉर्क में हुई बैठक का नतीजा वही निकला, जो पहले से तय था. बातचीत असफल रही. दोनों देश अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे. भारत चाहता है कि पाकिस्तान मुंबई के आतंकी पर कार्रवाई करे, वहीं पाकिस्तान ने फिर अपना पुराना राग अलापा- सबूत पर्याप्त नहीं हैं. मुंबई हमले के ज़िम्मेदार आतंकी और आतंकवाद से जिस तरह भारत और पाकिस्तान की सरकारें निपट रही हैं, उससे आंतकियों को एक ही संदेश मिला है – भारत और पाकिस्तान में धमाके पर धमाके करते जाओ. यहां की जनता का ख़ून सस्ता है और यहां पकड़े जाने का कोई ख़तरा नहीं है.

प्रजातंत्र की ख़ूबियां हैं तो उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं. फ़िलहाल पाकिस्तान में भी प्रजातंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार है. भारतवासियों की तरह ही आम पाकिस्तानी अमन और शांति चाहता है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है. पाकिस्तान की सरकार एक कमज़ोर सरकार है. सेना और आईएसआई इनकी पकड़ से बाहर हैं. यह ऐसी ख़तरनाक स्थिति है कि जिससे निपटने में ही सरकार उलझ गई है. उन्हें इस बात का डर है कि अगर आतंकियों और इस्लाम के नाम पर ज़हर घोलने वालों के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठता है तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के जैसा माहौल बन सकता है. भारत की सरकार कमोबेश ऐसी ही दुविधा में है. मुंबई के गुनहगारों को लेकर रवैया इतना सख्त इसलिए भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं. अगर सरकार कोई नरम रवैया अपनाती है तो वह विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ जाएगी.

पाकिस्तान की राजनीति पंजाबियत और इस्लाम की दो धुरियों के इर्द-गिर्द घूमती है. पाकिस्तान में सेना हो, व्यापार हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, इन सब पर पंजाबियों का क़ब्ज़ा है. पाकिस्तान में चल रहे अलग-अलग आंदोलन, दरअसल पंजाबियों के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा है. जैसे कि बलूचिस्तान के लोग अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ़ पंजाबियों के हित में सोचती है. पाकिस्तान के सरकारी तंत्र और संगठित क्षेत्रों पर पंजाबियों का एकाधिकार है, तो पाकिस्तान के समाज पर मौलाना और मौलवियों की मज़बूत पकड़ है.

पाकिस्तान में धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की अपनी ताक़त है. इन नेताओं को जनरल ज़िया के शासनकाल के दौरान हर तरह की मदद दी गई . वे ताक़तवर बन गए. आज यही लोग पाकिस्तान के धार्मिक लोगों का नेतृत्व करते हैं. ये लोग सीधे राजनीति से जुड़े हुए नहीं है. ये चुनाव नहीं लड़ते. मीडिया के सामने बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जनता पर इनकी पकड़ इतनी मज़बूत है कि सरकार इनके ख़िलाफ़ कुछ भी करने से हिचकिचाती है. इस वर्ग के नेताओं में हाफ़िज़ सईद का नाम सबसे ऊपर है.

हाफ़िज मोहम्मद सईद जमात-उद-दवा का आमिर यानी अध्यक्ष है. हाफ़िज़ सईद एक पंजाबी गूजर है. वह मियांवली ज़िले के जनुबी गांव का रहने वाला है. 1947 में आज़ादी के बाद हाफ़िज़ का परिवार शिमला से लाहौर आया. इस दौरान इसके परिवार के 36 लोगों की मौत हुई थी. हाफ़ि ज़ सईद ने साइंस के साथ-साथ सउदी अरब में इस्लामिक तालीम ली. सईद को जनरल ज़िया ने कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और लाहौर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति दी थी. पाकिस्तानी महकमे के साथ-साथ उसके ताल्लुकात सउदी अरब के इस्लामिक संगठनों से भी है. हाफ़िज़ सईद के आतंक का इतिहास भी पुराना है. 1990 में सईद ने लश्कर-ए-तैय्यबा का गठन किया. लश्कर के बारे में पाकिस्तान के अधिकारी भी कहते हैं कि लश्कर सउदी के पैसे और आईएसआई के संरक्षण में चलने वाला संगठन है. जब उस पर प्रतिबंध लगा तो उसने जमात-उद-दवा के नाम से अपना संगठन चलाना शुरू कर दिया. हैरानी की बात यह है कि इस संगठन का आतंकियों के साथ रिश्ता है, इसके बावजूद जमात-उद-दवा को एक एनजीओ मान कर पाकिस्तान की सरकार ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के नाम पर उसे करोड़ों रुपए दिए. पाकिस्तान में मीडिया रिपोर्ट छापती रही, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी चेतावनी देते रहे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने जमात-उद-दवा के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की. हाफ़िज़ सईद की न सिर्फ़ पाकिस्तान के सरकारी तंत्र पर पकड़ है, बल्कि वह उन्हें इस्तेमाल करना भी जानता है. वह अपनी इस ताक़त से वाक़िफ़ है कि अगर भारत में हुए हमले में नाम पर, उस पर कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान सरकार की साख ख़त्म हो जाएगी. उस पर यह आरोप लगेगा कि यह सरकार अमेरिका और भारत के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन गई है. हाफ़िज़ सईद का एक साथ पंजाबी और जिहादी होना ही पाकिस्तान की सरकार के लिए दुविधा पैदा करती है. यही वजह है कि भारत में हुए किसी आंतकी हमले के मामले में पाकिस्तान की सरकार हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती. अब सवाल यह है कि क्या हाफ़िज़ सईद नाम का शख्स इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से परमाणु हथियारों से लैस दो देश संवादहीनता की स्थिति में आ जाए. पाकिस्तान की मजबूरियां जगज़ाहिर हैं. इसके बावजूद अगर भारत अपनी जगह पर अड़ा रहता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या भारत की सरकार हाफ़िज़ सईद के लिए अपने पड़ोसी से हमेशा के लिए बातचीत बंद कर देगी या फिर भारत का यह रुख़ सिर्फ़ महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनाव तक के लिए सीमित है? मुंबई के आंतकियों के मामले में क्या दोनों देशों की सरकारें अपनी-अपनी जनता को गुमराह कर रही हैं?

मुंबई हमले ने आंतकियों की पाकिस्तानी तंत्र में पैठ और दोनों देशों की मजबूरियों को उजागर किया है. मीडिया के भड़काने वाले रवैये से ऐसा महौल बन गया है कि दोनों देशों के सरकार की बुद्धि भी मंद पड़ गई है. सरहद के दोनों तरफ़ अमनपसंद लोग भी बैकफुट पर आ गए हैं. दक्षिण एशिया में अगर आतंक के ख़िलाफ़ कोई ठोस लड़ाई लड़नी है तो भारत और पाकिस्तान की सरकारों को एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझना पड़ेगा और उसी के मद्देनज़र उपाय भी निकालने होंगे. दोनों देश आपस में लड़ते रहें, उनके बीच संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाए, हैरानी की बात यह है कि आतंकवादी संगठन भी यही चाहते हैं. और दोनों देशों की सरकारें बड़ी निर्लज्जता से आतंकवाद से लड़ने के नाम पर यह काम कर रही हैं.

manish@chauthiduniya.com

जिहादी तालीम की सरज़मीं

आयशा सिद्दीका

कुछ साल पहले की बात है. बहावलपुर के पास मेरी मुलाक़ात अपने गांव के कुछ ऐसे युवाओं से हुई जो जिहाद की तैयारी कर रहे थे. मैंने उन्हें अपनी आंखें बंद कर अपना भविष्य देखने की सलाह दी. बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने इस अनुरोध को टाल दिया और कहा कि वे खुली आंखों से कुछ भी नहीं देख रहे हैं. इसमें ज़्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं है. दक्षिण पंजाब का यह इलाक़ा ग़रीबी और पिछड़ेपन का शिकार है. यहां नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं हैं. सरकार के बनवाए हवाई अड्डे और अस्पताल बस नाम भर के हैं और इससे इलाक़े के लोगों की ज़रूरतें हल नहीं होतीं. ग़रीबी और निराशा के बीच यह जगह धार्मिक कट्टरपंथ के पनपने के लिए उपजाऊ ज़मीन साबित होती है. आतंकवाद की सबसे पहली ज़रूरत लड़ाकों की भर्ती है, और इस भर्ती का सीधा रास्ता भी है. ऐसे गांवों से कम उम्र के बच्चे, यहां तक कि उम्रदराज़ लोग भी, नज़दीकी शहर के मदरसों में लाए जा रहे हैं. इन मदरसों में उनके बेहतर खानपान और रहने आदि की व्यवस्था की जाती है. वे ऐसी सुविधाओं के अभ्यस्त नहीं होते. यह सबकुछ एक रणनीति के तहत किया जाता है, जिसे आतंकवादी संगठन अंजाम देते हैं. उनकी कोशिश उन मासूम बच्चों को मदरसों में इकट्ठा कर उन्हें ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की होती है जो उन्हें अपने घरों में नसीब नहीं होती. इस रणनीति का मक़सद मासूम बच्चों को घर पर उपलब्ध सुविधाओं की तुलना आतंकवादी संगठनों द्वारा दी जा रही सुविधाओं को बेहतर मानने के लिए मजबूर करना है ताकि ख़ुशी-ख़ुशी वे अपने घरों को छोड़ने को तैयार रहें. मेरी मुलाक़ात मदरसा से वापस घर लौट रहे ऐसे युवकों से ही हुई थी, जिन्हें वापस मदरसों में लाकर एक निश्चित विचारधारा से बांध दिया जाता है. जिन लोगों को आतंकवाद की इस विचारधारा में उतार लिया जाता है, वे अपने साथ दोस्तों और रिश्तेदारों को भी लेकर मदरसों में आते हैं. यह एक सतत प्रक्रिया है और इसके ज़रिए ऐसे मदरसों में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

पंजाब में ऐसे मदरसों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है, जो नौजवान इस्लामिक जिहादियों की फ़ौज तैयार कर रही है. यह फ़ौज हर वक़्त शहादत के लिए तैयार रहता है. वास्तव में, दक्षिण पंजाब आज जिहाद का गढ़ बन चुका है. इसके बावजूद, आज पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस ख़तरे को मानने से इंकार कर रहे हैं. दक्षिण पंजाब में सभी चार बड़े आतंकवादी संगठन सिपह-ए-सहाब पाकिस्तान (एसएसपी), लश्कर-ए-झांगवी (एलइजे), जैश-ए-मोहम्मद (जेइएम) और लश्कर-ए-तैय्यबा (एलइटी) बड़ी आसानी से मौजूद हैं. सूत्रों के मुताबिक़, दक्षिणी पंजाब के लगभग 5000 से 9000 युवक अफ़ग़ानिस्तान और वजीरीस्तान में जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं. मशहूर पाकिस्तानी शोधकर्ता हसन अब्बास की मानें तो वज़ीरीस्तान में ही यह आंकड़ा 2000 है. यह इलाक़ा पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी वारदातों की वजह से किसी भी योजना, रोज़गार और सहायता पहुंचाने के लिहाज से काफी संवेदनशील बन चुका है. इस पर कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 1989 में जिस फ़ौज ने ख़ोस्त पर फ़तह हासिल की थी, उसमें कई दक्षिणी पंजाब के भी कमांडर थे, जिन्होंने गुलबुद्दीन हिक्मतयार और बुरहानुद्दीन रब्बानी जैसे कई अफ़ग़ान सरदारों की सेना के लिए लड़ा था. और आज भी, ये सभी चारों बड़े संगठन अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद हैं.

यह सच्चाई पाकिस्तान सरकार या फिर सेना से छुपी नहीं हैं. कुछ ही दिन पहले आंतरिक रक्षा मंत्री रहमान मलिक ने दक्षिण पंजाब की तुलना स्वात घाटी से की. रहमान मलिक के बयान को पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ने सिरे से ख़ारिज़ कर दिया था. शायद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मंशा अपने सीनियर के बयान का खंडन करना नहीं था, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स (एनवाईटी) की सबरीना तवरनीज़ की उस रिपोर्ट को चुनौती ज़रूर दे रहे थे जिसमें दक्षिण पंजाब, ख़ासतौर पर डेरा ग़ाज़ी ख़ान में जिहाद के बारे में ज़िक्र किया गया था. द न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट देश के बाहर भी मीडिया में ख़ासी चर्चा में बनी रही. यह सबकी समझ से बाहर था कि दक्षिण पंजाब का भी नाम अब स्वात के साथ लिया जा रहा है. इसलिए नहीं कि वहां हिंसा अधिक है, बल्कि इसलिए कि आतंकवादियों की पंजाब में मौजूदगी का मक़सद समाज और राज्य को एक अलग ही दिशा में ले जाना है.

लेखिका पाकिस्तान की स्वतंत्र सुरक्षा विश्लेषक हैं

feedback@chauthiduniya.com

कमज़ोर स्मरणशक्ति किसी शख्स की क्षमता के स्तर और उपलब्धि के बीच विरोध पैदा करती है. यह एक खतरनाक स्थिति है.

दिल्ली, 5-11 अक्टूबर 2009
चौथी दुनिया

क्या आपका बच्चा भुलक्कड़ है

आपने बहुचर्चित फिल्म 'तारे ज़मीं पर' देखी होगी, जिसमें नायक एक अजीबो-ग़रीब बीमारी से पीड़ित था. दरअसल, याददाश्त कमज़ोर होना कोई मामूली विकार नहीं है. चिकित्सा विज्ञान में इसकी कई शाखाओं का उल्लेख मिलता है. डॉक्टरों का मानना है कि यह बीमारी बड़ों की तुलना में बच्चों को ज्यादा अपना शिकार बनाती है.

रीतिका सोनाली

किसी भी प्रकार की स्मरण अयोग्यता व्यक्ति में क्षमता के स्तर और उपलब्धि के बीच विरोध उत्पन्न करती है. यह एक न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्था है, जिससे व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित होता है. यह अक्षमता पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, सवाल हल करने और गणित के प्रयोग में प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है. अमूमन स्मरण अयोग्यता छोटे बच्चों में पाई जाती है. माता-पिता व शिक्षक जानकारी न होने की वजह से बच्चों के साथ ग़लत व्यवहार करते हैं, जो कि उनके मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है. ऐसे में बच्चे अपने आप से और अभिभावक बच्चों से परेशान हो जाते हैं. कई बार इस प्रकार के मानसिक विकार का समय रहते पता ही नहीं चल पाता और बच्चे कुंठा से ग्रसित हो गंभीर डिप्रेशन की खाई में गिर जाते हैं, लेकिन बच्चों के व्यवहार से उनकी मानसिक स्थिति का पता चल जाता है. इसके लिए ऐसी स्थिति में होने वाली परेशानियों और इसके लक्षणों से अवगत होना बेहद ज़रूरी है.

डिसलेक्सिया

आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म 'तारे ज़मीं पर' जिसने भी देखी होगी उसे इस मानसिक विकार का पता अवश्य ही चल चुका होगा, फिर भी इसके कुछ लक्षणों को विस्तार से जान लेना बेहद ज़रूरी है. रॉकलैंड अस्पताल के मनोचिकित्सक डा. एस.सुदर्शनन के अनुसार, इसमें बच्चे को एक जैसे दिखने वाले शब्द पढ़ने में दिक्कत होती है. जैसे अंग्रेजी में 'बी' और 'डी' के बीच बच्चा फ़र्क़ नहीं कर पाता है. ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ने में कई गंभीर गलतियां करता है. जैसे वाक्य में पिछले शब्द को छोड़कर अगर वह आगे पढ़ने लगे या फिर पिछले शब्द को देखकर आगे आने वाले शब्द के बारे में अनुमान लगा ले. कई बार बच्चा वाक्य को पीछे की ओर से उल्टा पढ़ने लगता है. अक्सर यह भी देखा जाता है कि किसी शब्द को बनाने के लिए बच्चा अक्षरों का ग़लत संयोजन करता है. जैसे टाइम की स्पेलिंग लिखते वक़्त वह टीआईएमई की जगह टीआईईएम लिखेगा. ऐसे बच्चे एक साथ संख्या का क्रम भी याद नहीं रख पाते हैं. जैसे दिन, वर्ष व माह आदि.

क्लास में शांत बैठे रहने के बावजूद वे कुछ सीख पाने में सक्षम नहीं होते और न ही ब्लैकबोर्ड से कॉपी कर पाते है. लेकिन उनकी ऐसी हरकतों से परेशान न हों, उन्हें बात बात में लापरवाह या शैतान कहकर डांटे-पीटें नहीं. ये बच्चे मानसिक रूप से मंद या सबनॉर्मल नहीं होते हैं. इनका आईक्यू लेवल सामान्य होता है, इनकी परेशानी केवल यह होती है कि इन्हें भाषा की स्पष्ट समझ नहीं होती है. हालांकि यह देखा जाता है कि लगभग सत्तर प्रतिशत मंदबुद्धि बच्चे डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि डिसलेक्सिक बच्चे बुद्धिहीन हों. कोई भी चीज़ सीखने में ज़्यादा वक़्त लगने की वजह से ये बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं. बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें. स्कूल में भेजने से पहले उस स्कूल की ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की पड़ताल अवश्य कर लें. सरकार की तरफ़ से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे बच्चों की खास देखभाल के लिए विशेष एजूकेटर की व्यवस्था करें. सरकार की तरफ़ से दिए गए निर्देशों में ऐसे बच्चों के लिए परीक्षा में ज़्यादा समय उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है जिसका पालन अनिवार्य है. संयम और सही तकनीक से ऐसे बच्चों को संभालना आसान हो जाता है और उनका भविष्य अंधकार में डूबने से बच जाता है.

कैसे पता करें कि बच्चे की स्मरणशक्ति कमज़ोर है

- बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट कराएं.
- बच्चे की पढ़ाई-लिखाई में रुचि को देखें.
- न्यूरोलॉजिकल, सुनने और देखने की क्षमता व अन्य टेस्ट.

फोटो- प्रभात पाण्डेय

विस्मृति के कुछ लक्षण

जिन बच्चों को कुछ भी याद रखने में परेशानी हो, उनमें इन लक्षणों को देखा जा सकता है. कुछ बच्चों में इनमें से सारे लक्षण होंगे या फिर सिर्फ़ एक या दो.

- किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की अवधि कम होगी.
- संगठन या संयोजन संबंधी अज्ञानता.
- एक साथ दिए गए निर्देशों पर काम करने में असुविधा.
- पढ़ाई-लिखाई में कमज़ोर.
- आक्रामक या उग्र व्यवहार.
- मित्रों के साथ ख़राब संबंध.
- बेमेल, अनुपयुक्त या अयोग्य व्यवहार.
- सामाजिक सामंजस्य बिठाने में परेशानी.
- फ़ैसला लेने में परेशानी.
- असहनशीलता.
- अतिक्रियाशीलता या व्यग्रता.
- मनमौजीपन और ग़ुस्सैल.

डिसग्राफिया

इस मानसिक गड़बड़ी से जूझते बच्चों द्वारा लिखे गए वाक्यों में सारे शब्द उलट-पुलट होते हैं और व्याकरण की ग़लतियां होती हैं. इन्हें अपनी सोच को शब्दों में ढालने में मुश्किल होती है. इसके अलावा इनकी लिखावट भी काफी ख़राब होती है और स्पेलिंग में इनसे अक्सर ग़लतियां हो जाती हैं, जैसे- मंकी की स्पेलिंग एमओएनकेईवाई की जगह वे एमयूएनकेवाई लिख देते हैं, पर ऐसी ग़लतियां वे केवल लिखने में करते हैं, मौखिक तौर पर वे बिल्कुल दुरुस्त होते हैं.

इन्हें स्कूल या घर पर विशेष वातावरण में रखने की ज़रूरत होती है. स्कूल में भेजने से पहले यह तय कर लें कि वहां ऐसे बच्चों की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था अवश्य हो. सरकार के निर्देशों के अनुसार लिखने में परेशानी होने की वजह से परीक्षा के दौरान इन्हें एक व्यक्ति उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है जो इनके जवाबों को सही-सही लिख सके.

डिसकैलकुलिया

डा.बी.एल.कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल की मनोवैज्ञानिक सौम्या सिंह के अनुसार, गणित के जोड़-घटाव और रीज़निंग में परेशानी आना इस मनोविकार के मुख्य लक्षण हैं. इस दिमाग़ी परेशानी से प्रभावित बच्चे अंकों को उल्टा पढ़ते हैं, जैसे- 12 को 21. इन्हें गणित का टेबल यानी पहाड़ा याद करने में भी परेशानी होती है. इन्हें उंगलियों पर गिनती करने की आदत होती है. गणित के मूल चिन्ह जैसे जोड़, घटाव, भाग और गुणा का भी वे गड्डमड्ड कर देते हैं. ऐसे में विशेष ट्रेनर की ज़रूरत होती है, जो इन्हें संख्या का अस्तित्व सिखा सके. ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई में गणित विषय की अनिवार्यता में सरकार द्वारा छूट दी गई है.

अटेंशन डेफिसिट डिजऑर्डर

घर में कठोर अनुशासनिक माहौल और अभिभावकों की उपेक्षा से बच्चा अक्सर कन्फ्यूज़ रहने लगता है. इससे ग्रसित बच्चों में कई लक्षण देखे जा सकते हैं जैसे-

- ध्यान केंद्रित करने में परेशानी. काम को ठीक तरह से पूरा कर पाने में नाकामयाबी.
- खेलने आदि में ध्यान न लग पाना.
- कही जा रही बातों को ध्यान से न सुनना और इस वजह से दिए गए निर्देशों का पालन करने में परेशानी होना.
- अपनी ज़रूरी चीज़ों जैसे- खिलौने, पेंसिल, कॉपी आदि को भुला देना या जरूरी कार्यों को करना भूल जाना.

इन बच्चों का इलाज छह वर्ष से कम उम्र में नहीं किया जा सकता है. डॉक्टरी परामर्श व जांच के बूते इन बच्चों को कमिश्नर द्वारा मानसिक विकार से ग्रसित होने का प्रमाणपत्र दिया जाता है, जिसका लाभ अभिभावक उनके शिक्षण में उठा सकते हैं.

याद करने की कठिनाई से बच्चे को कैसे उबारें

- बच्चे के साथ बहुत धैर्य और विश्वास से काम लें.
- उसकी क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा दें
- बच्चे के शिक्षक से परामर्श लेकर उनके साथ काम करने के तरीक़े निर्धारित करें.
- बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें.
- बच्चे को हतोत्साहित न करें. बल्कि उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं.
- बच्चे को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करें. इसकी कई शैक्षणिक पद्धतियां होती हैं.
- कंप्यूटर ऐसे बच्चों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

इसके लिए भी सरकार द्वारा स्कूलों को ख़ास निर्देश दिए गए हैं. ठीक तरह से ध्यान नहीं रखने पर ये विकार उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं और इसका असर उनके जीवन पर दिखता है. रिपोर्ट के अनुसार, तक़रीबन साठ प्रतिशत रोड रेज, घरेलू हिंसा जैसी आम दिखने वाली घटनाओं के ज़िम्मेदार वे लोग होते हैं जो बचपन में मानसिक विकार से ग्रसित थे. कोई भी बच्चा इस मानसिक विकार से ग्रसित हो सकता है, इसके लिए कोई तय पैमाना नहीं है.

अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिजऑर्डर

इस अवस्था में बच्चे काफी 'ऊर्जावान' होते हैं. ये बहुत बातूनी, हर काम को हड़बड़ी में करने वाले, शोर व हलचल मचाने वाले और बिल्कुल अशांत रहने वाले होते हैं.

- हर चीज़ को जल्दी करने की होड़ में अक्सर गड़बड़ियां हो जाती हैं.
- ऐसी दशा से जूझते बच्चे बार-बार काम की प्रवृत्ति और वक़्त बदल जाने से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. अगर उनके सोने का वक़्त आठ बजे तय किया गया है तो आप उन्हें आधा घंटे पहले ही बता दें कि अपने दूसरे कामों को करने के लिए उनके पास अब आधा घंटा ही शेष है. उन्हें कब सोने जाना है, इस बारे में उन्हें 15 मिनट बाद फिर से याद दिलाएं.
- बच्चे को बार-बार डांटे नहीं. इससे वे निगेटिव अटेंशन के शिकार हो जाएंगे. जहां तक हो सके, इनके ऐसे व्यवहार को संतुलित करने और इनकी गतिविधियों की अनदेखी करने की कोशिश करें
- उनके व्यवहार की सुधार सारणी बनाएं. जब भी बच्चा कोई बढ़िया काम करे तो उसे उसका मनपसंद इनाम दें. और, जब वह काम ख़राब या आपकी अपेक्षा के प्रतिकूल करे तो हल्की-फुल्की सजा दी जा सकती है. कभी भी उसे कोई गंभीर सज़ा न दें.

ऑटिज्म

यह एक जटिल न्यूरोलॉजिकल डिजऑर्डर है, जो दिमाग़ के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है. आमतौर पर यह मनोविकार जन्म के बाद तीन वर्षों की अवस्था में ज़्यादा देखा गया है. लड़कों में इससे प्रभावित होने की आशंका लड़कियों की तुलना में चार गुना ज़्यादा होती है. किसी भी बच्चे पर ऑटिज्म का असर पूरे जीवनकाल तक देखा जा सकता है. जन्म के वक्त भले ही बच्चा सामान्य हो, फिर भी इसका असर दो वर्ष की आयु में नज़र आने लगता है. ऑटिज्म के शुरुआती दौर में बच्चे की प्रभावित मौखिक गतिविधियां प्रकट होती हैं, जैसे ठीक से न बोल पाना, या बे सिर पैर के बोलना. वह समाज से कटकर एकांत में रहना पसंद करने लगता है और संवेदनहीन हो जाता है. किसी प्रकार के स्पर्श, रोशनी, गंध और आवाज़ को वह अति संवेदनशील तरीक़े से लेने लगता है. काल्पनिक खेलों में वह रुचि नहीं दिखाता है. किसी भी ख़ास संरचना में रहना वह ज़्यादा पसंद करता है और बदलाव से डरता है. कभी तो वह निष्क्रिय हो जाता है और कभी अत्यधिक क्रियाशील. किसी ख़ास चीज़ में वह असाधारण रुचि दिखाता है. आंख मिलाकर बात करने से भी वह कतराता है. इन चीज़ों का अहसास होते ही डॉक्टर से परामर्श लेने में देरी न करें. इसके बाद बच्चे की सामाजिक गतिविधियों और किसी भी प्रकार की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया को जांचना आसान हो जाएगा. फिर भी बच्चों की इन क्रियाओं के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है. विभिन्न प्रकार की डॉक्टरी जांच और थैरेपी के बाद ही यह बात तय हो पाती है कि अमुक बच्चा इस विकार से ग्रसित है अथवा नहीं.

ritika@chauthiduniya.com

राशिफल

(5 से 11 अक्टूबर तक)

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

अपने कामों में संबंधित अधिकारी या बड़े भाई से सहयोग लें. इससे आप को सफलता मिलेगी. सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी पैदा होगी. अचानक किसी मूल्यवान वस्तु को पाने की अभिलाषा पूरी हो सकती है. परिवार के साथ आपका समय सुखद गुज़रेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

सोच समझकर कार्य करें, अन्यथा किसी से टकराव की स्थिति बन सकती है. संयम से काम लेना हितकर होगा. जीवनसाथी से आर्थिक सहयोग मिलेगा. सुखद मनोरंजक यात्रा के योग हैं. रक्तचाप से पीड़ित लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

किसी अपने से काम निकालने में सफल होंगे. छोटी-छोटी बातों पर तनावग्रस्त न हों. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता का योग है. घर में भौतिक साधन बढ़ेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

कोई रुका हुआ काम पूरा होगा. कुछ नया करने से लाभ हो सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. विवादित मामलों में सफलता मिलेगी. फिजूलखर्ची से बचें और बचत करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

ख़र्च अचानक बढ़ सकते हैं. नौकरी एवं व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना है. काम करने की क्षमता बढ़ेगी. आलस्य से मुक्ति मिलेगी. सोच समझकर निर्णय लेने से सफलता मिलेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

दूसरों से काम निकालने में सफल रहेंगे. अचानक कहीं लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. किसी पर अधिक विश्वास न करें, हानिकारक साबित हो सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान ज़रूर दें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा. कुछ भी ऐसा न करें जिसके कारण बाद में तनावग्रस्त रहना पड़े. ज़्यादा भावुक होना हानिकारक साबित हो सकता है. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

वृश्चिक (21 अक्तूबर से 20 नवंबर)

शिक्षा के क्षेत्र में उदासीनता कष्टकारी हो सकती है. अनचाहे लोगों से मिलना पड सकता है. संतान के प्रति दायित्व की पूर्ति होगी. जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. आर्थिक क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनी हुई है. कार्य क्षेत्र में जारी प्रयासों में सफलता के योग हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

परिवार से आर्थिक सहयोग लेने में सफल होंगे. अहंकार से बचें. रचनात्मक प्रयास सफल होंगे. सेहत के प्रति सजग रहें. श्रम संबंधी समस्या आ सकती है, संयम से उसका हल खोजें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

पारिवारिक मामलों में जारी प्रयास सफल होने की संभावना है. सामान की सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. आय और व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें. आमोद-प्रमोद के सुखद अवसर मिलेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

मकान, जमीन व अन्य संपत्तियों को लेकर चल रही समस्या का समाधान होगा. दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, विवाद की स्थिति बन सकती है. भौतिक साधनों पर व्यय होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

घर के लोगों का सहयोग मिलेगा. भावुकता पर नियंत्रण रखें. सुखद यात्रा का योग है. बड़े भाई से मनमुटाव या विवाद हो सकता है. अचानक मन चिंतित हो सकता है. किसी अज्ञात डर के कारण परेशान भी रह सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

शहरयार को अपनी सभ्यता, इतिहास, भाषा और धर्म से बेहद लगाव है. लेकिन, इनका धर्म संस्कृति को जानने का एक अलग रास्ता है व संस्कृति और समाज की आत्मा को जाने बिना शायरी नहीं की जा सकती है.

और भी बेहतर हो सकता था हंस का युवा अंक

अनंत विजय

जनचेतना का प्रगतिशील कथा मासिक, हंस ने जब युवा रचनाशीलता पर अंक केंद्रित करने का एलान किया तो पाठकों के साथ-साथ लेखकों में भी इस अंक को लेकर खासी उत्सुकता थी. हंस के संपादक राजेंद्र यादव ने अंक के संपादन की ज़िम्मेदारी युवा दलित लेखक और हंस खेमे के खास सिपहसालार अजय नावरिया को सौंपा. संपादन की ज़िम्मेदारी सौंपने के निर्णय के बारे में राजेंद्र यादव ने अपने संपादकीय में लिखा, *बात तब सूझी जब समय नहीं रह गया था.* सहसा अजय नावरिया में अलादीन का वह चिराग दिखाई दिया, जिसे घिसकर जिन्न पैदा किया जा सकता है. जिन्न पैदा हुआ, और उसके कुछ पूछने से पहले ही उसे चमत्कार करने का काम सौंप दिया गया. *महीने भर में हंस का युवा रचनाशीलता पर केंद्रित अंक तैयार हो जाना चाहिए.* यादव जी को अपने जिन्न पर भरोसा था कि वो चमत्कार कर देगा. अतिथि संपादक के रूप में प्रकट हुए यादव जी के जिन्न ने चमत्कार किया भी और महीने भर में ही इतनी सामग्री जमा कर दी कि वो एक अंक में समा नहीं पाया और उसे दो अंकों में समेटना पड़ा. सामग्री इकट्ठा करना और स्तरीय सामग्री जुटाना दो अलग बातें हैं, जिसपर हम आगे विचार करेंगे.

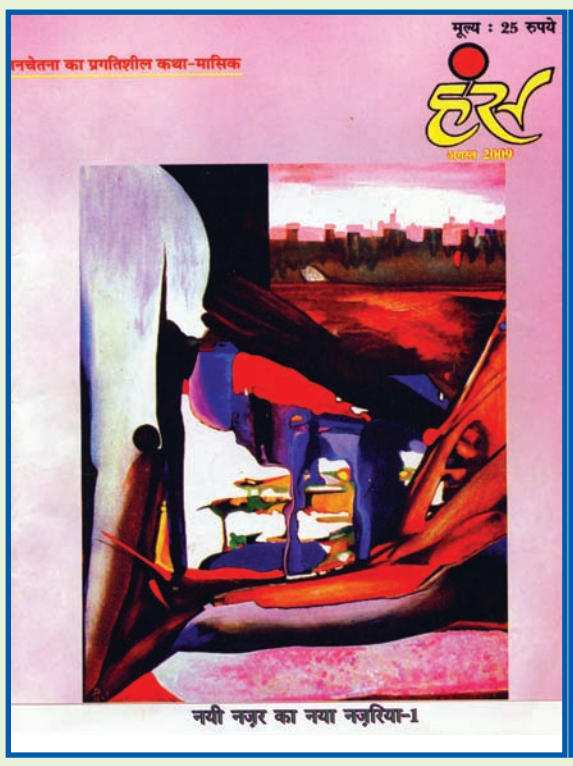

नयी नज़र का नया नज़रिया-I

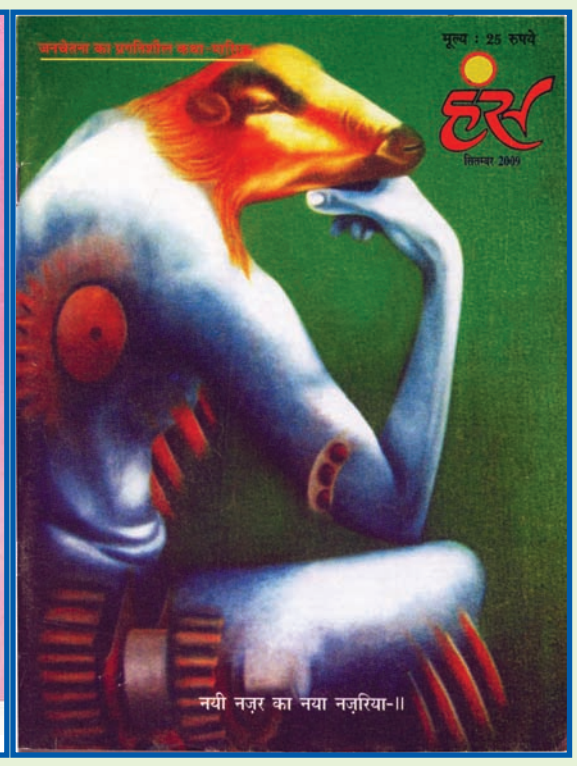

नयी नज़र का नया नज़रिया-II

राजेंद्र यादव को भले ही लगता हो कि अजय नावरिया ने अपने संपादकीय में सौंदर्यशास्त्र को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ़ चैंबर्स डिक्शनरी में से एसथेटिक्स का मतलब ढूंढ निकालना ही सौंदर्यशास्त्र को नए सिरे से परिभाषित करना नहीं है. इसके अलावा सौंदर्यशास्त्र पर अजय ने अपने संपादकीय में कोई नई बात नहीं की है. कहीं संस्कृत के श्लोकों और कहीं मार्क्स को आधार बनाकर सौंदर्यशास्त्र पर टिप्पणी करते चलते हैं. अंतत: वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव सभ्यता का विकास ज़रूरत के टुच्चे सिद्धांत के चलते नहीं, बल्कि सौंदर्यबोधात्मक चेतना के कारण हुआ है. राजेंद्र यादव को यह निष्कर्ष नया लग सकता है, लेकिन मैं यह फ़ैसला पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि वो इस बात को परखें कि इसमें नया क्या है.

अब बात दोनों अंकों में प्रकाशित कहानियों की. युवा रचनाशीलता पर केंद्रित इस अंक की पहली कहानी पत्रकार गीताश्री की है. प्रार्थना से बाहर नाम की यह कहानी संभवत: गीताश्री की पहली प्रकाशित कहानी है. गीताश्री की यह कहानी बेहद शानदार और पठनीय है. सचमुच में यह युवा रचनाशीलता की प्रतिनिधि कहानी कही जा सकती है. इसमें युवावस्था के दौर के हर पहलू, हर भटकाव और हर विचलन पर विचार किया गया है. जब किसी छोटे शहर की लड़की राजधानी पहुंचती है तो वहां की चमक-दमक और तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी उसे अपने आगोश में लेने को बेचैन होती है. इस बेचैनी में जब लड़की की महत्वाकांक्षा शामिल होती है तो कुछ ऐसा घटित हो जाता है, जिसकी उसने अपने शहर से चलते वक़्त कल्पना तक नहीं की थी. इस कहानी में गीताश्री ने युवाओं के इस मानसिक कॉकटेल को बेहद शिद्दत और सफ़ाई से उभारा है, लेकिन एक जगह कहानीकार से चूक हो गई है. एक उपन्यास की बेहद शानदार थीम को उन्होंने सस्ते में निपटा दिया. धैर्य और श्रमपूर्वक अगर इस विषय पर उपन्यास लिखा जाए और छोटे शहर की लड़कियों के संघर्ष को सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाए तो एक बेहतर कृति सामने आ सकती है. गीताश्री की भाषा में रवानगी है, अनुभव भी है, ज़रूरत बस धैर्य की है. इसके अलावा अश्विनी पंकज की कहानी पेनाल्टी कॉर्नर भी उल्लेखनीय है.

पहले अंक में यतींद्र मिश्र की कविता फैज को पढ़ते हुए में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत पर तल्ख टिप्पणी है. कवि जब कहता है– *आज भी कि फैज होते/जितने कि वो हैं अभी भी/ अपनी नज़्मों की तरक़्क़ी पसंद आवाजाही में/उम्मीद की तरह सुलगे हुए.* यतींद्र मिश्र ने कम उम्र में ही कविता की प्रौढ़ता को हासिल कर लिया है. इसके अलावा आकांक्षा पारे की दो छोटी कविताएं भी उल्लेखनीय हैं. आठ कहानियों और कुछ कविताओं के अलावा इस अंक में लेखों की भरमार है. अपने नज़रिए में नामवर सिंह और मैनेजर पांडे ने भी कोई नई बात नहीं कही है. दरअसल कोई नई बात उनसे पूछी ही नहीं गई है. घिसे-पिटे प्रश्नों के रटे-रटाए जवाब. इस अंक में अल्पना मिश्र की कहानी *पुष्पक विमान* अच्छी है.

नई नज़र का नया नज़रिया के दूसरे अंक में राजेंद्र यादव का संपादकीय बेहद सुलझा हुआ और आक्रामक भी है. आमतौर पर हंस का संपादकीय बौद्धिकता के बोझ तले दबा होता है, लेकिन इस बार राजेंद्र यादव के हमलावर तेवर ने बौद्धिकता को परे रख दिया है. नामवर सिंह पर हमला करते हुए यादव जी लिखते हैं, अपने युवाकाल में यही नामवर थे जो अपनी मेधा और तेजस्विता से सुननेवालों को झकझोर डालते थे. प्लेइंग टू द गैलरी की मानसिकता ने उन्हें कहां पर ला छोड़ा है? इधर उन्होंने यह सोचना भी छोड़ दिया है कि विमोचन वह अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की कर रहे हैं या वरवर राव की.... सत्ता वंदना के साथ थोड़ी बहुत क्रांति भी होती रहे तो क्या मुज़ायका, संकेत हाल ही में नामवर द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह की किताब के विमोचन की ओर है.

कहानियों के अलावा दूसरे अंक में भी एक परिचर्चा है जिसमें लेखक, पत्रकार, प्रकाशक आदि के विचारों को प्रमुखता दी गई है. नई नज़र का नया नज़रिया होने का दावा करनेवाला हंस के दोनों अंक बेहद सामान्य और साधारण हैं. इसमें युवा रचनाशीलता की झलकभर दिखाई देती है. राजेंद्र यादव केजिन्न ने चमत्कार तो किया, लेकिन यह चमत्कार रचना जुटाने और परिचर्चा आयोजित करने तक ही सीमित रह गया. समय की कमी और महीने भर में अंक निकालने की हड़बड़ी भी साफ़तौर पर नज़र आती है. इतने कम समय में इतनी ढेर सारी रचनाएं जुटाने के लिए अजय की तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

पत्थर भी ब्रह्म स्वरूप

देवेन्द्र झा

हर शिक्षित व्यक्ति अक्सर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आख़िर हम पत्थर को भगवान समझकर क्यों पूजा करते हैं? हम वटवृक्ष, पीपल, तुलसी आदि पेड़-पौधों की पूजा-अर्चना क्यों करते हैं? हम गाय, बैल आदि पशुओं को क्यों पूजते हैं? इन प्रश्नों को अगर पूजनेवालों से पूछा जाए तो वे अपनी अनभिज्ञता छुपाने का यत्न करते हैं. अक्सर वे अपनी क्रोधाग्नि को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर अथवा यह दोषारोपण कर, कि प्रश्नकर्ता किसी धर्मविरोधी संस्था का सदस्य है, इसलिए आस्थाहीन होकर धर्म की क्रिया-प्रक्रिया पर प्रश्नों की बौछार कर रहा है, भूल सवाल को टालने की कोशिश करते हैं. किंतु आज के सुशिक्षित और सजग समाज को जब तक तर्कसंगत उत्तर न दिया जाए, तब तक इन परंपराओं के प्रति उससे सम्मान के भाव की उम्मीद करना व्यर्थ होगा. इस तरह के प्रयास की आवश्यकता इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि धर्म के अंतर्गत इन परंपराओं का पालन समाज में अति व्यापक रूप से करते हुए देखा जा रहा है. अत: हमें उत्तर पाने के प्रयास में इन परंपराओं में सन्निहित तथ्यों तक पहुंचना होगा, जिनसे इनकी सार्थकता सिद्ध होती रही है. इस सद्प्रयास में हमें सृष्टि के कुछ नियमों पर दृष्टिपात करना पड़ेगा और नियमों के सूत्र में बंधी इस निराली सृष्टि की सुंदरता एवं विविधता में छिपे सृजनहार के पुनीत भाव को ध्यान में रखना होगा.

सृजनकर्ता ने सृष्टि की रचना में तीन चीज़ों को मिलाया- अविनाशी आत्मा (या आत्म तत्व), नश्वर माया और जुड़ने या बिछुड़ने वाली कला. सृष्टि के हर अंग-प्रत्यंग में ये तीनों अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं. यानी आत्मा, सृष्टि के समस्त पदार्थों में विराजमान है. अत: कोई सजीव और कोई निर्जीव हो, ऐसा होना संभव है. सृष्टि की हर इकाई सजीव ही है, क्योंकि उसमें आत्मतत्व है. और जो अविनाशी है, वह निर्जीव नहीं हो सकता. विज्ञान ने भी तत्व की परिभाषा में अविनाशिता एवं न रचे जा सकने वाले गुण को तत्व का आधार माना है. ब्रह्म में भी इन दो गुणों को माना गया है, अत: परमात्मा तत्व है और परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी तत्व है. चूंकि तत्व के बिना कोई यौगिक नहीं बन सकता, अत: आत्मा के बिना कोई इकाई नहीं हो सकती. सृष्टि की प्रक्रिया में प्रयुक्त दूसरी चीज़ है माया, जिसके फलस्वरूप सृष्टि की इकाई को आकार, प्रकार और विकार प्राप्त होते हैं, जिसके कारण हमें आकर्षण, विकर्षण अथवा राग-द्वेष होता है. माया से उत्पन्न गुण समयावधि से बंधे होते हैं.

अत: अवधि पूर्ण होते ही नष्ट हो जाते हैं. इसलिए माया का अस्तित्व और प्रभाव दोनों नश्वर होते हैं. सृष्टि में जो तीसरी चीज़ प्रयुक्त होती है, वह है कला. कला का अर्थ है निर्धारित और वांछित कर्म संपादित करने की सम्यक क्षमता. जैसा कि वैज्ञानिक अनुभव भी मानता है कि कार्य क्षमता के क्षेत्र और परिमाण दोनों विकसित किए जा सकते हैं. उसी तरह सृष्टि में उपस्थित विभिन्न इकाई अपनी कला बढ़ा सकते हैं और इसे घटाया भी जा सकता है. अब इन तीन चीज़ों के सम्यक मेल से जब सृष्टि की रचना हुई तो सर्वप्रथम सबसे कम कलाधारी जीव यानी एक कलाधारी जीव की रचना की गई. एक कला की परिभाषा के अंतर्गत एक कलाधारी जीव को स्वरूप और स्थान पर बने रहने की क्षमता प्रदान की गई. इस एक कलाधारी जीव की श्रेणी में पत्थर, पहाड़, मिट्टी, सोना व चांदी आदि को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है. एक कलाधारी जीव की रचना के पश्चात दो कलाधारी जीव की रचना की गई. इनमें आकार-प्रकार के साथ- साथ अपने स्थान पर संवर्धित-विकसित होने की क्षमता दी गई. दो कलाधारी जीव के उदाहरण हैं, पेड़-पौधों की दुनिया. तदुपरांत तीन कलाधारी जीव की रचना हुई. इनमें चलने-फिरने, हंसने-बोलने, सोचने-समझने आदि गुणों का भी समावेश किया गया. तीन कलाधारी जीव के उदाहरण हैं, पशु-पक्षियों की दुनिया. इसके पश्चात चार कलाधारी जीव की रचना की गई और इसे विवेक अतिरिक्त गुण के रूप में दिया गया. मानव योनि है चार कलाधारी जीव का उदाहरण. विवेक समस्त गुणों का शिरोमणि है, क्योंकि इसी के कारण हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क़ समझ पाते हैं. इसी विवेकरूपी विलक्षण गुण से विभूषित होने के कारण मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम कृति कहलाता है.

मनुष्य चार कलाधारी जीव होते हुए भी अपने सम्यक प्रयास से और कलाएं जोड़ सकता है. मनुष्य का शरीर सात कलाएं तक धारण कर सकता है. आठ अथवा आठ से अधिक कलाएं धारण करने वाले महाभूति अवतार होते हैं जिनका विशिष्ट संरचनायुक्त शरीर होता है, जो आठ एवं आठ से अधिक कलाओं के तेज़ और आभाओं को अंतर्निहित करने में समर्थ होते हैं तथा इन कलाओं के क्रिया जगत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में ये अवतार सक्षम होते हैं. इन अवतारों का प्रादुर्भाव धरा पर प्रयोजनवश होता है तथा ये माया के अधीन कार्य करते हुए दिखते रहने पर भी सदैव मुक्त अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये स्वकर्म वश नहीं, बल्कि ब्रह्मप्रयोजन वश शरीर धारण करते हैं. इसके विपरीत समस्त जीवों का मृत्युलोक में आना उनके पूर्वजन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप होता है.

अत: कर्मफल पाने के लिए वे सदा माया के अधीन होते हैं. पर, जब यही जीव अपने ब्रह्मप्रयास से चार की जगह सात कलाओं के स्वामी बन जाते हैं तो मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेते हैं. इस अवस्था को मोक्ष, परमावस्था, निर्वाण आदि नाम दिए गए हैं. इस अवस्था को प्राप्त करना ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य माना गया है. उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि पत्थर एक कलाधारी जीव है. पेड़-पौधे दो कलाधारी जीव हैं. ये भी इसलिए जीव हैं, क्योंकि इनमें भी परमात्मा का वही अंश आत्मा है जो हम चार कलाधारी जीवों अर्थात मनुष्यों में है. इस ईश्वर तत्व का आदर बना रहे और हमें अपनी अधिक कलाओं का अहंकार न हो जाए, इसलिए महापुरुषों ने सबसे पहले उनका आदर किया, जो एक कलाधारी जीव हैं. अर्थात पत्थर और पृथ्वी.

इन्हें ईश्वर का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा. भगवान अर्थात ब्रह्म तत्व को पत्थर में भी देखा जा सके, इसलिए पत्थर को ब्रह्मरूप मानकर पूजा जाने लगा. इसी परंपरा के अंतर्गत पहाड़ विशेष की भी पूजा होने लगी और पृथ्वी को माता स्वरूप मानकर इसकी पूजा होने लगी.

(लेखक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

हुआ ये क्या कि ख़ामोशी भी गुनगुनाने लगी - शहरयार

प्रदीव मांडव

जिस शहर अलीगढ़ में मैंने सउर और सलीके का पहला लफ़्ज़ सीखा, पहला अफ़साना लिखा, अदब से पहली मुलाक़ात हुई वहां रहते मुझे पता ही नहीं लगा कि अज़ीम शायर शहरयार का घर भी उसी गांव में है जहां मेरा घर है. अचानक दिल्ली आकर मैंने यह गीत सुना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यूं है/ इस शहर में हर शख्स परेशान-सा क्यूं है. फिर फिल्म आई उमराव जान जिसमें रेखा को इनकी ही ग़ज़ल पर मुज़रा करते और थिरकते देखा, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने/ इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने. इसी ग़ज़ल का आख़िरी शेर जब ज़ेहन में घुसा तो बेचैन कर गया, उम्र भर सच ही कहा, सच के सिवा कुछ न कहा, अज्र क्या इसको मिलेगा, ये न सोचा हमने और इसी की बेचैनी ने शहरयार साहब से मिला दिया और उसके बाद जब मैंने इस शायर के अंदर तक झांकने की कोशिश की तो पाया कि एक नायाब दोस्त और इंसानियत से लबालब शख्सियत की सरपरस्ती का हाथ मेरे सिर पर है.

शहरयार साहब का असली नाम कुंवर अख़लाक मोहम्मद खां है. वह क़द काठी से मज़बूत और सजीले थे, यह बात सत्तर साल की उम्र पार करने के बाद आज भी क़ायम है. वालिद चाहते थे कि शहरयार उन्हीं के क़दमों पर चलकर पुलिस अफ़सर बन जाएं, लेकिन इन्होंने झूठ बोल दिया और फार्म जमा नहीं किया. वालिद पुलिस की वर्दी पहनाना चाहते थे. उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि अख़लाक मोहम्मद खां को तो शहरयार बनना था. लाल खानियों के इलाक़े की विरासत सांझी तहज़ीब को अपने कंधों पर लेकर चलना था. 1961 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने उर्दू में एमए किया. शहरयार विद्यार्थी जीवन में ही अंजुमन-ए-उर्दू मुअल्ला के सेक्रेटरी और अलीगढ़ मैगज़ीन के संपादक बना दिए गए, तभी इनके इरादों ने पकना शुरू कर दिया. अपने इलाक़े की सांझी तहज़ीब उनका मज़हब बन गई. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में उर्दू और हिंदी भाषा के बीच की दीवार बनावटी नज़र आने लगी. वर्ष 1959 में उन्होंने गालिब नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन-संपादन शुरू कर दिया. फिर 1961 से 1966 तक हमारी ज़ुबान से जुड़े रहे.

दरअसल वह दौर था, जब अलीगढ़ फ़िरकापरस्ती के लिए बदनाम था और फ़िरकापरस्ती के ख़िलाफ़ इतिहासकार मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर नुरुल हसन मशहूर अदीब आले अहमद सुरूर, प्रोफेसर अब्दुल अलीम और प्रोफेसर सतीशचंद्र एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करने में जुट गए थे, जो मुल्क की जम्हूरी तहज़ीब क़ायम रख सके और फ़िरकापरस्ती से लड़ते हुए नए तरक़्क़ी पसंद अदब की तहरीर कर सके! वहीं दूसरी ओर थे, अफ़साना निगार डॉ. काजी अब्दुल सत्तार, शायर एवं उपन्यासकार डॉ. राही मासूम रजा, जावेद कमाल, डॉ. कुंवर पाल सिंह और सैयद यूनिस रज़ा, जो बुज़ुर्गों की दी हुई मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे थे. वर्ष 1966 में शहरयार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में प्रवक्ता नियुक्त हुए और 1965 में

ही इनका पहला काव्य संग्रह इस्मे आजम प्रकाशित होकर आया. इसके बाद 1983 में वहीं रीडर और 1987 में प्रोफेसर हो गए. साथ ही एएमयू की विचार प्रधान पत्रिका फ़िक्र-ओ- नज़र के संपादक भी बन गए. फिर तो शहरयार ने मो. अब्दुल कलाम आज़ाद, हाजी, शिबली, नजीर अहमद और सर सैयद विशेषांक संपादित कर दिए, जो बाद में संदर्भ ग्रंथ बने. वर्ष 1969 में इनका दूसरा काव्य संग्रह सातवां दर आया. हिज्र का मौसम 1976 में और 1985 में ख्वाब का दर बंद है प्रकाशित हुआ, जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया. सिलसिला अब भी जारी है. शहरयार बदस्तूर लिख रहे हैं. अब उनका समूचा काव्य लेखन नागरी लिपि में भी आ गया है और हिंदी में उसका भरपूर स्वागत हुआ है. शायद यही सपना था उनका, क्योंकि बातचीत के दौरान वह अक्सर कहते हैं, हिंदी और उर्दू अदब, शायरी के मकसद से अलग नहीं हो सकते. मुझे बहुत... और उलझनें एक ही तरह की हैं. असल में... अपने ज़ेहनी इलाक़े के सवालों और सबब से ही हिंदी उर्दू अदब बनता है. शहरयार को अपनी सभ्यता, इतिहास, भाषा और धर्म से बेहद लगाव है. लेकिन, इनका धर्म संस्कृति को जानने का एक अलग रास्ता है व संस्कृति और समाज की आत्मा को जाने बिना शायरी नहीं की जा सकती है. इसलिए वह सिर्फ़ ग़ज़ल, नज़्म लिखते नहीं, बल्कि उनके साथ जीते हैं. लफ़्ज़ों की किफ़ायत, नई ज़ुबान गढ़ने और मुहावरों की अनवरत खोज करते हुए वह पढ़ने और सुनने वालों में एक आंच सी सुलगा देते हैं- तुम्हारे शहर में कुछ हुआ नहीं है क्या/ तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या/ मैं इक जमाने से हैरान हूं कि हाकिमे शहर / जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या.

शहरयार को अपनी सभ्यता, इतिहास, भाषा और धर्म से बेहद लगाव है. लेकिन, इनका धर्म संस्कृति को जानने का एक अलग रास्ता है व संस्कृति और समाज की आत्मा को जाने बिना शायरी नहीं की जा सकती है.

वह अपनी शायरी में उन लफ़्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, जो अपने मायने खो चुके हैं. वह मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा इंसानी जज़्बात को भी बहुत ही सीधे-सादे ढंग से पेश करने की क्षमता रखते हैं.

बकौल कमलेश्वर, शहरयार को पढ़ते हुए रुकना पड़ता है... पर यह रुकावट नहीं, बात के पड़ाव हैं, जहां सोच को सुस्ताना पड़ता है, सोचने के लिए... इसलिए, जब आज तिहत्तर साल का यह नौजवान कवि आपसे कहता है कि- तमाम शहर आग की लपट में है भागिए/हुजूर कब से मीठी नींद सो रहे हैं भागिए/ इसी तरह ये जो आसमां पे सितारा है... को पढ़कर सरदार अली ज़ाफरी जैसी शख्सियत ने उनकी तारीफ़ में कसीदे कसे थे. शहरयार की शायरी तनहाई में पैदा होती है और उन लम्हों में रंग भरने का काम करती है और ये रंग इंसानी ज़िन्दगी की मोहब्बत व उसके सरोकारों से पैदा होते हैं. जैसे, तनहाई की ये कौन सी मंज़िल है रफीको/ ता-हद्दे-नज़र ए क़ाबियाबान सा क्यूं है. शहरयार साहब को पता है कि भाषाएं वर्तनी से नहीं बनतीं, बल्कि दुख-दर्द और समाज की तक़लीफों से भाषा जन्म लेती है. वह अपनी जवानी के दिनों में हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और एएमयू के जाने माने एथलीट भी वही शायद उनकी सेहत के काम आ रहा है. कोई अनचाही भूख नहीं है, उन्हें तो सिर्फ़ इंतज़ार है-

स्याह रात नहीं लेती है, नाम ढलने का
यही वक़्त है सूरज तेरे निकलने का
कहीं न सबको समंदर बहाकर ले जाए
ये खेल ख़त्म करो कश्तियां बदलने का.

सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक तसल्ली की बात है कि इस बदलते हुए बेचैन वक़्त और बदहवास दौर में मुक़म्मल तहज़ीब का नक़्शा तैयार करते शायर शहरयार हमारे साथ हैं, नहीं तो हम भी यही कहते हैं, आंखों से कहो अब मांगे ख्वाबों के सिवा जो चाहे...

(लेखक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

सैमसंग ने यूजर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखकर इसे बाज़ार में उतारा है. सैमसंग पिक्सन-12 क़ीमत के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है.

याहू और ट्वीटर के बाद क्या?

क्या याहू विश्व में सबसे ज़्यादा माइक्रो ब्लॉगिंग की ख़बर देने वाली वेबसाइट ट्वीटर को टक्कर दे पाएगा? ख़ैर इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा. फ़िलहाल याहू भी ट्वीटर से दो-दो हाथ करने मैदान में उतर गया है. लेकिन ट्वीटर वेबसाइट के मुताबिक़, हम इस साइट को एक सफल रेवेन्यू उत्पन्न करने वाली कंपनी बनाना चाहते हैं, जो विश्वस्तरीय प्रतिभा को प्रेरणादायक संस्कृति और व्यापार के दृष्टिकोण से अपनी ओर आकर्षित करेगा.

ट्वीटर हमेशा यूजर्स के व्यवहार का अनुसरण करता है. सबसे ख़ास बात यह है कि यह अनुसरण ही नहीं करता, बल्कि उनके फीचर्स रिक्वेस्ट पर ध्यान देता है और उस पर अमल भी करता है. यही कारण है कि उसने यूजर्स के रिक्वेस्ट पर मोबाइल पर एम.टवीट्र.कॉम साइट लांच की है. इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञानवर्धक जानकारी सहजता और सरलता से देना है. उन्होंने मोबाइल पर भी इस तरह की सुविधा देने का वादा किया है. ट्वीटर ने पाया कि लोग बड़े ही दिलचस्प तरीक़े से किसी फीडबैक को एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं और वे अपने आपको विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना चाहते हैं. वैसे ट्वीटर ने हमेशा यूजर्स की इच्छाओं का ध्यान रखा है. माइक्रो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में याहू धीरे-धीरे अपने क़दम आगे बढ़ा रहा है. याहू एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है और उसके फीचर्स से भी हर कोई वाक़िफ़ है.

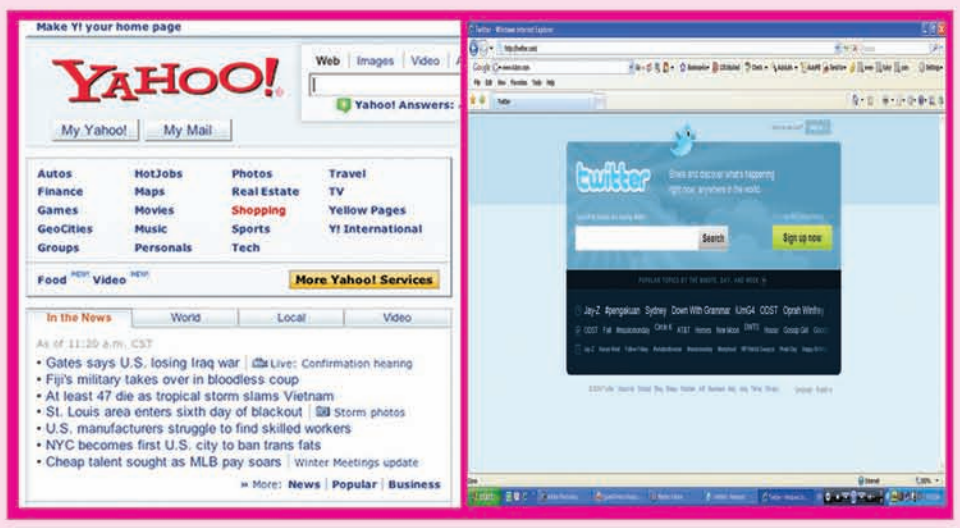

उसने याहू मेमे के नाम से माइक्रो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा दी है. यह बिल्कुल ट्वीटर जैसी ही साइट है. इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? इसका सीधा और सरल जवाब है कि इंटरनेट पर बहुत से सोशल नेटवर्किंग साइट सक्रिय हैं. इन साइट्स के द्वारा यूजर्स मैसेज भेजते और पढ़ते हैं. इतना ही नहीं वे ताजातरीन घटनाओं से भी वाक़िफ़ रहते हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग टेक्स्ट पोस्ट है. याहू जल्द ही इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट ला रहा है. जिससे पूरे विश्व में लोग टेक्स्ट पोस्ट के द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे. बिना प्रचार-प्रसार के याहू ने माइक्रो ब्लॉगिंग याहू मेमे शुरू करने की घोषणा की है. हालांकि याहू मेमे की लांचिंग स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा में पहले ही हो चुकी है. अब इसे अंग्रेजी में लांच किया गया है. वर्तमान में यह सुविधा इनविटेशन मोड में है. इनविटेशन प्राप्त करने के बाद याहू यूजर्स आसानी से एकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. इसके जवाब में उन्हें माइक्रो शेयरिंग टेक्स्ट, म्यूज़िक, फोटो और वीडियो के लिए एक ब्लैंक ब्लॉग मिलेगा. ग़ौरतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी. मेमे यूजर्स फाइंड ऑप्शन के द्वारा दूसरे यूजर्स को सर्च कर सकते हैं. इसमें आप एक सौ शब्दों का विवरण लिख सकते हैं.

याहू मेमे ट्यूंबलर, ट्वीटर, पॉवेंस और कई दूसरे जैसा ही है. अब एक अहम सवाल यह है कि इस पर रजिस्टर्ड कैसे किया जाए. इस पर रजिस्टर्ड करना बहुत ही आसान है. इसे कोई भी आसानी से कर सकता है.

सबसे पहले आप साइट पर जाएं, उसके बाद मेमे यूआरएल जो निर्देश देता है उसका पालन करें. रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ट्वीटर और फेसबुक जैसी ही है. मेमे सर्विस बहुत ही बुनियादी है. हालांकि इसमें और अधिक सुधार करने की ज़रूरत है. दूसरे प्रतियोगियों की तुलना में इसके फीचर्स में कमी है. अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी याहू अपने फीचर्स में सुधार करता है और यूजर्स की उम्मीदों पर खरा उतरता है.

रफ़्तार की ऐश, वीमैक्स!

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

प्रबंध निदेशक यूकी मिने सूजी, जॉन अब्राहम और बिजनेस हेड पंकज दुबे

जानदार इंजन, शानदार सवारी...जी हां, रफ़्तार के सौदागरों के लिए हवा से बातें करने वाली सवारी है, वीमैक्स. यूथ के दिलों पर राज़ करने वाली यह बाइक जितनी ख़ूबसूरत है उससे कहीं अधिक दमदार इसके फीचर्स हैं. यामहा इस बाइक के ज़रिए बाइक के इतिहास में एक नई कहानी लिखने को तैयार है.

बाइक, वह भी 20 लाख रुपये की. जी हां, चौंकिए मत. राजधानी के पांच सितारा होटल में जापान की मशहूर दोपहिया कंपनी यामहा ने भारतीय बाज़ार में अब तक की सबसे महंगी बाइक लांच की है. यह है वीमैक्स. इसकी शो रुम क़ीमत ही 20 लाख रुपये है. ग़ौरतलब है कि पिछले साल जापानी कंपनी सुज़ुकी ने भारतीय बाज़ार में सबसे तेज़ रेसिंग बाइक हायाबूसा और इंट्रयूडर लांच किया था, जिसकी इंजन क्षमता मारुति 800 से भी दोगुनी थी. यानी लगभग 1600 सीसी. इससे एक बात तो साफ़ है कि बाइक निर्माण के क्षेत्र में किसी भी जापानी बाइक कंपनी का मुक़ाबला करना काफी मुश्किल है.

कंपनी ने एफज़ेड बाइक के तीन मॉडल भी पेश किए, हालांकि ये तीनों अभी सीमित संख्या में ही बाज़ार में उपलब्ध होंगे. वीमैक्स बाइक की बात करें तो इसकी इंजन क्षमता 1679 सीसी की है, यानी टाटा इंडिका कार से भी ज़्यादा मज़बूत. इसका वज़न 310 किग्रा है और ईंधन क्षमता 15 लीटर है. इस लिहाज़ से देखा जाए तो भारत में अब तक की सबसे दमदार बाइक यामहा ने लांच की है.

इस अवसर पर इंडिया यामहा मोटर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी युकी मिनेत्सूजी ने बताया कि मुझे उम्मीद है कि इन बाइक्स को ग्राहक उसी उत्साह से पसंद करेंगे, जिस तरह वे यामहा की बाइक्स को पसंद करते आए हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कंपनी ने भारतीय बाज़ारों की बिक्री में 80 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है और उम्मीद है, आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ेगी.

सैमसंग पिक्सन-12 करेगा धमाल

वैसे यूजर्स, जो अपने मोबाइल से अच्छी क्वालिटी की फोटो लेना चाहते हैं, उनके लिए ख़ुशख़बरी है. सैमसंग ने एक नया हैंडसेट बाज़ार में उतारा है. इसमें ऐसे फीचर्स की भरमार है, जो यूजर्स को दीवाना बना देती हैं. यह जल्द ही भारतीय बाज़ार में धूम मचाने आ रहा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं सैमसंग पिक्सन-12 की.

सैमसंग ने हाल ही में एक नया मॉडल पिक्सन 12 मोबाइल भारतीय बाज़ार में लांच किया है. यह देखने में काफी आकर्षक है और इसमें 7.9 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन है. इसके फीचर्स यूजर्स को अपनी ओर अवश्य ही आकर्षित करेंगे. इसके ज़रिए यूजर्स आसानी से फोटो ले सकते हैं. इतना ही नहीं इससे वे नेट से ब्राउज और शेयर भी कर सकते हैं. पिक्सन 12 मोबाइल में जो डिजीटल कैमरा लगा हुआ है उसमें विकसित लेंस और एक्सनेन का शानदार कांबिनेशन है. 28 एमएम के वाइड एंगल लेंस से यूजर्स फुल स्नैप ले सकते हैं. मतलब यह हुआ कि उन्हें स्नैप लेने में दिक़्क़त नहीं होगी. स्मार्ट ऑटो पिक्सन 12 इसकी दूसरी विशेषता है.

सैमसंग पिक्सन 12 में टच ऑटो फोकस (एफ) एक नई विशेषता है. जिसके ज़रिए यूजर्स अंगुली से फोकस प्वाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर मूव करा सकते हैं. फोटो शेयर करने के साथ ही आप सोशल नेटवर्किंग साइट-फेसबुक, माई स्पेस, फ्लीकर, फ्रेंडस्टार आदि से फोटो और वीडियो भी डाउन लोड कर सकते हैं. इसमें हाई कनेक्टिविटी वाई-फाई और एचएसयूपीए सुविधा भी है. सैमसंग टेलकॉम डिवीज़न के कंट्री हेड सुनील दत्त के मुताबिक़, पिक्सन 12 को लांच कर कंपनी ने अपना वादा पूरा किया. स्पीड एक्सेस, फास्ट शटर स्पीड और क्वीक ब्राउजिंग, फेस टेग और फोटो टेग आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स है, जिसे यूजर्स अपने मोबाइल में सर्च करते हैं. सैमसंग ने यूजर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखकर इसे बाज़ार में उतारा है. सैमसंग पिक्सन-12 की क़ीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. लगता है कि इस हैंडसेट की क़ीमत 30,000 रुपये तक की हो सकती है.

सैमसंग ने हाल ही में एक नया मॉडल पिक्सन 12 मोबाइल भारतीय बाज़ार में लांच किया है. यह देखने में काफी आकर्षक है और इसमें 7.9 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन है.

बच्चों के लिए हैंडसम हेडफोन

संगीत से लोगों को सुकून मिलता है. शायद इसलिए जब वे तनावग्रस्त रहते हैं तो संगीत सुनते हैं. अक्सर आपको बूढ़े, बच्चे और जवान सभी अपने कान में लीड लगाकर गाना सुनते मिल जाएंगे. इस मामले में बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले हैं. वे भी संगीत का जमकर लुत्फ़ उठाते हैं. बच्चे फिल्म, कंप्यूटर गेम और मीडिया प्लेयर से निकलने वाली सभी धुन को सुनना चाहते हैं और इसके लिए वे हेडफोन का उपयोग करते हैं. लेकिन इस दरम्यान वे ऐसे हेडफोन का उपयोग करते हैं जो उनके सिर के हिसाब से नहीं बना होता है और आवाज़ भी स्पष्ट नहीं आती है. लेकिन अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिफिन टेक्नोलॉजी ने एक हेडफोन माइफोन्स डिज़ाइन किया है, जो ख़ास तौर से बच्चों के लिए ही है. इसमें वे सारी ख़ूबियां मौजूद हैं, जिसकी ज़रूरत बच्चों को होती है. इसमें एक सर्किट भी लगा हुआ है जो 85 डेसीबल की आवाज़ को रेगुलेट करता है. यह बच्चों के लिए काफी सुरक्षित है और उनके कान पर ख़राब असर नहीं पड़ता है. इस हेडफोन की बनावट ऐसी है जो इसे बच्चों के सिर से बाहर नहीं निकलने देता. हेडफोन के ईयर कैप को आप बदल भी सकते हैं. यह तीन डिज़ाइनों में उपलब्ध है और इसमें ख़ाली टैंपलेट्स भी हैं, जिसके द्वारा बच्चे हेडफोन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. इसकी क़ीमत लगभग 39 डॉलर है और यह जल्द ही बाज़ार में आ जाएगा. तो है न, अच्छा! और आपको हो-हल्ला से मुक्ति मिल जाएगी. मतलब यह कि आपका शरारती लाडला जो शोरगुल करके आपके दिमाग की बत्ती बंद कर देता था, कम से कम उससे तो आपको चैन मिलेगा. इसके साथ ही घर का वातावरण भी शांत रहेगा.

फोर्ड भारतीय बाज़ार में उतारेगी छोटी कार

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

फिगो के साथ फोर्ड के ग्लोबल हेड एलेन मुलाली (आगे) और फोर्ड के इंडिया हेड माइकल बोनहम

कार बनाने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी फोर्ड ने भारत में अपनी नई छोटी कार फिगो को बाज़ार में उतारने की घोषणा की. इस मौक़े पर फोर्ड के ग्लोबल हेड एलान मुलाली भी मौजूद थे. फिगो इटालियन नाम है और इसका अर्थ सौम्य होता है. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 50 करोड़ डॉलर की छोटी कार परियोजना के तहत इसे 2010 के पहली तिमाही में भारतीय बाज़ार में उतरेगी.

हालांकि कंपनी ने कार की क़ीमत की घोषणा नहीं की है. उन्होंने बताया कि 2010 में कंपनी ने दो लाख कार उत्पादन करने की योजना बनाई है. साथ ही यह भी कहा कि इस कार को भारतीय सड़कों के अनुरूप ही बनाया गया है. कंपनी का मानना है कि अगले 10 वर्षों में भारत में छोटी कार की मांगों में दो गुना वृद्धि होगी और इसी के चलते फोर्ड ने भारत पर ध्यान केंद्रित किया है.

इस छोटी कार के ज़रिए भारत की सबसे बड़ी कार निर्यातक कंपनी बनने का इरादा रखती है और इसी उद्देश्य से चेन्नई स्थित संयंत्र में 50 करोड़ डॉलर की लागत से नया संयंत्र लगाया जा रहा है. फिगो की क़ीमत इस श्रेणी के अन्य कारों की तरह ही होगी, लेकिन उसकी घोषणा जब कार सड़क पर दौड़ेने के लिए तैयार हो जाएगी. उन्होंने फिगो को भारतीय ग्राहकों को आकर्षित करने वाली कार बताते हुए कहा कि इसका डिज़ाइन युवाओं और कामकाजी लोगों को ध्यान में रख किया गया है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 9811205225 email : advt@chauthiduniya.com

यह दूसरा मौक़ा था जब इस सत्र में मोहन बगान को चर्चिल ब्रदर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

डूरंड कप का चैंपियन चर्चिल ब्रदर्स

फोटो– सुनील मल्होत्रा

आई लीग चैंपियन चर्चिल ब्रदर्स की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है. मोहन बगान की टीम को 3–1 से धूल चटाकर उसने 122वें डूरंड कप ख़िताब पर क़ब्ज़ा कर लिया. निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं होने के बाद अतिरिक्त समय तक चले इस मैच में चर्चिल ने ताबड़तोड़ तीन गोल दागे. तीनों ही गोल चर्चिल ब्रदर्स के नाइजीरियाई स्ट्राइकर औदाफे ओनयका ने किए. जबकि मोहन बगान की ओर से एकमात्र गोल अतिरिक्त समय के पांचवें मिनट में चिदी इदेह ने बेहतरीन हेडर के द्वारा किया. लेकिन इदेह का यह चमत्कार अधिक समय तक बरक़रार नहीं रह सका. ओदाफा ने पैरों की जादूगरी दिखाते हुए हैट्रिक गोल दागकर मोहन बगान के मंसूबों पर पानी फेर दिया. ओदाफा ने न सिर्फ़ अपने पैरों की कलाकारी दिखाई, बल्कि उसने हेडर से ही अपनी हैट्रिक पूरी की. यह दूसरा मौक़ा था जब इस सत्र में मोहन बगान को चर्चिल के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इसके पहले गोवा की इस टीम ने कोलकाता की चैंपियन टीम को आईएफए शील्ड कप के फाइनल में भी 2–0 से मात दी थी. मोहन बगान की टीम का लगातार तीसरे साल भी डूरंड कप के फाइनल में पहुंचने के बावजूद हार का मुंह देखना. यह उसके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है. पिछली बार महिंद्रा यूनाइटेड की टीम ने उसे मात दी थी तो इस बार चर्चिल ब्रदर्स के हाथों मुंह की खानी पड़ी.

निर्धारित समय तक किसी भी टीम के गोल नहीं कर पाने की वजह से अतिरिक्त समय तक चले इस मैच में चर्चिल ब्रदर्स ने ताबड़तोड़ तीन गोल दागे. तीनों ही गोल चर्चिल ब्रदर्स के नाइजीरियाई स्ट्राइकर औदाफे ओनयका ने किए.

गुरु गैरी का सेक्स ज्ञान

सेक्स आपकी आक्रामकता बढ़ा सकती है. चौंकिए मत जनाब, यह मंत्र दिया है टीम इंडिया के गुरु गैरी ने. गैरी कर्स्टन ने टीम इंडिया को चैंपियन बनने का नया सूत्र दिया है. पहले एक वात्स्यायन हुए, जिन्होंने कामसूत्र दिया था और अब गुरु गैरी ने चैंपियन होने का नया सूत्र दिया है जिसके नक़्शेक़दम पर चलकर धोनी की टीम चैंपियन बन सकती है. उनके सुर में सुर मिलाया है टीम इंडिया के मेंटल कंडीशनर पैडी उपटन ने. इन दोनों की मानें तो सेक्स से खिलाड़ियों में जोश और आक्रमकता आती है. काम से क्रीड़ा तक के इस सूत्र में खिलाड़ियों को ख़ूब खाने और ख़ूब सेक्स करने की सलाह दी गई है. साथ ही अपने फिटनेस की भी फ़िक्र करने की नसीहत दी गई. चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के पहले कर्स्टन की इस सलाह ने एक अलग ही बहस छेड़ दी है. फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान इस तरह की बातें काफी चर्चा का विषय बनती थीं. गत फीफा प्रतियोगिता में ब्राजीलियन सुपर–स्टार रोडाल्डिन्हो अपने प्रदर्शन से कम और प्रेमिका के साथ इन्हीं वजहों से सुर्ख़ियों में अधिक बने रहे. बाद में फ्रांस के हाथों हार के बाद रोनाल्डिन्हो को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. जबकि 2002 में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील के कोच फिलिप स्कोलारी ने इस पर प्रतिबंध लगाया था और उन्होंने टीम को चैंपियन भी बनाया. ख़ैर अब गुरु गैरी की इस सलाह ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. पूर्व भारतीय खिलाड़ी सहित विश्व क्रिकेट के कई दिग्गजों ने इसकी खिल्ली उड़ाई है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग और ब्रिटिश खिलाड़ी कॉलिंगवुड ने तो इसकी मुख़ालफ़त भी शुरू कर दी है. पोंटिंग ने तो इसका मज़ाक़ उड़ाते हुए कहा कि क्या वाकई अब यह टीम इंडिया का विज़न है. हालांकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और मशहूर खिलाड़ी अशोक कुमार, कोच कर्स्टन के विचारों से बिल्कुल सहमत है. उनका तो यहां तक मानना है कि सेक्स करने से मना करने की वजह से ही भारत को 1973 के हॉकी विश्वकप में मात मिली थी. उनके मुताबिक़, जो खिलाड़ी सारे मैचों में बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा था, उसे फाइनल में सेक्स करने से मना कर दिया गया.

फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान इस तरह की बातें काफी चर्चा का विषय बनती थीं. गत फीफा प्रतियोगिता में ब्राजीलियन सुपर-स्टार रोडाल्डिन्हो अपने प्रदर्शन से कम और प्रेमिका के साथ इन्हीं वजहों से सुर्ख़ियों में अधिक बने रहे. बाद में फ्रांस के हाथों हार के बाद रोनाल्डिन्हो को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

नतीजतन भारत को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. अब टीम इंडिया अपने कोच की इस नेक सलाह को किस हद तक अपनाती है, यह तो देखने वाली बात होगी. क्या वह वाकई इस पर अमल कर चैंपियन बनना चाहती है. हालांकि, फ़िलहाल कोई भी भारतीय खिलाड़ी इस पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं. लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं कि कोच कर्स्टन ने एक नए विवाद को तूल दे दिया है.

कुश्ती का किंग

भारतीय कुश्ती में एक और सितारा उभर कर सामने आया है. यह सितारा है रमेश कुमार. जिसने डेनमार्क में चल रहे विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी. बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा था. इस बार कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह कारनामा रमेश कुमार ने कर दिखाया. हालांकि भारत की उम्मीदें सुशील कुमार से भी थी, जिसने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले गोल्ड मेडल जीतने का दावा किया था. लेकिन सुशील बीजिंग के इतिहास को भी नहीं दोहरा सके और बिना किसी पदक के उन्हें मायूस खाली हाथ ही लौटना पड़ा. भारत की इस कमी को उत्तरप्रदेश के इस पहलवान ने पूरा कर दिखाया. ग़ौरतलब है कि विश्व कुश्ती के इतिहास में भारत का यह सिर्फ़ चौथा पदक है. इसके पहले भारत के विशंबर ने 1967 में रजत जबकि 1961 में जापान में उदयचंद ने कांस्य पदक जीता था. वहीं महिला वर्ग में अलका तोमर ने 2006 में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की थी. विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 74 किलो वर्ग में रमेश कुमार ने कांस्य पदक जीत बीजिंग ओलंपिक के बाद भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई है. सबसे बड़ी बात कि रमेश ने 42 साल बाद भारत को इस प्रतियोगिता में कोई पदक दिलाया. रमेश ने ब्रिटेन के माइकल ग्रंडी को 4–2 और बुल्गारिया के किरिल तेर्जिव को 7–4 से हराकर कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. कांस्य पदक जीतने पर उनके कोच नरेश कुमार ने बताया कि हम रजत या स्वर्ण पदक भी जीत सकते थे. लेकिन एक ही दिन में फाइनल मुक़ाबले होने से भी पहलवानों को नुक़सान उठाना पड़ा. उम्मीद की जा रही थी कि अगर ऐसा नहीं होता तो नतीजा इससे भी बेहतर हो सकता था. विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदकों की दौड़ से सुशील के बाहर होने के बाद रमेश ने न सिर्फ़ पदक जीतने में सफलता हासिल की, बल्कि उसने इतिहास ही रच दिया. इस तरह देखा जाए तो भारत के लिहाज़ से यह साल टेनिस, क्रिकेट और कुश्ती सहित कई खेलों के लिए एक सुनहरा दौर लेकर आया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Haier
Bhagyalakshmi
offer
Assured Cash Back Offer upto 100%
GLOBAL No.1 REFRIGERATION APPLIANCES
Free Exciting Gifts & Lot More!
Discount Coupon for Diamond Jewellery and Gold plated cutlery set
DTH*
Digital Entertainment Service
Chance to Participate in Haier Gladrags Mrs. India Contest 2010 without Auditions!
8 pieces Microwavable Ref-Kit worth Rs. 699/- absolutely free
Travel Bag
Celebrate the festive spirit with free gifts, exciting offers, up to 100% cash back* and a lifetime chance to get famous!!
This festive season when you buy a Haier Refrigerator, Washing machine, Air Conditioner or a Colour TV, you get a scratch card which gets you assured cash back upto 100%*. There's more! Get a shot at fame with a chance to participate in the Haier Gladrags Mrs. India Contest 2010 without auditions. Also get free exciting gifts on various products. So hurry! Infuse your life with the excitement of Inspired Living.
Offer valid during festive season or till stocks last.
Offer not valid on CTV 21F17SS *Conditions Apply.
Available in select cities only. * As per Euromonitor International Survey 2008.
Arms 'd' Crestra /Haier/204/09
www.haierindia.com
Haier
Inspired Living
Haier CUSTOMER CARE
1860-180-3333 (Any Service Provider)
6000 9090* (Prefix nearest city STD Code)

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया दिल्ली, 5-11 अक्टूबर 2009

फिल्मी दुनिया में पहले कभी भी आपने किसी दो अभिनेत्रियों के बीच दोस्ती की चर्चा नहीं सुनी होगी, लेकिन अब कुछ समय से अभिनेत्रियों की दोस्ती आम-सी होती जा रही है.

इस दोस्ती में दम है

फिल्मी दुनिया में पहले कभी भी आपने किसी दो अभिनेत्रियों के बीच दोस्ती की चर्चा नहीं सुनी होगी, लेकिन अब कुछ समय से अभिनेत्रियों की दोस्ती आम-सी होती जा रही है. शेर्लिन चोपड़ा व रानी मुखर्जी के बीच और करीना कपूर व अमृता राव के बीच दोस्ती की चर्चा तो आपने सुनी ही होगी. दोस्ती की इस लिस्ट में अब पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली भी शामिल हो गई हैं. वैसे भी बॉलीवुड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि दो हसीनाएं ख़ुशनुमा पल साथ-साथ बिता रही हों. एक बात तो दोनों में कॉमन है. मिस इंडिया का मंच दोनों के लिए फिल्मी दुनिया का प्रवेशद्वार बना था. आजकल तो दोनों साथ-साथ शॉपिंग करने और तफरीह के लिए भी जाने लगी हैं. और हां, ख़ाली समय में अपनी फिटनेस से जुड़ी बातें भी एक दूसरे से शेयर करती हैं. लगता है कि हिंदी फिल्मों की इन दो ग्लैमरस अभिनेत्रियों की दोस्ती अगर इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में फिल्मों की प्रतिस्पर्द्धी दुनिया में लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देंगे. हम भी यही चाहेंगे कि दोस्ती को दुनिया की नज़र न लगे.

गुलाबी गैंग में रवीना हुई शामिल

जल्द ही रवीना टंडन फिल्मों में दिखाई देने वाली हैं. बॉलीवुड में उनकी वापसी फिल्म गुलाबी गैंग से होने जा रही है. फिल्म के निर्माता मेकअप मैन से निर्माता बने सुभाष सिंह हैं. फिल्म में रवीना का किरदार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से मिलता-जुलता रखा गया है. फिल्म की कहानी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के एक महिला संगठन गुलाबी गैंग पर आधारित है. इस संगठन की सभी महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं. ज़ाहिर है फिल्म का नाम भी इसी वजह से गुलाबी गैंग ही रखा गया है. निर्माता सुभाष सिंह ने रवीना को एक नहीं, एक साथ तीन फिल्मों के लिए इकट्ठे साइन कर लिया है. फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है. इस फिल्म में रवीना के अलावा तब्बू, शहाना गोस्वामी, संध्या मृदुल की भी प्रमुख भूमिका होगी. माना जा रहा है कि इस फिल्म में अभिनय रवीना के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. वह पहले भी सत्ता और शूल जैसी फिल्मों में बख़ूबी राजनीतिक भूमिकाएं कर चुकी हैं और ज़ोरदार अदाकारी के लिए लोगों की भरपूर प्रशंसा भी बटोर चुकी हैं. रवीना ने पहले जिस तरह से अपने अभिनय से पहले लोगों का दिल जीता था, क्या वह अब फिर से पहले वाला प्यार और पहले वाली सफलता हासिल कर पाएंगी? यह तो फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस फिल्म को गुलाबी रंग दे पाने में वह कितना कामयाब हो पाती हैं या फिर कामयाब हो भी पाती हैं या नहीं.

बिग बॉस को बाबा रामदेव की ना... ना

लगता है योगगुरु बाबा रामदेव अपनी वास्तविक ज़िंदगी से लोगों को वाक़िफ़ करवाने से बचना चाहते हैं. शायद इसी वजह से बिग बॉस-3 में प्रतियोगी बनने से उन्होंने मना कर दिया. इस शो के निर्माताओं ने बिग बॉस के घर का सदस्य बनने के लिए बाबा रामदेव से संपर्क साधा था. लेकिन समय की कमी का हवाला देकर उन्होंने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया. वैसे कई टीवी शो में नज़र आ चुके गुरु जी ने यह भी कहा कि मेरा काम सिर्फ़ योग का प्रचार-प्रसार करना है, न कि इस तरह के शो में प्रतियोगी बनना. लोग तमाम तरह के अनुमान लगा रहे हैं, पर वास्तविक कारण तो सिर्फ़ बाबा ही बता सकते हैं.

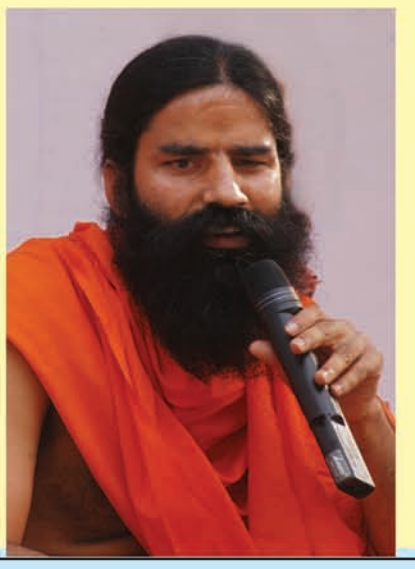

कारण चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि बाबा रामदेव योग के ही नहीं, मीडिया के भी धुरंधर खिलाड़ी हैं और उन्हें झांसा देना कोई आसान बात नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

तो अब सुष्मिता करेंगी डिस्टर्ब

पिछले कुछ दिनों से सुष्मिता सेन के बारे में कोई न कोई नई बात लगातार सुनने को मिल रही है. अब सुनने में यह आया है कि सुष्मिता कभी भी छोटे पर्दे पर काम नहीं करेंगी. उनका साफ़ शब्दों में कहना है कि भले ही उनके पास काम हो या न हो, पर वह अब कभी भी छोटे पर्दे पर हरगिज़ नज़र नहीं आएंगी. सुष्मिता काफी समय के बाद फिल्मों में दोबारा नज़र आ रही हैं. सुष्मिता सेन के प्रशंसक उन्हें एक बार फिर से पर्दे पर जलवा बिखेरते देख सकते हैं. हाल ही में रिलीज़ हो चुकी डेविड धवन की हास्य फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब और किंग ख़ान के साथ आने वाली फिल्म दुल्हा मिल गया में हमें उनकी अदाकारी देखने को मिलेगी.

सुष्मिता का कहना है कि फिल्म उनके लिए सब कुछ नहीं हैं. हो यह उनके जीवन का अहम हिस्सा ज़रूर है. निजी ज़िंदगी उनके लिए कहीं अधिक मायने रखती है. कोई भी फिल्म वह तभी साइन करती हैं जब उन्हें अपनी भूमिका दमदार लगती है. दर्शकों को हंसाने के लिए वह काफी समय से बेक़रार थी. डू नॉट डिस्टर्ब में उनकी यह बेक़रारी पूरी हुई है. इसमें उन्हें अपने पसंदीदा अभिनेता गोविंदा का भरपूर साथ जो मिला है. सुष्मिता कहती हैं कि सेट्स पर अगर गोविंदा साथ हों तो शूटिंग कब ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता. उनके रहते पूरा माहौल हंसी खेल का बन जाता है. वैसे यह तो फिल्म देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि उन्होंने दर्शकों को वाकई में डिस्टर्ब कर दिया है.

आने वाली फिल्में

इस दीवाली पर बड़े मेगा बजट की कई फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं. देखते हैं कौन-सी फिल्म दीवाली पर धमाका मचाने में कामयाब होती है.

मिस्टर एंड मिसेज खन्ना

प्रेम आर सोनी निर्देशित फिल्म मि. एंड मिसेस खन्ना में मुख्य भूमिका निभाई है करीना कपूर, सलमान ख़ान और सोहेल ख़ान ने. प्रीति ज़िंटा फिल्म में एक आइटम डांस करेंगी. फिल्म में संगीत है साजिद वाजिद का. फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई है. समीर (सलमान) पत्नी रैना (करीना) के साथ ख़ुशी से रहता है, तभी अचानक आकाश (सोहेल) की एंट्री होती है, जो कि एक बेहद दिलफेंक इंसान है. वह करीना को चाहने लगता है. उसकी अचानक एंट्री से फिल्म की कहानी नया मोड़ लेती है. फिल्म में बप्पी लहिरी भी एक विशेष भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि असली में आख़िर कौन मिस्टर एंड मिसेज है.

ब्लू

ब्लू फिल्म एक अरब से भी ज़्यादा बजट में बनी है. फिल्म में अभिनेता हैं संजय दत्त, ज़ायद खान और अक्षय कुमार और अभिनेत्री हैं लारा दत्ता. कैटरीना केवल एक कैमियो करते हुए दिखाई देंगी. फिल्म में हॉलीवुड की पॉप सिंगर काइली मिनॉग ने भी गाना गाया है. निर्देशक है एंथनी डिसूजा. फिल्म में संगीत दिया है ए आर रहमान ने. तूफ़ान का अहसास दिलाने वाली अंडरवाटर एक्शन फिल्म पहली बार बॉलीवुड के दर्शकों को देखने को मिलेगी. इस फिल्म में सागर (संजय दत्त) अपने भाई सैम (ज़ायद) और पत्नी मोना (लारा दत्ता) के साथ बहामा के समुद्र में 200 फीट की गहराई में दबे खजाने की खोज में निकलते हैं. वहीं उनकी मुलाक़ात आरव (अक्षय कुमार) से होती है. शातिर क़िस्म का आरव भी इसी खजाने की तलाश में आता है. यह खजाना कौन हासिल करता है यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा.

ऑल द बेस्ट

इस फिल्म के निर्माता अजय देवगन और निर्देशक रोहित शेट्टी हैं. संगीत प्रीतम का है. फिल्म के कलाकार अजय देवगन, बिपाशा बसु, फरदीन ख़ान, संजय दत्त, मुग्धा गोडसे, और जॉनी लीवर हैं. गोलमाल और गोलमाल रिटर्न्स जैसी सफल फिल्मों की जोड़ी (अजय देवगन-रोहित शेट्टी) इस दीवाली पर दोबारा ऑल द बेस्ट में देखने को मिल जाएगी. वीर (फरदीन) वैसे तो रॉकस्टार होने का दावा करता है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी रहती है. उसका सौतेला भाई धर्म (संजय दत्त) बाहर रहता है. वीर अपने भाई से पैसे लेने की ताक में रहता है. विद्या (मुग्धा) को वीर बेहद चाहता है. फिल्म में प्रेम चोपड़ा (अजय देवगन) अपनी पत्नी जाह्नवी (बिपाशा बसु) के साथ एक जिम को चलाता है. वीर धर्म की नज़रों में शादीशुदा है. मुश्किल तब शुरू होती है, जब एक दिन धर्म वीर से मिलने आता है. झूठ को छिपाने के लिए प्रेम और वीर मिलकर कई झूठी कहानियां गढ़ते हैं. कई हास्य परिस्थितियां पैदा होती हैं. क्या होता है बाद में वीर का झूठ पकड़ा जाता है या नहीं यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा.